हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

11 मार्च, 1991

खण्ड 1 अंक 7

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 11 मार्च, 1991

पृश्ठ संख्या

ताराकित प्र ान एवम उत्तर	(7)1
नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे हुए तारांकित प्र न का लिखित उत्तर	(7)23
अतारांकित प्र ान एवम उत्तर	(7)25

विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(7)34
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–	
जिला हिसार में गन्ने की खरीद	(7)37
वक्तव्य–	
सहकारित मंत्री द्वारा उपरोक्त	
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी	(7)39
वर्श 1991–92 के बजट पर सामान्य चर्चा	(7)41
अध्यक्ष द्वारा रूलिंग–	
अधिकारी दीर्धा में सी0 आई0 डी0 अधिकारी के बैठने	
सम्बन्धि श्री होरा नन्द आर्य के प्वायंट आफ आर्डर पर	(7)71
वर्श 1991–91 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)73
अनैक चर	(7)96

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 11 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1 चण्डीगढ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवम उतर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Construction of Electricity Stations/Sub-Stations

1226. Shir Hira Nand Arya: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state-

(a) the number of electricity stations/sub-stations for which foundation stones were laid in the State during the last two years togetherwith the details of such stations which have been completed or are under construction;

(b) the time by which the stations which are under con-struction as referred to in part (a) above are likely to be completed; and

(c) the details of stations/sub-statons which are over-loaded at present togetherwith the steps taken or proposed to be taken to remove the over-loading in these stations?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह):

(क) पिछले 2 वर्शो के दौरान 12 नं0 उपकेन्द्रों का ि ालान्यासह किया गया जिनमें से छः उपकेन्द्र निर्माणाधीन है। अन्य उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए टेण्डर आमन्त्रित किये जा चुके हे।

(ख) 8 नं0 उपकेन्द्रों को वर्श 1991–92 तक तथा 4 नं0 उपकेन्द्रो को वर्श 1992–93 तक पूरा किया जाना सम्भावित है।

(ग) वर्तमान समय में 49 नं0 उप–केन्द्र अतिभार है, इनकी पहचान कर ली गई है। इन उपकेन्द्रो के ओवलोडिग (अतिभार) को करने के लिए निम्नलिखत कदम उठाये गये है या उठाये जाने प्रस्तावित है:–

(1) अतिभार वाले उपकेन्द्रों का क्षमता मे वृद्धि करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त नये उपकेन्द्र भी निर्मित किये जाएगे।

(2) वोल्टेज स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न उपकेन्द्रों पर एच0 टी0 कैपोसीटर प्रतिस्थपित किये जा रहे है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जो संख्या पिछले दो वर्शो के दौरान 12 सब स्टे ानों के ि ालान्यास रखने के बारे में बताई है उनके बारे मै इनसे जानना

चाहूंगा कि इन में से कितनों पर काम चल रहा है और जिन के टेण्डर काल किए गए है, उन के नाम क्या क्या है? मेरे पूछने का मकसद यह है कि ये कहां कहा पर बनाये जा रहे है या बनाए जाएंगे? इसके अलावा मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक सब स्टे ान पहाड़ी नेकीपुर का भी ि ालान्यास किया गया था और इसे मार्च, 1991 तक पूरा करने का आ वासन भी दिया गया था। इसी तरह से लोहारू सब स्टे ान की कैपेसिटी भी बढ़ाने के लिए कहा गया था और इसे 91–92 तक कम्पलीट करने की बात कही थीं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो घोशण उस समय की गई थी क्या वह इन 12 सब स्टे ानों में भाामिल है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब पिछले 2 वर्शो के दौरान जो जी नीव पत्थर रखे गए हैं मै उनके नाम बता देता हूं। इनके अलावा जिन 2 सब स्टे ानों के बारे में इन्होंने पूछा है उनकी भी स्थिति कलियर कर देता हूं कि पहाड़ी नेकीपुर की फाईने ि ायल और एडिमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दी जा चुकी है और यह सब स्टे ान 1992–93 तक पूरा हो जाएगा। जहां तक लोहारू सब स्टे ान की कैपेसिटी बढ़ाने की बात है, उनका नीव पत्थर 9–7–90 को उस समय के मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता जी द्वारा रखा गया था। इस बारे मैं स्थिति स्पश्ट कर दूं कि जिस समय इस का नीव पत्थर रखा गया था उस समय इसकी फाई ि ायल और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल नहीं ली गई थी। अब जब

इसका सवाल आया तो उसके बारे मैने बोर्ड को कहा कि इसकी फाईनेि ायल ओर एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रूवल कलियर कर दी जाये। इसलिए अब इसको ये दोनों एप्रूवल जल्दी ही कलियर हो जाएंगी और इसे भी 1992–93 तक पूरा कर लेगे। स्पीकर साहब, इन्होने पूछा था कि 12 सब स्टे ानों पर कहां कहां पर काम हो रहा है? जहां पर काम हो रहा है उन के नाम हैं भााहबाद, सागा, रानिया, लोहारू, ऐलनाबाद, दड़वी, पहाड़ी नेकीपुर नेहला, अग्रोहा, दनोदा कला, गन्दा और उकलाना।

श्री रतन लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भााहबाद में ढोला–माजरा में जो एक 232 के0 बी0 का सब स्टे ान बनाने का ि ालान्यास किया गया था, वह अब किस स्टेज पर है? इसके अलावा बबैन में भी 66 के0 बी0 सब स्टे ान के लिए भी हाउस में कहा गया था, उस बारे में भी जानना चाहता हूं कि उसकी भी अब क्या स्थिति है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, प्रोपर भााहबाद में तो काम चल रहा है लेकिन जो नए सब स्टे ान बन रहे है उसमें भााहबाद हल्के के ढोला–माजरा गांव का नाम मेरी लिस्ट पर नही है।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय को स्पश्ट कर दूं कि जब पहाड़ी नेकीपुर के सब–स्टे ान का ि ालान्यास किया गया था तो उस समय 31 मार्च 91 तक इसे

कम्पलीट करने की घोशण की गई थी और उस समय मै भी यहां पर मौजूद था और बिजली बोर्ड के चेयरमैनं भी वही पर हाजिर थे। अब मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या परे ाानी है कि इसे 31 मार्च, 1991 तक पूरा नही कर पर रहे? इसी तरह से लोहारू सब स्टे ान सब स्टे ान की भी कैपोसिटी बढ़ाने की आ वासन दिया गया था और इसे भी 92 तक कम्पलीट करने की घोशणा की गई थी।

प्रो0 सम्पत सिंह स्पीकर साहब, मै फिर दोबारा कलियर कर दूं कि जब पहाड़ी नेकीपुर और लोहरू सब स्टे ान बनाने को घोशणा की गई थी तो उस समय इन दोनों की फाईनेि ायल और एडीमिनिस्ट्रेटिव एप्रुवल नही थी। गवर्नमैंट का किसी काम को करने का बाकायदा एक प्रौसैस बना हुआ है और जो भी चीफ मिनिस्टर की घोशणा होती है उसका पूरा किया जाता है चाहे चीफ मिनिस्टर बी0 डी0 गुप्ता जी रहे हों या मास्टर जी हों। लोहारू सब स्टे ान को स्थिति भी कलियर कर देता हूं कि जिस समय इसका ि ालान्यास किया गया था उस समय का टैक्नीकल गलती रह गई थी और वह यह थी कि ि ालान्यास तो कर दिया गया लेकिन इसकी फाईनोंि ायल और एडिमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल नही ली गई थी। मैं खुद सिरसा में फ्लड ऐरियाज में दौरा करने के लिए गया हुआ था जब इसका नींव पत्थर रखने की बात फाईनल हुई। मुख्यमंत्री जी फ्डल ऐरिया के दौरे पर सिरसा गए थे और उन्होंने मुझे वहीं बताया कि कल नींव पत्थर रखा जाना

है। स्पीकर साहब, उस समय इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाईनैि ायल एप्रूवल नही ली गई थी। नींब पत्थर रखे जाने के समय मैं भी वहीं पर था। अध्यक्ष महोदय, मवनमैंट एक कांटीन्युअस प्रोसैस है और मुख्य मंत्री जी ने जो–जो नीवं पत्थर रखे है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल और फाईि ायल अप्रूवल ले कर 1992–93 तक इसको पूरा करने की कोि ा ा करेंगे।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरी कान्स्टीचुसेंसी टोहाना में धारसूल में 132 के0 वी0 के सब–स्टे ान को पूरा करने में क्या दिक्कत है? इसको पूरा करने के लिए वहां पर मैटीरियल भी पहुंचाया था लेकिन वह बाद में वहां से उठवा लिया गया है। यह मैटीरियल वहां से किस कारण उठाया गया है?

प्रो0 सम्पत सिंहः अग्रोहा में 33 के0 वी0 और धारसूल में 132 के0 वी0 के सबस्टे ांज बनाए जाने है। मैटीरियल उठाये जाने की आदत भाायद चौधरी बीरेन्द्र सिंह की रही होगी, मेरा ऐसी आदत नही है (हंसी)। धारसूल का काम भी जल्दी ही पूरा करवाया जाएगा।

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस समय प्रदे ा में कितनी मैगावाट बिजली पैदा हो रही है और

इसमें से कितनी हाईडल और कितनी थर्मल सिस्टम के द्वारा प्राप्त की जा रही है? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कटारिया साहब, आप कहा जा पहुचे। यह सप्लीमैटरी मेन सवाल से ताल्लुक नही रखता।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या बात ठीक है कि सतनाली, डिगाना, बहल और बाढड़ा आदि सब स्टे ान्ज ओवर लोडिड है और क्या ये इनकी स्थिति को सुधारने बारे विचार करेंगे?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, आर्य साहब ने जिन सब स्टे ान्ज के नाम बताए है वे ओवर लोडिड नही है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 49 सब–स्टे ाल्ज ओवर लोडिड बताए है। मै आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि उन ओवर लोडिड सब स्टे ान्ज में से फरीदाबाद में कितनी है और क्या हथीन का नाम भी उनमें है यदि है तो क्या इसके अपग्रेड होने की सम्भावना है?

प्रो0 सम्पत सिंहः फरीदाबाद जिले में कोई ऐसा सब स्टे ान नहीं है जो कि ओवर लोडिड हो।

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहब, करनाल में राम नगर में 50 हजार से ज्यादा की आबादी है और वहां पर एक 33

के0 वी0 का सब–स्टे ान लगाने बारे 2–3 बार वहां की स्थिति का जायजा भी लिय गया है। इसलिए, मै माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन सब–स्टे ान को बनाने के बारे में विचार करेगी?

प्रो0 सम्पत सिंहः इसको दोबारा देख लेंगे।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, पीछे भी बिजली के बारे में एक क्वै चन आया था और उसके उतर में पटिकुलरली टोहाना के बारे में था कि वहां पर 33 के0 वी0 और 11 के0 वी0 के दो सब–स्टे ान्ज मंजूर हुए है। नांगला और जगलौदा के बीच क पैडी का एरिया है जिस की वजह से वहां पर ओवर लोडिंग रहती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर ये सब–स्टे ान्ज भीघ्र बनाए जाएंगे?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जहां कही भी लोगों को तकलीफ है और लाईनें ओवर लोडिड है, वे यदि लिख कर दे दे तो इस बारे में जरूर विचार किया जाएगा।

तारंकित प्र न संख्या 1401

(यह प्र न पूछा नही गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री लछमन सिंह कम्बोज, सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Land with Forest Department

1415. Shri Durga Dutt Attrl: Will the Minister for Forest be pleased to state-

(a) the total area of land under afforestation in the State as at present;

(b) the total area of land on which Forest Department has its own control togetherwith the land of other departments which is under the control of Forest Department; and

(c) whether any land has been given to the Farmers after afforestation thereon during the year 1987, 1988, 1989 and 1990, if so the total acreage of land togetherwith yearwise expenditure incurred thereon?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह):

(क) 3,39,700 हैक्टेयर,

(ख) 1,67,909 हैक्टेयर,

(ग) हा, विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्श	भूमि जो वनरोपण के प चात् किसानों को दी गई (हैक्टेयर में)	खर्च (रूपयो में)
1987	1118.5	47,23,425
1988	2003	84,58,822

1889	2080	87,83,848
1990	122.5	51,73,175
कुल	6427	2,71,39,270

श्री दुर्गा दत अत्रीः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्श 1989 में 2080 भूमि पर प्राईवेट लोगों को जंगलात लगाकर दिये गये जबकि वर्श 1990 में 1225.5 भूमि पर ऐसा किया गया। मै उनसे यह जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि वर्श यह एरिया कम क्यों रह गया है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, कई बार जमीन भी अवेलेबल नही होती। लोग अपनी जमीन भी नही देते है। जिस तरह से डिमांड होती है, हम उसी हिसाब से काम करते रहते है।

श्री रामबिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि इस वर्श अरावली योजना के नाम से हरियाणा को केन्द्र ने कोई अनुदान दिया है ताकि अराबली पर्वत पर वृक्षारोपण किया जा सके? अगर दिया गया है तो उसके लिये क्या योजना बनाई गयी है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, सैंटर से पिछले साल के मुकाबले में डबल ग्रान्ट हमारे पास आयी है। पिछली बार हमारे

पास 3.82 करोड रूपये की ग्रान्ट आया थी और इस वर्श लिये 6. 78 करोड़ रूपये की ग्रान्ट आयी है और इस पर काम चल रहा है।

श्री दुर्गादत अत्रीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को यह याद होगा कि एक वायदा किसान के साथ किया गया था कि उसके खेत के साथ लगते हुए पेड़ो में उसको भी आधा हिस्सा दिया जायेगा। मै यह जानना चाहता हूं कि उसके लिये क्या तरीका अख्तियार किया जाता है? अब तक किसनों को इसका लाभ पहुंचा है और किसनों को यह हिस्सा पेड़ों की भाक्ल में दिया गया है और कितनों को रा ि ा की भाक्ल में दिया गया है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, हरियाणा सरकार बनने के साथ चौधरी देवी लाल जी ने जो एक वायदा किया था उस वायदे की लागू करने के लिए जो स्कीम बनाया गयी है, उसके तहत जितने भी दरख्त नहर पर ही, सड़क पर हो या रेलवे लाइनों के साथ–साथ हो, उन दरख्तों की खेत की तरफ की जो लाईन होती है, उसमें से आधा हिस्सा किसानों को दिया जाता है। जब तक 13,260 दरख्त सम्बन्धित किसानों की दिये जा चुके हैं। जैसे मेरे साथी ने पूछा पैसे का भुगतान भाुरू में जरूर किसान का किया गया था लेकिन बाद में यही पाया गया कि पैसे से किसान खु ा नही होता। उसके जेहन में यह भांका रहती हे कि भाायद यह दरख्त ज्यादा कीमत का था। अब हमने उन पर यह छोड़ दिया है कि आखिरो लाईन है, उसमें से आधे दरख्त चुन लें जब फारैस्ट डिपार्टमैंट यह कह दे कि यह मैच्योर हो गये है और यह

अब कोर्ट जा सकते है तो उन में से यह आंधे काट सकता है और इस तरह से हमने 13,260 दरख्त उनकी दिये है।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पानीपत ब्लाक में एक आसन कला गांव है, वहां पर 500 एकड़ जमीन फलदार पौधे लगाने के लिए दो गयी थी, क्या उस पर फलदार पौधे विभाग द्वारा लगवाये जायैंगे।

प्रो0 सम्पत सिंहः इडीविजुअल इस तरह का कोई केस है तो मैम्बर साहब मुझे लिखकर दे दे। हम इसकी एग्जामिन करवा लेगे कि क्या वहां फलदार पौधे लगाये जा सकते है या नही।

डा0 रधुबीर सिंहः स्पीकर साहब, पिछले बजट सै ान में मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि केन्द्र की तरफ से इस काम के लिए सैट्रल अस्लिटैस 130 करोड़ रूपये की हरियाणा को दो गयी है। क्यां मंत्री महोदय यह बतायेगे कि उस 130 करोड़ रूपये में से कितना पैसा केन्द्र ने हरियाणा सरकार को दिया है और जितना भी पैसा केन्द्र से आया है, वह किस–किस योजना के तहत खर्च किया गया है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, 130 करोड़ रूपय के बारे में मुझे मालूम नही है। फौरैस्ट डिपार्टमैट को सैन्टर से जो पैसा मिला है 6 करोड़ 78 लाख है लेकिन पिछले साल के मुकाबले में लगभग दुगना है।

श्रीमती कमला वर्माः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वृक्षारोपण के तहत किन वृक्षों को प्राथमिकता दी गई और वे कितने लगाए है? क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि सफेदा लगाने से कृशि योग्य भूमि पर बुरा असर पड़ता है और सरकार इसके लिए क्या कर रही है?

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में सफेदा के वृक्ष 15.7 प्रति ात कीकर 43.17 प्रति ात मसकट के 13.83 प्रति ात सुबाबूल के 0.67 प्रति ात सरैत के 1.00 प्रति ात भाी ाम 1.83 प्रति ात तथा दूसरे 4.3 प्रति ात लगाए है। स्पीकर साहब, पानी तथा सायन को देखकर पडे. लगाए जाते है। सफेदा की कीमतें नीचे न जाए इसको देखने के लिए फौरैस्ट कापोरि ान बनी हुई है। फौरैस्ट कापॅरि ान को गवर्नमैंट से बीस लाख रूपया भोयर मनी मिला है ताकि प्राईसिज डाउन न जाएं और मार्किट में जो प्राइसिज है उनको प्रोटैक्ट किया जा सके और अगर मार्किट में सफेदा की प्राइस नीचे जाए तो उनको खरीदा जा सके।

कामरेट हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, सफेदा की वजह से अम्बाला, करनाल और कुरूक्षेत्र में बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है और वहां पर पानी का लैवल काफी नीचे चला गया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि फौरैस्ट डिपार्टमैंट इस पर रिसर्च कर रहा है कि सफेदे के वृक्ष लगाने से कितना नुक्सान होता है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, रिसर्च तो बाकायदा होती रहती है। अगर रिसर्च न ही तो फिर एक ही प्रकार के दरख्त लगें। ज्यौं–ज्यों रिसर्च होती है वहां पर उसी तरह के दरख्त लगे। ज्यों–ज्यों रिसर्च होती है वहां पर उसी तरह के दरख्त लगाए जाते है।

श्री कैला ा चन्द भार्माः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अरावली योजना के अन्तर्गत पिछले वर्श कौन–कौन से इलाका को चुना गया था और उनमें कितने वृक्ष लगाए गए थे और आने वाले साल में कौन कौन से इलाके चुने गए है और कितने दरख्त लगाए जाएगें?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, अरावली योजना के अन्तर्गत टोटल 49 करोड़ रूपये खर्च होने है और यह योजना बात वर्श में पूरी होगी। इस वर्श तीन करोड़ रूपय खर्च होगे और अगले वर्श 5.80 करोड. रूपये खर्च किये जाएंगे। गुडंगाव, फरीदाबाद, भिवानी तथा महेन्द्रगढ़ को इस योजना के लिए चुना गया है।

श्री किरपा राय पुनियाः स्पीकर साहब, यूकलिप्टस के लिए बहुत बड़ा कम्पैन चलाया गया था लेकिन आज किसान महसूस कर रहा है कि यूकलिप्टस का ठीक दाम उसको नही मिला। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह गल्त प्वानिंग क्यों रही?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, हमारे यहां दिक्कत है जो कोई किसी प्रकार का भ्रुरू में एक दरख्त लगा ले लोग उसी की तड़ते है और इसलिए ये दरख्त ज्यदा लग। उसे बाद गवर्नमैंट उनके प्रोटैक ान पर आई एक कापरेरि ान बनाई गई ताकि वह कापेंरि ान उनके दरख्तों को खरीद सके और किसान को दाम ठीक मिल सके।

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, हिमाचल प्रदे ा मैं लोगों को रोजगार देने के लिए पेड़ लगाकर रोजगार देने की स्कीम भ्रुरू की गई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में भी बारानी, बन्जर और अनकल्टीवेटिड लैड पर पेड़ लगाकर बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की कोई स्कीम भ्रुरू की जाएगी?

Mr. Speaker: This is no supplementry. Moreover he is not the Revenue Minisster.

श्री कैला ा चन्द भार्माः अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने बताया है कि अरावली योजना सात वर्श में पूरी होगी। क्यों मंत्री महोदय बताने को कृपा करेंगे कि अराबली योजना के तहत कितने पेड़ पिछले वर्श लगाए और कितने पड़े पिछले वर्श लगाए और कितने पेड़ अगलेह वर्श लगाए जांएगे?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैने टोटल अमाउन्ट बताया है, पेडों की सख्यां मेरे पास नही है?

श्री किरपा राम पुनियां: मंत्री महोदय ने बताया है कि लोगों ने ज्यादा सफेदे के पेड़ लग दिये इसीलिए किसानों की रेमूनरेटिव प्राईस नही मिली। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करगे कि आज दिन भी स्थिति उसी तरह की है जैसे कि पहले लोग अन्धाधुध सफेदे के पेड़ लगा रहे थे?

प्रो0 सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जहां पर पानी ज्यादा मात्रा में होग वहां पर सरकार सफेदे के पड़े लगवाएगी और जहां पानी की कमी होती है वहां पर सरकार इनको लगाने में डिसकरेज करती है।

तारंकित प्र न संख्या 1372

यह प्र न पूछा नही गया, क्योंकि इस समय, माननीय सदस्य सर्वश्री बलवीर सिंह चौधरी व अजय सिंह यादव, सदन, में उपस्थित नही थे।

General Hospital, Faridabad

1994. Shri Yogesh Chand Shrama: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new bulling of General Hospital, Faridabad; and

(b) if so, the time by which the afore-said building is likely to be constructed?

Health Minister (Shri Om Parkash Bhardwai):

(a) Yes.

(b) Within two years subject to the availability of funds.

श्री योग ा चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, 1947 में जब जनरल हस्पताल, फरीदाबाद बना था तो उस वक्त फरीदाबाद की जनसंख्या 30 हजार के लगभग थी और आज वहां की जनसख्यां लगभग 7 लाख है और आज वह हस्पताल वहां के लोगों को जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। लोग वहां से दिल्ली में चिकित्सा सुविधाओं के लिये आते है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज दिल्ली तक पहुंच ही नही पाता और रास्ते में हो दम तोड़ जाता है। इसलिए मेरा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि क्या सरकार प्रायरिटी बैसिज पर फरीदाबाद के हस्पताल की बिल्डिंग को दोबारा बनाने का विचार रखती है ताकि वहां के लोगों की जरूरत को वही पूरा किया जा सके? अगर सरकार के ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीनह है तो सरकार बताए कि कब तक नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी?

श्री ओम प्रका ा भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बी0 के0 हस्पताल फरीदाबाद की जानकारी चाही लेकिन मैं यहां हाउस में बताना चाहता हूं कि वह हस्पाल चालू है। परन्तु यहां नए हस्पाल की ईमारत बनाने की बात ही रही है औरह यह सब फण्डज पर डिपैन्ड करता है।

श्री योगे ा चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, पिछले फाईले को मंत्री महेादय ने यह कहा था कि वहां पर काम चालू है। वहां पर सी0 एम0 औ0 का क्वार्टर भी बन गया है और बाऊंडरी बाल भी बनाकर तैयार हो गयी है। मेरा सवाल करने का मतलब यह था कि उस हस्पताल की जो बिल्डिग है, वह पूरी तरह से खंडरात में तबदील हो चुकी है और उसी वक्त भी वहां पर कोई न कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिये आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से यह जानना हूं कि कब तक नई बिल्डिंग के बनाने के लिये फण्डज ऐलोकेट कर दिये जाएंगे?

श्री ओम प्रका ा भारद्वाज: स्पीकर साहब इस हस्पताल मैं अब तक 4 लाख 31 हजार रूपये खर्च हो चुके है और इस साल 25 रूपयें और इसके लिये अलौट किये गये है।

श्री उदयभान: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि जनरल हस्पताल की बिल्डिंग कब स्वीकृत हुई थी, इसके बनाने के लिये कितनाह समय नि चत किया गया है और कितना इसके लिये फण्डल ऐलोकेटिड था। क्या सरकार इस बिल्डिंग को नि चत समय के अन्दर बनाने का प्रयास करेंगी?

श्री ओम प्रका ा भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, इस बिल्डिंग की ऐडमिनिस्ट्रेटिक्ऐप्रूवल 1982 में हुई थी और इस पर ऐस्टीमेंटिड कास्ट 3 करोड़ 8 लाख 67 हजार की थी।

डा0 बुज मोहना गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, आज सब जगहों पर आवादी बढ़ रही है और मरीज भी बढ़ रहे हैं। पहले जो हस्पताल होथे थे आबादी के हिसाब से बनाये गये थे और मु कल से 30–30 बैडज के हस्पताल होते थे। क्या लोगों की मांग को देखते हुए और आबादी का ध्यान रखते हुए सरकार इन छोटे 30–30 बैडज के हस्पतालों को बड़ा करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्षः डा0 साहब मेन प्र न केवल फरीदाबाद से सम्बन्धित है। आप कृपया बैठिय।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय, ने 1982 इस हस्पताल को प्र ाासनिक स्वीकृति देने की बात कही। मै उनसे जानना चाहता हूं कि क्या कही और जगहों पर भी ऐसी प्र ाासनिक स्वीकृतियां सरकार की और से दी गयी है? प्र ासनिक स्वीकृति होते हुए हस्पताल न बनने के क्या कारण है? फरीदाबाद के हस्पताल को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि कोई मिट्टी की दीवार हो और वह बिल्डिंग वैसे भी अनसेफ डिक्लेयर की जा चुकी है। क्या इन सभी बातों को देखने हुए सरकार भीघ्र ही नई बिल्डिंग बनाने का विचार रखती है?

श्री ओम प्रका ा भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैने पहले ही बताया कि इस काम के लिये 25 लाख रूपये की ऐलोके ान हो चुकी है और काम चालू है। इसके साथ–साथ मैं यह भी

हाउस को बताया चाहता हूं कि हमारे आन गोंइग वर्कस 1218.15 लाख रूपये के ऐस्टीमेंटिड है और इन सबका पूरा करने के लिए 8 करोड़ 78 लाख 2 हजार रूपये की आव यकता है। स्पीकर साहब, अगले साल के लिए एक करोड़ रूपये का बजट इस हस्पताल के लिये ऐलीकेट किया गया है।

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, मैने इनसे यह पूछा था कि इस हस्पताल के कब तक बन जाने की योजना थी? इसके अलावा जो 8 करोड़ 78 लाख रूपय का ऐस्टीमेट बना इसमें से कितना पैसा खर्च हो चुका है और कितने परसैंट काम चुका है।

श्री ओम प्रका ा भारद्वाजः स्पीकर साहब, यह तो मैं कह नहीं सकता इसकी बनाने की डेट कब तक की फिक्स हुई थी क्योंकि यह चौधरी भजन लाल जी के वक्त की बात है। इस बारे में भाई महेन्द्र प्रताप जी रो ानी डाल देंगे।

श्री महेंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय जिस रफ्तार से ये चल रहे है उसके हिसाब से इसे हमें ही पूरा करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि इसके ऊपर आठ करोड़ रूपय से ज्यादा खर्चा होगा और इसमें से इस साल 25 लाख रूपया रखा गया है। तो क्या यह पैसा रैजीडैि ायल बिल्डिंग के लिए है या हस्पताल के वार्डज वगैरह बनाने के लिए रखा गया है जोकि ज्यादा जरूरी है?

श्री ओम प्रका ा भारद्वाजः सर, यह पैसा रैजीडैस के लिए रखा गया है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मै यह जानना चाहता हूं कि 1982 के बाद डिस्ट्रिक्स लैवल के जितने और हस्पतालों की एप्रूवल हुई वे जब पूरे हो चुके है तो इसको अब तक पूरा क्यों नही किया गया?

श्री ओम प्रका ा भारद्वाजः स्पीकर साहब, यह फरीदाबाद के हस्पताल की कंस्ट्रक ान के बारे में सवाल है और उसके बारे में मैने बता दिया है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मंत्री जी ने बी पार्ट के जवाब में कहा– Within two years subject to thee avatiability of funds यह प्रपोजल कब बनी और दो साल में अगर फंडेज अवेलेबल न हुए तो फिर आगे इसके बारे में से क्या कहूंगे? या तो ये कह देते कि यह बनेगा subject to the availability of funds दो साल की मियाद देने की क्या जरूरत है। क्या इसको फंडज मिलने की कोई संभावना है?

श्री ओम प्रका ा भारद्वाजः स्पीकर साहब, वीरेन्द्र सिंह जी तो बहुत अच्छी तरह से जानते है कि आ ा के साथ ही सब कुछ चलता रहता है। इसलिए इनको दो साल तो इंतजार करना चाहिए।

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कभी हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन के महत्व को देखते हुए, जरूरत को देखते हुए वहां पांच सौ बिस्तरों का हस्पताल बनाने की घोशणा की थी।

श्री ओम प्रका ा भारद्वाजः स्पीकर साहब, मेरे नोटिस में तो यह नही है लेकिन गुप्त जो कि जानकारी के लिए मै इतना कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद में एक तो इ0 एस0 आई0 का दो सौ बिस्तरों का हस्पताल है और दूसरा बी0 के0 हस्पताल भी है।

Minor from Gonchhi Drain

1378. Shri Unal Bhan: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to dig-out a minor from Gonchhi drain at Village Banchari irrgate the barren land of Village Sodath, Boraka, Dadka, Neemka, Garhi patti Hodel, Bhuwana and Hodal; and

(b) if so the time by which the afore-said minor is likely to be dug-out

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह):

(क) नही।

(ख) प्र न ही नही उठता।

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, ये 8–10 गांव है जिनके लिए सिचांई के पानी की व्यवस्था नही है। इन गांवो का जमीन के नीचे का भी खारी पानी है। मे आपके माध्यम से मंत्री जी ने जानना चाहूंगा कि क्या इन गांवों को सिचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार कोई विार करेंगी?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, एक बार 1972–73 में सरकार ने एक स्कीम बनाई थी कि संधि योजक ड्रैन बनाई जाएगी उससे सोध के पास जो पानी इक्ट्ठा होगा उस पानी को गोछी मेन ड्रेन में डाल कर वहां एक लिफ्ट माइनर बना कर इन गांवो तक पानी पहुचाया जाएगा। लेकिन 1977–78 में उजीना इाइव र्न ड्रेन बन गई और वह पानी उजीना डाईव र्न ड्रेन में चला जाता है इसलिए गोछी ड्रेन में पानी न होने के कारण वहां में माइनर नही निकाली जा सकती।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र को सिचांई के लिए पानी उपलब्ध कराने के बारे में सरकार क्या योजना बना रही है? क्या सरकार उस क्षेत्र को सिचांई के पानी देने की कोई व्यवस्था करेगी? अगर करेगी, तो सरकार के सम्मुख क्या प्रस्तावित योजना है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, यह सरकार उस क्षेत्र को सिचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था जरूर

करेगी। अगर माननीय सदस्य के पास इस बारे में कोई सुझाव है तो वह हमें बताएं हम उस पर गौर करेंगें?

श्री उदयभानः स्पीकर साहब, माननीय मंत्री जी कह रहे है कि गोछी ड्रेन में पानी नही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूगा कि क्या मंत्री जी स्वयं वहां आ कर गोछी ड्रेन को देख सकते है? मै भी इनके साथ वहां पर मौजूद हुंगा। अगर माननीय मंत्री जी स्वयं देखे तो इनकी मालूम ही जाएगा कि गोछी ड्रेन में पानी उपलब्ध है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य मुझे इनविटे ान देगे तो मै वहां जरूर जाऊगा। माननीय सदस्य मुझे इनवाइट करें और मै वहां न जाऊ यह हो ही नही सकता।

श्री सरदूल सिंहः स्पीकर साहब, मेरे हल्के में ड्रेनों की बहुत बुरी हालत है। उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? मेरे हल्के में आडवा और गंगोली ड्रेनों से लोगों को बहुत पर ाानी है। मेरे हल्के में जो ड्रेन बनी हुई है उनके ऊपर से पानी का निकास नही हो रहा है जिससे किसान बहुत परे ाान है। मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में जिन ड्रेनो की बहुत बुरी हालत है उनके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है?

Mr. Speaker: This is no supplementry. Please take your seat.

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, गुडगांव और फरीदाबाद के क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के बारे में सरकार की क्या प्रस्तवित योजना है क्योंकि मेवात क्षेत्र को गुड़गांव कैनात और आगरा कैनाल से पानी नही मिल पा रहा है। यदि उस क्षेत्र को सिचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्तावित योजना है तो वह किस स्तर पर है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने मेवात और दूसरे क्षेत्र का जिकर छेड़ दिया। मै इन्हें बताना चाहूंगा कि हमे ज्यों ज्यों पानी उपलब्ध होता है त्यों–त्यों हम माइनर या चैनल बनाने की कोि ा ा करते है।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेन सवाल के भाग (ख) का जबाव दिया है प्र न ही नही उठता। कुछ दिन पहले मंत्री जी ने सभी विधायकों से एक पत्र द्वारा यह पूछा था कि आपके हल्कों में कौन–कौन सी माइनर का काम बाकी है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या विधायकों द्वारा दिए गए पत्रों के बारे में कोई कार्यवाही हुई है क्योंकि श्री उदय भान जी की चिटठी का जवाब तो इन्होंने दे दिया है कि प्र न ही नही उठता?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैने उदय भान जी की चिट्ठी का जवाब नही दिया है। यह तो इन्होंने कोई 1972–73

की स्कीम थी उसके बारे में पूछा था उसका जवाब मैनें दिया है। जहा तक मैम्बर साहेबान ने अपने हल्के माइनर्ज के बारे में चिट्ठियां लिखी है उनके बारे में मै बताना चाहूंगा कि सरकार इस सालह के अन्दर–अन्दर 150 माइनर्ज पर काम भुरू करेंगी।

Taking over of Adarsh Kanya Uch Vidyalya, Bawwa

1370. Rao Ram Narain: Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whetther the Government has received any applecation for taking over the Adarsh Kanya Uch Vidyalya, Bawwa Teh. Kosli, District Rewari; and

(b) if so the action taken thereon?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह):

(क) जी, हा।

(ख) मामला सरकार के विचारधीन है।

राव राम नारायण: अध्यक्ष महोदय, मै इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आद र्ा कन्या उच्चविद्यालय, बब्वा, तहसील कोसली, जिला रिवाड़ी को टेक औवर करने के लिए आज से डेढ़ साल पहले जब मंत्री जी रिवाड़ी में त ारीफ लेकर के गए थे उस समय इनको एक दरख्वास्त दी गई थी। मै जानना हूं इसको टेक ओवर करने की क्यो देरी हो रही है?

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये आबकारी एवं कराधान मंत्री थे तो उस समय इन्होंने 30.6.1989 को एक लैटर लिखा था। इनके लैटर लिखने के बाद हमने 18.8.1989 को सबंधित डी0 ई0 ओ0 को रिपोर्ट भेजने के लिए लिखा और उन्होंने 5.3.1990 का अपनी रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट में कुछ कमी थी इसलिए 27.2.1991 को फिर संबंधित डी0 ई0 ओ0 को लिखा गया है लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नही आई है।

राव राम नारायणः अध्यक्ष महोदय मै जानता चाहूंगा कि इस स्कूल की कब तक टेक ओवर कर लेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जब सारी कार्यवाही पूरी हो जाएगी तब इसको कान्सीडर कर लेगे।

श्री कै ाला चन्दा भार्माः स्पीकर साहब, मेरे हल्के में एक कालेज है.....(ाोर)

Mr. Speaker: This is not the way. I wan't permit tike this. Please take your seat.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किसी स्कूल को टेक ओवर करने का क्या काईटेरिया है? दूसरा मेरा सवाल यह कि ऐसे और स्कूल अपग्रैड करने के लिए कितनी ऐप्लीके ाज आई है? जो ऐप्लीके ाज आई

है क्या उनमें श्री कैलाश चन्द भार्मा जी जिसके बारे में पूछने लगे थे वह भी कवर हो जाता है?

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, किसी स्कूल या कालेज को टेक ओवर करने के लिए सरकार की कुछ कंडी ाज होती है और उन्हीं कंडी ांज के तहत स्कूल टेक ओवर किये जाते है। जैसे किसी स्कूल को किसी वि ोश समुदाय के लोग चला रहे हो, कोई स्कूल बाढ़ ग्रस्त एरिया में हो, दलदल एरिया में ही या किसी स्कूल को कोई स्कूल बाढ़ ग्रस्त एरिया में हो, दलदल एरिया में ही या किसी स्कूल को कोई पंचायत चला रही हो। इसके अलावा, और कुछ भार्ते है जिनको पूरा किया जाना होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कन्डी ांज सरकार की होती है उनको जो स्कूल पूरा करता है उसे ही टेक ओवर किया जाता है।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, ि ाक्षा मंत्री जी ने लिखित जवाब में आद र्ा कन्या उच्च विद्यालय बब्वा को टेक औवर करने के बारे में बताया है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। राव साहब ने स्पेसिफिक पूछा है कि इस स्कूल को कब तक टेक औवर कर लेंगे? इन्होंने विचारधीन वाली जो बात कही है यह कब तक विचारधीन रहेगी और इसे कब तक पूरा किया जाना है क्योंकि जब इनके पास डी0 ई0 ओ0 से रिपोर्ट आ गई है तो फिर इसको टेक ओवर करने में क्यों कठिनाई हो रही है?

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह नही कहा कि रिपोर्ट आ गई है बल्कि उन्होंने यह बताना है कि डी0 ई0 ओ0 से जो रिपोर्ट मानी गई थी वह कम्पलीट नही थी इसलिए अब दुबारा रिवाड़ी डी0 ई0 ओ0 की लिखा गया है कि वह रिपोर्ट भेजे। उनकी रिपोर्ट अभी तक नही है।

Upgadation of Primary Health Center, Aurangabad

1428. Shri Bhagwan Sahai Rawat: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal undeer consideration of the Government to uprade the Primary Health Centre Aurangabad to a Community Health Center; and

(b) if so whether there is also any proposal under const deration of the Government to construct the building of Primary Health Center, at Nangal Jat of district Faridabad in Hathin Constituency; and

(c) if the reply to rarts (a) and (b) be in the affirmative, the time by which the afore proposals are likely to be materalized?

Health Minister (Shri Om Parkash Bhardwaj) :

(a) No.

(b) No.

(c) Question does not arise.

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष मैं अपने योग्तम मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ओरंगाबाद का कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर कब स्थापित हुआ था और इसको अपग्रेड करने का मामला कब से विचाराधीन है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि नांगल जाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब खोला गया था और इसकी ईमारत कब तक बन कर तैयार हो जाएगी?

श्री ओम प्रका ा भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई राश्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अनुसार प्रत्येक 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए एक रामु दायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसमें 30 बिस्तर तथा भाल्य चिकित्सा, फिजि ियन, स्त्रीरोग, बालरोग, एव दंत चिकित्सा वि ोशज्ञ होगे, स्थापित किए जाएंगे। मै माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि इन 4 पी0 एच0 सीज0 में से होडल को पहले ही अपग्रेड किया जा चुका है।

श्री योगे ा चन्द भार्माः स्पीकर साहब, भाग पुन खादर में अस्पताल की बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन वहां पर कोई डाक्टर की सुविधा नही है, न ही वहां पर कोई नर्स की ही सुविधा है और न कोई दूसरा स्टाफ हैं। केवल वहां पर एक चपरासी रहता है। मैने का एक बार दौरा किया था तो वहां प दारू की बोतल रखी हुई थी। मै माननीय मंत्री जी से यह जानना

चाहूंगा कि क्या वे वहां पर कभी छापा मारेगे और वहां डाक्टर की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे?

श्री ओम प्रका ा भारद्वाजः स्पीकर साहब, इनका सवाल मेरी समझ में नही आया है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध कंरूगा कि वह अपना प्र न रिपोट कर दे।

श्री अध्यक्षः ये कह रहे है कि इन्होने वहा पर दारू की बोतल देखी थी।

श्री ओम प्रका ा भारद्वाजः स्पीकर सर, हमारी जानकारी में तो ऐसी बात नही है फिर भी अगर ये लिख कर दे दें तो हम इन्क्वायरी करवा लेंगे।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या कभी इनके मूख श्री से हां भाब्द निकलेगा? जब भी कोई प्र न इनसे पूछा जाता है तो इनका जवाब नही में होता है। क्या ये कभी हां भी कहेंगे?

श्री ओम प्रका ा भारद्वाजः स्पीकर साहब, हमें जो भी जानकारी यहां पर देते है वह सच्चाई पर आधारित होती है। यह पुरानी कांग्रेसी सरकार की तरह के आ वासन चाहते हों तो मुझे अफसोस है क्योंकि हम झुठे वायदे नही करते। ,

श्री भगवान साहय रावतः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे हाउस में तैयारी करके आया करें।

श्री ओम प्रका ा भारद्वाजः स्पीकर साहब, हम पूरी तैयारी करके हाऊस में आते है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्राईमरी हैल्थ सैटर, नांगल जाट को सी0 एच0 सी0 में कब तक अपग्रेड कर दिया जाएंगा?

श्री ओम प्रका ा भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, वहां पर प्राईमरी हैल्थ सैटर पंचायत कि बिल्डिंग में चल रहा है। इसका सवाल यह है कि प्राईपरी हैल्थ सैंटर का अपग्रेड क्यों नही किया जा रहा? अध्यक्ष महोदय, मै यह बताना चाहूंगा कि अपग्रे ान के बारे में सरकार को जो नीति है यह उसको कवर नही करता।

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जो से यह जानना चाहता हूं कि इन्हें रावत जी से क्या नाराजगी है, क्या कारण है कि ये इनके पूछे हुए सवाल का जवाब नही दे रहे है। इस प्राइमरी हैल्थ सैंटर की अपग्रे ान क्यों नही हो रही, सरकार को कौन सी नीति है जिस के अन्दर यह कबर नही होता, क्या ये इनको बताने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रका ा भारद्वाजः गुप्ता जी, रावत साहब प्राईमरी हैल्थ सैंटर की अपग्रैडे ान के बारे में बात कर रहे है। अध्यक्ष महोदय, अब तक हरियाणा में 41 सी0 एच0 सीज0 चल रही है और इस साल 17 और सी0 एच0 सीज0 को अपग्रेड किया जाना विचारधीन है। जहां तक बिल्डिंगों का ताल्लुक है, हमारे पास 47 ओन गोईग वर्क्स है। स्पीकर साहब, इन 47 बिल्डिंगों का कम्पलीट करने के लिए 3 करोड़ 50 लाख 38 हजार रूपये की आव यकता है।

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से करनाल के दानवीर कर्ण अस्पताल के बारे में एक बात जानना चाहता हूं।

Mr. Speaker: Please take your seat. It is not possible for the Minister to give reply to such questions off hand.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय जरा सवाल का पार्ट बी देखने का कश्ट करें। इसमें साहब ने क्वै चन के अन्दर कहीं अपग्रेडे ान का सवाल नही पूछा है, इसमें तो कंस्ट्रक ान का सवाल पूछा है। जो कुछ पूछा गया है, वह इस प्रकार से हैः—

If so whether there is also any proposal under consideration of the Government to construct the building of Primary Health Centre at Nanal Jat of district Faridabad in Health Constituency; and.

पी0 एच0 सी0 की अपग्रेडे ान का तो सवाल ही नही है। इन्होने तो केवल यह पूछा है कि क्या नांगल जाट की पी0 एच0 सी0 की बिल्डिंग बनाने की कोई प्रोपोजल है, अगर है तो कब तक बना देंगे?

श्री ओम प्रका ा भारद्वाजः स्पीकर साहब मैने पहले ही बता दिया है कि नांगल जाट में यह जो पी0 एच0 सी0 चल रही है, यह पंचायत की बिल्डिंग में चल रही है। अभी हम इसकी बिल्डिंग को नही बना पायेगें क्योकि हमारे पास 47 पी0 एच0 सी0 की बिल्डिंग्ज अन्डर कंस्ट्रक ान है। यह चूकि आन गोइंग वर्क्स है इसलिए पता है, इसलिए पता नहीं और क्या जानकारी हमारे आदरणीय साथी हमसे चाहते है।

श्री भगवान सहाय रावतः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि नांगल जाट की पी0 एच0 सी0 कब खुली थी और उसके बाद खोली जाने वाली पी0 एच0 सीज0 की क्या बिल्डिग्ज बना दी गयी है? अगर हां तो इसकी अब तक क्यों नहीं बनाई गयी है? मेरा प्र न तो केवल इतना सा है यह भेदभाव क्यों है?

श्री ओम प्रका ा भारद्वाजः मैने स्पीकर साहब, आपको बताया है कि नै ानल हैल्थ पालिसी बनाई गयी है। उसके कुछ नौर्म्ज है। हम उसके मुताबिक बना रहे है।

Cheeking of inereasing nuber of Jhuggi Jhuggi Jhopri in Cities

1383. Shri Mahender Partap Singh: Will the Minister of State for Local Government be pleased to state-

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to cheek the inerasing number of Jhuggi Jhopri and nu-autheorised number of Jhuggi Jhopri and un-authorieed colonies in the cities in the State; and

(b) if so the deails thereof?

Minister of State for Local Governmentf (Shri Kanti Parkash Bhalla):

(a) Yes.

(b) Statement giveing details of the schemes to check the increasing number of Jhuggi Jhopri and un-authorised colonies in the cities is land on Table of the House.

Statement of schemes to check the increasing number of Jhuggi Jhopri and un-anthorised construction in the cities.

1. Preparation of Town Planning Schemes under Section 203 of the Muncipal Act, 1973.

The Municpal Committees are required to prepare town planning schemes for meeting the growing housing needs of the urban population. Necessary guidelines have been issued and the municipalities have been asked to formulate speciflc schemes for the year 1991-92.

2. Development and Expansion Schemes of Towns under Section 24 of the Punjab Town Improvement Act 1922

The Improvement Trusts are responsible for the improvement and expansion of the towns by making development and expanison schemes of the towns and cities. Improvement Trusts have been revived in the 23 towns of Haryana during 1990 so that planned development and cxpanision of the towns could be ensured.

The Improvement Trusts in the State have been asked to for muate Town Planning Schemes for the year 1991-32

3. Environment improvement of Urban Slums Schemes.

A sum of Rs. 110.00 lacs has been provided in the budget for the year 1990-91 for providing grants to the municipalities during 1990-91 and a provision of Rs 125.00 lacs has also been made in the budget for the year 1991-92.

4. Housing and Shelter Upgradation Scheme under the Nehru Rozgar Yojna.

This scheme aims at improving the position of the exiting house of the slum dwellers, who are living in the towns, where population in above one lac but below 20 lacs. Under this scheme financial assistance upto Rs 4000 (Rs 3000 as loan and Rs 1000 as subsidy) is advanced to each beneficiary. A sum of Rs 313.12 lacs is proposed to be spend on this scheme out of which Rs 234.84 lacs will be loan and Rs 78.28 lacs will be subsidy.

5. Development of slum areas under the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Act. 1961.

The above Act has been amended and it provides for the constitution of Slum Clearance Borad for the delopment of Slums and rehabilition of the Slum dwellers in the cites .The proposed Hoard will formulate and implement comprehensive projeets for which, it is autherised also to take loans from the financial institutions like HUDCO, LIC, World Bank etc.

6. A scheme for the rehabiliation of the existing Jhuggi- Jhopri dwillers by providing them Sites & Servies proposed to be implemented jointly by Faridabad Complex Administration and Haryana Urban Development Authority is under consideration of the Government.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब ऑन दी टेबल आफ दी हाउस रखा है, उसके अन्दर यह लिखा हुआ हे कि भाहरों में अनाधिकृत बस्तियों तथा झुग्गी–झोपड़ियों की बढ़ती हुई सख्यां को रोकने के लिए कुछ स्कीम्ज बनायी गयी है। स्कीम के विवरण में इन्होने यह माना है कि भाहरी जनसख्यां की बढ़ती हुइ आवासीय आव यकताओ को पूर्ती हेतु, नगरपालिकाओं द्वारा टाउन प्लानिंग स्कीम बनाने की गहन आव यकता है। नगरपालिकाओं को वर्श 1991–92 के लिये वि ोंश टी0 पी0 स्कीमों तैयार करने के लिये आव यक दि ाा–निर्दे ा भेजे जा चुके है। इसके अलावा जवाब में यह भी कहा गया है कि नगरपालिकाओं को यह योजना के लिये बजट में 125 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है। मै आपके माध्यम से यह

जानना चाहता हूं कि यह तो मानते है कि इसकी गहन आव यकता है, लेकिन वह जो टी0 पी0 स्कीम्ज है क्या इसके बारे में दिया में दि ाा निर्दे ा दिये गये है? दूसरी बात यह है कि यह स्कीम्ज कब तक बनकर तैयार हो जायेगी और कब तक वह इनको लागू करेंगे? मेरा इस बारे में एक और प्र न है। सारे प्रदे ा के अन्दर 80 म्यूनिस्पिल कमेटीज है। सरकार ने इस काम के लिए केवल 125 लाख रूपयें रखे है।

श्री अध्यक्षः चौधरी महेन्द्र प्रताप जी, दूसरा सप्लीमैट्री बाद में आप कर लेना। मै आपको परमिट करूंगा।

श्री कान्ति प्रका ा भल्लाः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से अपने साथी विधायक को यह बताना चाहता हूं कि सारी हरियाणा स्टेट के अन्दर 81 म्युनिस्पिल कमेटीज है और 21 इम्पूवमैट ट्रस्ट है। उन सब को यह डायरैक ान दी गयी है कि जो स्लम एरियाज या गन्दी बास्तियां है, म्यूनिस्पिल कमेटीज के अन्दर जो खाली जगहें पडी हुई है उनकी टाउन प्लानिंग बनायें और उनकों हमारे पास भेजे ताकि हम स्लम एरियाज को खत्म करने के बारे में कार्यवही कर सके।

श्रीमति कमला वर्माः स्पीकर साहब, बजट के अन्दर 52 लाख 58 हजार रूपय आवास सुधार योजना के लिये रखे गये है। क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन–जिन जगहो पर झुग्गी झोपडीयां है, क्या उनको फिर से बसाने के लिये कोई

नमूना बनाकर इन्होंने भेजा है कि उनको इस तरह को आवसीय सुविधा दी जायेगी। इसके अलावा में एक और बात पूछना चहाती हूं।

Mr. Speaker: Only one suppementary at one time, I will give you another opportunity.

श्री कान्ति प्रका ा भल्लाः अध्यक्ष महोदय बहिन जी ने बजट के प्रोवीजन के बारे में सवाल किया है कि खास–खास जगहों पर जहां पर गुग्गी झोपड़िया है, उनके लिए क्या किया जा रहा है। मै उनकी बात नही समझ। अगर किसी खास जगह का नाम लेकर बहन जी बात करती तो मै बताता कि वहां की झुग्गी झोपड़ियों को हटाने और बसाने के लिये क्या योजना बनाई गयी है। यह जो आवासीय योजना है, इसके अन्दर केवल उन्ही लौगों को प्राथमिकता दी जायेगी, यह मै बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम बनाई जा रही है और इस स्कीम पर तेरह करोड़ रूपया खर्च किया जाएगा और छब्बीस हजार झुग्गी झोंपड़ियों को मकानों में कन्वर्ट किया जाएगा। इन लोगों को पैतीस–पैतीस गज के प्लाट दिये जाएंगे और जमीन का रेट 150 रूपया प्रति गज का होगा। इस स्कीम को हुड्डा तथा वहां का कम्पलैक्स दोनों मिलाकर तैयार करेंगे। इस स्कीम पर जल्दी ही अमल किया जाएगा।

श्री सूरज भानः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा के किन–किन भाहरों में यह समस्या समस्या गम्भीर

है और हरियाणा में टोटल कितनी झुग्गी झोपड़ियां है और क्या इस 125 लाख रूपय से काम पूरा हो जाएगा?

श्री कान्ति प्रका ा भल्लाः स्पीकर साहब, यह जो 125 लाख की बात मैंने कही है यह ग्रान्ट की भाक्ल में देनी है। जो टी0 पी0 स्कीम है उसको म्यूनिसिपल कमेटियां तैयार करेगी। उसके बाद अलौटमैट होगी।

श्री सुरजभानः स्पीकर साहब, मैने यह पूछा कि हरियाणा में कितनी झुग्गी झोपड़िया है?

श्री कान्ति प्रका ा भल्लाः स्पीकर साहब, मै बताना चाहता हूं कि बल्लभगढ़ में 26, तीन एन0 आई0 टी0 में, और दस फरीदाबाद में अवैध कोलोनीज है। इस तरह से वहां 39 अवैध कालोनीज है। फरीदाबाद में 26 हजार झोपड़िया है। अम्बाला सदर में 48 है और यमुना नगर में 22 है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि 125 लाख रूपया ग्रान्ट के रूप में दिया जाएग। मै समझता हूं कि यह रा ि ा अपयप्ति है। जीरा। स्पीकर साहब, यह सरकार झुग्गी झोपड़ी वालो के कही ऋण दे रही है और कही प्लाट्स दे रही है और इनको बनाने की को ि ा ा कर रही है लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि झुग्गी झोपड़ी तथा अनाधिकृत कालोनियों की समस्या अधिक बढ़ती जा रही है और वि ोश रूप से फरीदाबाद में।

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचारधीन कोई ऐसी स्कीम है जिसके दीर्घगामी परिणाम निकलें ताकि जे प्राईवेट कालोनाइजर है उनके द्वारा हुड्डा के रेट के अनुरूप लोगों को जमीन दी जा सके?

दूसरा मेरा सवाल यह है कि जहां इंडिस्ट्रियल एरिया है जैसे कि फरीदाबाद, वहा इंडस्ट्रीज की वजह से आबादी का दबाव बढ़ रही है। क्या सरकार के विचारधीन कोई स्कीम है जिससे कि यह बढ़ती हुई आबादी छोटे भाहरों की तरफ जा सके और बड़े भाहरों पर उसका दवाब कम हो सके?

श्री कान्ति प्रका ा भल्लाः अध्यक्ष महोदय, वह सारी प्रोबलम महेन्द्र प्रताप सिंह की सरकार द्वारा पैदा की हुई है। जब भजन लाल को सरकार थी तो प्राईवेट कालोनाइजर पैदा हो गए और उन्होंने नाजायज तौर पर कालोनियां बनाकर लोगों को प्लाट दिए। वहां पर न तो सड़के थी न वहां पर लाइट का कोई इन्तजाम था और न ही वहां पर पीने का पानी का तथा नालियां का इन्तजाम था। अब टी0 पी0 स्कीम म्यूनिसिपल कमेटीज के द्वारा तैयार करवाई जा रही है और हमने उनको लिखा है कि वे टी0 पी0 स्कीम तैयार करें। हमारी पूरी कोि ा ा है कि झुग्गी झोपड़ी वालों को राहत दी जाए। यह सहूलियत हम सभी जगह पर देगें वह चाहे अम्बाला हो और चाहे वह फरीदाबाद हो। हमारी पूरी कोि ा ा है कि इस तरह की आवास कालोनीज हम झुग्गी झोपड़ी वालो को दे।

श्री योगे ा चन्द भार्मा: स्पीकर सर, बल्लभगढ़ के अन्दर लगभग 26 अवैध कालोनीज है और वहां पर फरीदाबाद कम्पलैक्स ऐडमिनिस्ट्र ान के कर्चचारी आते है और उन अवैध कालोनीज तो तोड़ कर चले जाते है या फिर अगर कोई पैसा दे देता है तो उसके घर को नही गिराते। ऐसा करने से लोगों को काफी परे ाानी हो रही है। मै मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि इस तरह की अवैध कंस्ट्रक ान रोज हो रही है। मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कोलोनीज को पास करके क्या सरकार इस अन्याय से लोगों को छुटकारा दिलाने का विचार रखती है?

श्री कान्ति प्रका ा भल्ला: अध्यक्ष महोदय, जहां जहां इस प्रकार की कोलोनीज बन चुकी है, सरकार उनके बारे में विचार कर रही है। मै अपने माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि वे वहां की म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा एक रेजोल्यू ान डी0 सी0 के द्वारा रिकमन्ड करवा के हमारे हमारे पास भेजे तो उसकी हम जांच करवा लेंगे और उसके बाद लोगों से 20–25 रूपये गज के हिसाब से डिवैल्पमैंट चार्जिज लेकर ऐसी कोलोमजि को रेगुलेराइज करवाने के लिये सरकार विचार करेंगी।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैने सप्लीमैन्ट्री किया था लेकिन मंत्री महोदय ने कोई तसल्लीविख्भा जवाब नही दिया। मंत्री महोदय न अपने जवाब में बोलते हुए इसकी सारी जिम्मेवारी कांग्रेस सरकार पर ही डाल दी है कि ये सारी समस्याएं

उन्ही के टाइम की है। अध्यक्ष महोदय, जिनकी भी सरकार रही हो, ऐसे डिवैल्पमैंट के काम हर सरकार के राज में होते रहे है और जहां डिवैल्पमैन्ट होगी, वहां पर इस प्रकार की समस्याएं भी अव य ही होगी। मै यह कह सकता हूं कि आज तक कांग्रेस के समय में कभी ऐसी बाते नही हुई है जैसी कि यहां पर चर्चा हो रही है, यह निराधार है।

श्री अध्यक्षः महेन्द्र प्रताप सिंह जी आप सीधा सप्लीमन्ट्री कीजियेगा। यह कोई सप्लीमैन्ट्री नही है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः मेरी सप्लीमैंट्री है कि सभी सरकारों ने अपने वक्त में विकास के कार्यो को करने की भरसक कोि ा ो की है लेकिन जो कोि ा ा इस सरकार के वक्त में हुई है, वह नाकाफी है जिसके कारण से ये समस्या और बढ़ती हो गयी है। इस लिये मेरी सरकार से यह रिक्वैस्ट है कि अवैध कोलोनिज को आगे बढ़ने से रोका जाए। क्या सरकार किसी योजना कै तहत चाहे कोई पी0 सी0 की योजना हो या टी0 सी0 की योजना हो जिसका दूरगामी कोई असर हो, कोई ऐसा प्रावधान करना चाहती है। जिससे इस समस्या का कोई समाधान निकाला जा सके?

Mr. Speaker: Question Hour is over please.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारंकित प्र नों के लिखित उतर

Property damaged during Anit Resevation Agitation in Sonepat

1399. Shri Devi Dass: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the names and value of the property; if any, damaged during the anti reservation agitation in Sonepat; and

(b) whether any case aginst the persons for damaging of property as persons against whom cases were registerd?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह):

(क) सोनीपत में नुकसान हुई सम्पति की कुल अनुमानित कीमत लगभग 3, 14, 58, 107 रूपये है।

(ख) हां, श्रीमान।

(क) एवं (ख) की विस्तुत जानकारी सदन के पटल पर रखी है।

सूचि (विस्तुत जानकारी)

(क) सोनीपत में नुकसान/जलाई गई सम्पति की कीमत

क्रमांक	कार्यलय का नाम	नुकसान/जलाई गई सम्पति का नाम	अनुमानित कीमत रूपयों

			में
1.	पुलिस विभाग	पंखे, कार, मोटर साईकल, वायरलैस सैट	1,41,300.00
2.	हरियाणा राज्य परिवहन	बसें एवं भवन	3,05,00,000.00
3.	पी0 डब्ल्यू0 डी0 (भवन एव सड़क)	फरनीचर एवं भवन	1,10,000.00
4.	खाद्य एवं पूर्ति	गेहूं तथा दवाईयां	29,000.00
5.	डाक घर	फरनीचर, रिकार्ड एवं भवन	50,000.00
6.	केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग	फरनीचर एवं भवन	50,000.00
7.	आबकारी एवं कराधान	फरनीचर एवं भवन	65,000.00
8.	हरियाणा	फरनीचर एवं भवन	30,000.00

	पर्यटन विभाग		
9.	भारतीय खाद्य विभाग	फरनीचर एवं भवन	30,000.00
10.	दूरभाश केन्द्र	भवन, जीप एवं साज सामान	2,50,000.00
11.	हैफेड	फरनीचर एवं भवन	31,000.00
12.	सरकारी बैक	फरनीचर एवं रिकार्ड	1,17,,007.00
13.	पंजाब नै ानल बैक	फरनीचर एवं रिकार्ड	54,800.00
कुल कीमत			3,14,58,107.00

(ख) इस सन्दर्भ में 42 मुकदमे जिला सोनीपत में दर्ज किये गये। 12 मुकदमों में 100 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 26 मुकदमें उतेजित भीड़ के विरूद्ध दर्ज गये। अतः ऐसे मुकदमों में भागिल व्यक्तियों का ठीक से अनुमान लगाना सम्भव नही है।

Bus Stand at Kalanwall Mandi

1357. Shri Mani Ram: Will the Minister of State for Iransport be pleased to state whether there is any scheme under consideration of Government to construct Bus Stand at kalanwali

परिवहन राज्य मंत्री (श्री वेद सिंह मलिक): जी हां।

Construction of Roads

1407. Shri Atma Singh Gill: Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a road from Jakhal to Narail village and Alike to Malwala; and

(b) if so the time by which it is likey to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) नही।

(ख) प्र न उत्पन्न नही होता।

अतारंकित प्र न एवं उतर

Un-authorised outlets Loharu Canal

253. Shri Ran Singh Maan: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that un-authorised outets are runing in the the main canal of

authorised outles are running in the main canal of Loharu; if so the number therof and

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative the steps taken or proposed to be taken to close these outlets as referred to above?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह)

(क) जी नही।

(ख) प्र न ही नही उठतां

Counstruction of Satnali Feeder

254. Shri Ran Singh Maan: Will the Minister for Irrigataion and Power be pleased to state the persent stage of the construction of Satnali feeder togetherwith the time by which it is likely to be completed?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): सतनाली फीडर का निर्माण कार्य पूर्ण है

Outstandings of Electricity Bills

255. Shri Ran Singh Maan: Will the Minister for Irrgation and Power be pleased to state-

(a) wherther any amount of electrucity bills of Industrial, Agricultural and domestic secdtor are outstanding at present; if so, since when togetherwith the details thereof; and

(b) the steps, if any taken or proposed to be taken to realize the amount as referred to above?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह):

(क) हां श्रीमान जी,

दिसम्बर, 1990 के अन्त तक सामान्य (घरेलू एवं व्यावसायिक) कृशि औद्योगिक तथा सरकारी ऐजन्सियों के विरूद्ध मिन्म विवरण अनुसार कुल 22,559.43 लाख रूपय की धनरा ि बकाया पड़ी है:–

श्रेणी		रा ि (रूपयों लाखों में)
1.	सामान्य क्षेत्र (घरेलू एवं गैर घरेलू)	941.53
2.	कृशि	1038.61
3.	औद्योगिक	2529.74
4.	अन्य	344.66
5.	सरकारी एजेन्सियां	17704.89
	योग	22559.43

अवधि के अनुसार बकाया धन रा ि ा का विवरण निम्न अनुसार है:–

(क)	6 वर्श से अधिक पुरानी	2147.46
(ख)	3 वर्श से अधिक पुरानी	3050.39
(ग)	3 वर्श से कम पुरानी	17361.58
कुल योग		22559.43

(ख) बकाया धन रा ि ा को वसूल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे है:–

(1) दोशी व्यक्तियों के कनैक ान काटे जाते है।

(2) यदि कोई दोशी उपभोक्ता बकाया रा ि ा को जायज या निर्धारित अवधि के अन्दर जमा करा देता है तो उसका कनैक ान पुनः जोड़ दिया जाता है परन्तु यदि वह रकम जमा नही कराता तो उसका कनैक ान स्थाई रूप से काट दिया जाता है।

(3) उपभोक्ता की प्रतिभूति बकाया बिजली बिलों के विरूद्ध संमजित कर दी जाती है।

(4) बकाया बिलों के मामलो को हरियाणा विद्युत प्रदाय (देय वसूली) एकट 1970 के अन्तर्गत भूमि राजस्व की भांति वसूल करने की प्रक्रिया भुरू की जा रही है।

Size of Outlits

265. Shri Jai Narain Khundia: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the size prescribed for the outlets ment for irrigation purpose in the State ; and

(b) the size of outlets in District Sirsa, Hisar, Rathak, Sonepat and Bhiwani at present?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह):

(क) ग्रेवटी नहरों पर इनका आकार प्रायः 1.5 क्यूसिक है और उठान नहरों पर इनका आकर 1.0 क्यूसिज है।

(ख) सिरसा, हिसार, रोहतक व सोनीपत में आउटलैटों का आकार 0.75 क्यूसिक से 2.0 क्यूसिक तक है और जिला भिवानी में यह 0.5 क्यूसिक से 1.5 क्यूसिक है जो कि क्षेत्र के चक और वाटर अलाऊंस पर निर्भर करता है। फिर भी असाधारण केसों में आकार इन सीमाओं से भिन्न हो सकता है।

Upgradation of Schools

266. Shri Jai Narala Khundia: Will the Minister of State for Education be pleased to state the districtwise number of schools upgraded from Primary to Middle Middle to

High and High to 10+2 System in the State during the year 1989-90?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह): विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्श 1989–90 में स्तरोन्नत किये गये स्कूलों की जिलावर सख्यां

क्रमांक	जिला का नाम	स्तरोन्नत किये गये स्कूलों की सख्यां		
		प्राईमरी से मिडल	मिडल से हाई	हाई से+ प्रणाली
1.	अम्बाला	11	6	3
2.	यमुनानगर	8	3	1
3.	भिवानी	23	9	2
4.	हिसार	15	11	2
5.	गुड़गांव	8	5	1
6.	फरीदाबाद	4	5	3

7.	जीन्द	10	4	3
8.	करनाल	8	7	2
9.	पानीपत	9	8	—
10.	कुरूक्षेत्र	7	2	—
11.	कैथल	6	5	1
12.	महेन्द्रगढ़	10	5	2
13.	रिवाड़ी	3	2	1
14.	रोहतक	20	16	4
15.	सोनीपत	6	4	1
16.	सिरसा	12	8	5
योगः		160	100	31

Shri Jai Narain Khundia: Will the Minister of State for Tourism and Welfare of Scheduled Castes and Backward Chasses be pleased to state the districtwise number of Chaupals, if any constructed for the persons belonging to Scheduted Castes and Backward Classes during the peeriod from 1987 to 1990 in the State togetherwith the number of Chaupals lying incomplete so far?

Interim Reply

क्रमांक 4/91/243/M.T.W.

प्रेशक

श्री कि न हुड्डा,

राज्य मंत्री, पर्यटन एव अनुसूचित जातिया

एव पिछडे वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा,

चण्डीग।

सेवा में,

अध्यक्ष,

हरियाणा विधान सभा,

चण्डीग।

दिनांक, 4 मार्च, 1991

विशयः विधान सभा अतारंकित प्र न नं0 267

महोदय,

श्री जय नारायण खुडिया विधायक ने हरियाणा राज्य में अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये बनाई गई/अधूरी चौपालों के बारे में जिलावार वर्श 1987 से 1990 तक की सूचना मांगी है। मै आपको ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस

स्कीम के अधीन रा ि ा की स्वीकृतियां जिला के उपायुक्तों द्वारा की जाती है तथा इसाका आदान तथा वितरण तथा परिपालन सम्बन्धित5 खंड़ विकास एवं पंचायत अधिकारीयों द्वारा किया जाता है। स्पश्ट है कि 4 वशोंर् की सूचना विभिन्न स्तरों से एकत्रित की जानी है इसलिए इस प्र न का उतर तैयार करने के लिये काफी समय लगेगा तथा उतर भीघ्र तैयार कर पाना संभव नही है। इसलिए मेरा आपसे समय लगेगा तथा इसका उत्तर भीघ्र तैयार कर पाना संभव नही है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्र न का उत्तर देने के लिए कम से कम एक मास का समय देने का कश्ट करें।

भवदीय,

(श्री कि ान हुड्डा)

Cases of Theft, Murder registered in the State

268. Shri Jai Narain Khundia: Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state-

(a) the number of cases of theft of Cars, Scooters, Trucks murders and rapes registered in the State during the period from 1987 to 1990; and

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) in which stolen goods have been recovered and the persons arrested in respect of murders?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): एक विवरण तालिक सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण तालिका

वर्श	कार, स्कूटर और ट्रकों की चोरी के दर्ज अभियोग				हत्या के अभियोग	बलात्कार के अभियोग
	कार	स्कूटर	ट्रक	जोड़		
1987	55	208	57	320	484	142
1988	69	184	59	312	449	157
1989	101	250	58	409	500	172
1990	92	299	73	264	543	170

वर्श	जिन अभियोगों में चुराया गया सामान बरामद हो चुका है				हत्या के अभियोगों में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	
	कार	स्कूटर	ट्रक	जोड़		
1987	44	135	45	224	—	1084
1988	54	112	48	214	—	1075

1989	74	179	49	302	—	1170
1990	67	190	61	318	—	1279

Pay Scales to Jailis Offcers/Offcials

271. Seth Lachhan Dass Bajaj: Will the Minister for Jails be pleased to state-

(a) whether it is fact that the Jails Officers/officeals are not being given the pay scales and other facilities as are being given to the officers/officials of the Police

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative whether there is any proposal under consideration of the Government to bring them at par with the offcers/officials of the Police Department; and

(c) if so, the time by which the afore-said proposal is likely to be materalized?

जेल राज्य मंत्री (श्री देस राज):

(क) जी हां।

(ख) जी नही।

(ग) प्र न उत्पन्न नही होता।

Promotion of Employees working in Haryana State Small Industries and Export Coropation

270. Shri Kirpa Ram Punia: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether the reservation policy for SCs/BCs in promotion is being implemented by the Haryana State Small Industries and Ecport Corporation Chandigrad, if not, the reasons therefor; and

(b) the details of back-log if any, for the reserved cate-gories of posts in the above said Coporation at prisent category-wise separately?

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह):

(क) हां

(ख) केवल श्रेणी तीन के कुछ पदों में कुछ बैकलाग है जिसके संबंध में ब्यौरा सलंग्न सूची क के अनुसार विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

सूची

हरियाणा राज्य लघु उद्योग निर्यात निगम लि0, चण्डीगढ़

क्रम. सं0	पदों की कैटेगरी	स्वीकृत हुए पदों की संख्या	कुल भरे गए पदों की संख्या	अनूसूचित जाति			पिछड़ी जाति		
				रोस्टर के रजिस्टर के अनुसार पद भरे जाने चाहिए	रोस्टर रजिस्टर के अनुसार भरे गए पदों की संख्या	कमी	रोस्टर रजिस्टर के अनुसार पद भरे जाने चहिएं	रोस्टर रजिस्टर के अनुसार भरे गए पदों की संख्या	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चतुर्थ श्रेणी	197	162	20	28	+8	8	10	+2

2.	तृतीय श्रेणी								
(i)	लिपिक	97	86	19	16	−3	8	4	−4
(ii)	आ ाु लेखक	8	4	2	1	−1	—	—	—
(iii)	लेख सहायक / सहायक	134	134	26	13	−13	10	10	—
4.	सेल्स गर्ल / सेल्स मैन	20	15	2	—	−2	1	—	−1
5.	सेल्स सहायक	15	11	2	2	—	1	—	−1
6.	आ ाुलिपिक	9	5	2	—	−2	1	—	−1
7.	निजी सहायक	7	7	1	—	−1	—	—	—
8.	लेखाकर	12	8	2	1	−1	—	—	—

9.	ब्रांच मैनेजर	4	—	1	—	—1	—	—	—
10.	जिला विपणन अधिकारी	12	12	3	—	—3	1	—	—1
	द्वितीय श्रेणी	कोई कमी नही।							
	प्रथम श्रेणी	कोई कमी नही।							

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

(इस समय कई मैम्बर्ज बोलने के लिए खड़े हुए)

Mr. Speaker: Hon. Members, please take your seats. I will reply one by one. Until and unless you are satisfled, I will not proceed further.

15.00 बजे

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कालिंग अटैन ान था। कर्मचारियों के बारे में आपने ऐडजर्नमैंट मो ान ऐडमिट करके और उस पर डिस्क ान अलाऊ करके बड़ी अच्छी रिवायात डाली है। इन कर्मचारियों ने भी और मुख्य मंत्री महोदय ने भी कहा कि हम आपस में बातचीत के लिये तैयार है। उन्होंने आज लिखित रूप से भी मुख्य मंत्री महोदय के पास दरख्वास्त दी है। उन्होंने आज कहा है कि सरकार ने जो उतर दिया है, वह गल्त है लेकिन हम बातचीत के लिये तैयार है। अध्यक्ष महोदय, वे लोग आज जेल में है और सरकार यह कह रही है कि वे जेल में नही है। (ाोर एवं व्यवधान) उनका अध्यक्ष महोदय, इलाज भी नही हो रहा है। (ाोर)

Mr. Speaker: Sharma Ji this is not the way. I will not permit you to raise this like this again. I have received your calling attention motion and that is under exmination. Moreover, session is not going to be over today.Please take your seat.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार कर्मचारियों से बातचीत करने के लिये तैयार है कर्मचारी भी सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार है तो पहले जो लोग सरकार ने जेल में बन्द करवा रखें है उनको छोड़ा जाए तभी बातचीत का वातावरण बन सकता है तथा भाासन और प्र ाासन ठीक तरीके से चलाया जा सकता है।

Mr. Speker: Mr. Arya, Please take you seat.

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, हरियाणा एग्रे इंडस्ट्रीज द्वारा दी गई कीट ना ाक और खरपतवार दवाइयों ने कोई काम नही किया। इस बारे में मैने एक कालिंग अटैन ान मो ान का नोटिस दिया था, उसका क्या बना?

Mr. Speaker: Mr. Kataria you were sitting with me in my Chamber when I decided it. You know that it is fixed for tomorrow, You are still enquiring about it. This in not the way. Please take your seat.

श्रीमति कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैने 14–15 दिसम्बर को आपको एक पत्र लिखा था कि मुझे आठ घंटे इल–लीगल मैं रखा गया। यमुनानगर से 20 किलोमीटर दूर सुनसान स्थान में बस खड़ी कर दी, बाद में छोड़ दिया। उसका न आपकी और से और न ही मुंख्य मंत्री महोदय जी की और से कोई उतर मिला है कि अधिकारियों के खिलाफ क्या ऐक ान

लिया गया है। मेरे साथ गनमैंन भी था और साठ कार सेवक भी थे लेकिन दोशियों के विरूद्ध ऐक ान क्यों नही लिया जा रहा है?

Mr. Speker: I have sent that to the Government.

श्री मति कमला वर्मा: मै जानना चाहती हूं कि उसका कब तक जवाब आएगा?

Mr. Speker: I will require about it and let you know.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। भाुक्रवार को डिप्टी स्पीकर साहब जब यहां पर विराजमान थे तो मैने एक प्वायंट आफ आर्डर रेज किया था कि क्या सी0 आई0 डी0 का कोई अधिकारी/कर्मचारी हाउस में (औफिसर्ज गैलरी) में बैठ सकता है? में उस बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूं।

Mr. Speker: I will give my ruling today.

चौधरी सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब चौधरी सूरज भान जी से संबंध रखने वाला मैने एक काल अटैन ान मो ान दिया है। उसका क्या बना?

Mr. Speaker: That is nuder my consideration. Please take your seat.

श्री रामबिलास भार्माः स्पीकर साहब, सत्ता पक्ष के लोगों ने सम्पत सिंह जी की अध्यक्षता में एक स्ट्रैटेजी बनाई है। ....(ाोर)

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): कोई भी स्ट्रैटेजी नही है। यह सरासर गलत और निराधार बात है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः मेरी इजाजत के बगैर जो कुछ भी बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री राम बिलास भार्माः .....

प्रो0 सम्पत सिंहः .....

श्री राम बिलास भार्मा.....

प्रो0 सम्पत सिंहः .....

श्री वीरेन्द्र सिंह.....

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): स्पीकर साहब, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक दूसरे पर प्रत्यारोम न लगाए। हाउस में यह प्रथा चल पड़ी है कि माननीय सदस्य एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाने की कोि ा ा करते है। इस प्रथा को समाप्त किया जाए। जो माहौला बन गया है यह अच्छा नही है। (ाोर)

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री जी बड़ी अच्छी बात कहते है और बहुत अच्छी सलाह देते है लेकिन हमारी तरफ से क्या कोई आरोप किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ लगाया गया है? (ाोर) नही लगया गया। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बतलाए कि क्या विपक्ष को और से किसी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई व्यक्तिगत आरोप लगाया गया है? (ाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः आप तो सारा दिन ही आरोप लगाते रहते है। (ाोर)

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब.....
.....(ाोर)

Mr. Speaker: This is not to be recorded. (Interruptions) Comrade Harpal Ji this is not the way. Please take your seat.

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी बार–बार कहते है कि सरकार विपक्ष की और से कोई स्वस्थ आलोचना सुनना चाहती हैं अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का यह कर्तव्य बन जाता है कि अगर सरकार के किसी काम में या किसी नीति में कोई त्रुटि नजर आए तो उसकी आलोचना करे। यह लोकतंत्र का तकाजा है लेकिन इसमें व्यक्तिगत द्वेश क्यों है। आध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा कि यहां सदन में बैठे–बैठे एक जिम्मेदार मंत्री ने कहा कि बनारसी दास गुप्ता ने दिल्ली में एक करोड़ रूपय की

कोठी खरीदी है। अध्यक्ष महोदय, मैं चेलेंज करता हूं कि यह सरकार दिल्ली में मेरे नाम पर एक इन्च जमीन भी साबित कर दे, कोठी का तो सवाल ही पैदा नही होता तो मै आज ही अपना इस्तीफा दे दूंगा। मै यह चेलेज करता हूं कि यह सरकार जो मेरे खिलाफ आरोप लगाती है वह साबित करे। इस सरकार के हाथ में कानून है, हमारे खिलाफ केस चलाएं। (ाोर)

श्री सुरज भानः अध्यक्ष महोदय, ये भाई लगातार 4–5 दिन से अपने हाथ में एक कागज उठा कर मेरे खिलाफ कोई बात कह रहे है। मै यह कहता हूं कि इस बारे में हाउस की एक कमेटी बना दी जाए और वह कमेटी सभी मैम्बर्ज की नई और पूरानी प्रोपटी की इन्क्वायरी कर ले। (ाोर)

श्रीमति कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि अपोजि ान ठीक कह रहे है। (ाोर)

Mr. Speaker: I won't permit anybody to interrupt like this. Please take seat.

श्री सूरज भानः स्पीकर साहब, हमने तो इस सरकार से लोकायुक्त बैठाने के बारे में भी कहा था। यदि यह सरकार लोकयुक्त नही बैठा सकती तो कम से कम हाउस की एक कमेटी बना दी जाए जो नए और पूराने सभी एम0 एल0 एज0 की प्रोपर्टी की इन्क्वायरी कर ले। (ाोर)

(ाोर समय बहुत से मैम्बर्ज बोलने के लिये खड़े हुए।)

Mr. Speaker: Please take your seats. Next item.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

जिला हिसार में गन्ने की खरीद के लिए प्रबंध करने संबंधी

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of calling attention motion No. 26 from Dr. Harnam Singh, M.L.A. regarding arrangements for purchasing sugar-cane in district Hisar. I admit it. He may please read his motion and the concerned Minister may make the statement thereafter.

(At this stage many members rose to speak)

Mr. Speaker: Every body should take his seat. (Noise & Interruptions) I would not permit anybody except Dr. Harnam Singh, who may please read his calling attention motion. (Interruptions)

श्री आत्मा राम गोदाराः स्पीकर साहब, आप इनकी तरफ ही देखते रहते है। हमारी तरफ भी देख ले।

Mr. Speaker: Atma Ram Ji, you please take your seat. Let Dr. Harnam Singh read his call attention motion. (Interruptions)

श्री दुर्गा दल मंत्रीः स्पीकर साहब, मेरी जान को खतरा है। (ाोर एवं व्यवधान)

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब आनरेबल मैम्बर्ज की जान की खतरा है क्योंकि उनके जिले के एस0 पी0 ने उन्हें धमकी दी है।

Mr. Speaker: Please take your seat.

Comrade Harpal Singh: ----------

Mr. Speaker: This is not to be recorded. (Noise & Interruptions)

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इनकी जान को खतरा है और इन्होने आपको एक लैटर भी लिखा है। आप इनको सुन तो लीजिए। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Comrade Sahib, I have received that but I have not taken any decision as yet. Please take your seat,

डा0 रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर की जान को खतरा है। आप उनकी बात तो सुनिये। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Doctor Sahib, I have already said that I have received his letter but I have not taken any decision on that yet. You please take seat. (Interruptions)

Whatever is being said by any members without my permission is not to be recorded. I request Dr. Harnam Singh to please read his calling attention motion.

श्रीह हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मै इस माहन सदन का ध्यान एक अति आव यक लोक महत्व के विशय की विशय की और दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने भूना जिला हिसार में एक चीनी मिल स्थापित की है जो कि अभी तक चालू नही हुई है। परन्तु मिल की सहमति से गन्ने की का ात मिल के अधिकां ा क्षेत्र में की गई है। गन्ने की फसल तैयार है परन्तु उक्त मिले के चालू न होने के कारण खेतों में खड़ी है। उक्त सारे क्षेत्र के किसानों में मिल के अभी तक चालू न होने तथा गन्ने की बिक्री न होने से भारी बेचैनी व्याप्त है। किसानों की फसल नश्ट हो रही है। यदि गन्ने की फसल की खरीदने का तुरन्त प्रबंध नही किया गया तो फसल नश्ट हो जायेगी। अतः मैं निवेदन करता हूं कि खेतों में खड़ी गन्ने की फसल को खरीदने के लिये सरकार तुरन्त कार्यवाही करे तथा इस संबंध में एक व्यक्तव्य दे।

वक्तव्य–

सहकारिता मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

सहकारित मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): भारत सरकार ने 31.8.88 को भूना से 2500 टन गन्न पिराई क्षमता प्रतिदिन बाली एक नई सरकारी चीनी मिल स्थापित करने के लिए आ ाय पत्र प्रदान किया था। मिल स्थापना के लिए स्थान का चुनाव 29–9–88 को किया गया और प्लाट तथा म ाीनरी खरीद करने

का आदे ा 23–5–89 को दिया। मिल की इमारत बनाने का ठेका 19–9–89 को दिया गया। दुर्भाग्यव ा 27–7–90 को इमारत के ठेकेदार द्वारा कार्य रोक दिया गया। यदि ठेकेदार कार्य बीच में न छोड़ जाता तो वर्तमान पिराई सीजन के अन्त तक गन्ना पिराई का कार्य मिल भाुरू कर देती। क्योंकि प्लांट एवं म ाीनरी नियमानुसार आ रही थी। कार्य बीच में छोड़ने वाले ठेकेदार की जिम्मेवारी एवं कीमत पर जरूरी विभिन्न कानूनी व अन्य कार्यवाही करके मिल की इमारत बनाने का ठेका अन्य ठेकेदार को दे दिया गया है, जिसने पिछले सप्ताह ही कार्य आरम्भ किया है। अब मिला के अगले पिराई सीजन तक चालू होने की संभावना है।

यह सुनि ित करने के लिये कि कई मिल के भाुरू होने के समय भरपूर मात्रा में गन्ना उपलब्ध हो, मिल के क्षेत्र में मार्च 1990 से गन्ना उत्पादन प्रोग्राम भाुरू कर दिया गया था। क्योंकि इस क्षेत्र में पहले गन्ने बहुत कम होता था इस लिये गन्ना उत्पादन के लिये सहीं किस्मों का गन्ना बीज बाहर से मंगवाया गया। क्योंकि भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी मिल चालू वर्श के अन्त तक ही चल सकती थी इसलिए केवल 1500 हैक्टेयर के क्षेत्रफल मे ही गन्ना लगवाया गया। किसानों के गन्ने की खेती में पहली बार लगने व अन्य आरम्भिक दिक्कतों के कारण 1500 हैक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग 6 लाख क्विटल गन्ना होने की आ ाा थी। प्रायः यह देखा गया है। कि कुल गन्ने की पैदावार का 55 से 60 प्रति ात बीज गुड़ खांडसारी तथा चूसने आदि में प्रयोग हो

जाता है। क्योंकि मिल की योजना के अनुसार आने वाले वर्श में गन्ने के तहत लगभग 4000 हैक्टेयर ज्यादा क्षेत्रफल लाना था, इस लिए बीज के लिए गन्ने की ज्यादा मात्रा का प्रयोग होना था व उपरोक्त प्रति ात का बढ़ कर 65 हो जाना स्वाभविक था। अतः 6 लाख क्विटंल की कुल पैदावार में से 3 लाख क्विटल गन्ना तो बीज के तौर पर ही प्रयोग कर लिया जायेगा और लगभग 90 हजार क्विटंल गुड़ बनाने व चुसने आदि में लग जायेगा। अतः बाकी गन्ना जो कि 2.1 लाख क्विटल के करीब है, मे से 1.5 लाख क्विंटल गन्ना या तो भूना चीनी मिल ने स्वयं खरीदा कर पंजाब में बुडलाढा चीनी मिल को सीधा बेच दिया है। पंजाब में गन्ने की इस वर्श बहुत ही ज्यादा कमी है। यहां यह भी बताना ठीक होगा कि भूना सहकारी चीनी मिल ने किसानों से गन्ना खरीदने के लिए पांच गन्ना खरीद केन्द्र स्थापित किये ताकि किसानों को गन्ना बेचने में कोई दिक्कत न आये। लगभग 40000 क्विटल गन्ना जींद सहकारी मिल को ही भेजा गया है और बकाया 20000 क्विंटल गन्ना भी सहकारी चीनी मिल जींद भेजा जायेगा।

उपरोक्त से स्पश्ट है कि माननीय सदस्य की आ ाका के बारे सरकार को पहले ही ध्यान था और सरकार ने वे सभी आव यक व उचित पग पहले ही उठा लिये थे जो भूना सहकारी चीनी मिल भाुरू न होने के कारण जरूरी थें। इस समय जो गन्ना खेतों में भी खड़ा है व या तो मिल ने या किसानों ने बीच के लिये रखा हुआ है और यह सारा गन्ना की बिजाई पूरी होने के

साथ प्रयोग में ला लिया जाएगा। वहां यह कहना भी सराहनीय होगा कि हरियाणा सराकर जिसके मन में किसानों के हित सर्वेपरि रहते है न हर प्रकार से यह सुनि चत किया है कि मिल क्षेत्र में जो भी गन्ना उपलब्ध है उसका पूरी तरह प्रयोग हो जाए।

सदन के माननीय सदस्य यह जानकर खु ा की राज्य की सात सहकारी चीनी मिलें 4.3.91 तक 154 लाख क्विटल गन्ना पिड़ चुकी है जबकि पिछली वर्श इसी तिथी तक 134 लाख क्विंटल गन्ना ही पिड़ा गया था। यह तभी संभव ही पाया है कि मिलों की कार्य क्षमता का प्रति ात प्रयोग पिछले वर्श के 110 से बढ़कर 130 तक पहुंच गया है। हम इस बारे में पूर्णतयः जागरूक है कि राज्य में गन्ने की ज्यादा पैदावार होगी पर हमारी मिले इस गन्ने के प्रयोग के लिए कोई कसर बाकी नही छोडेगी। सरकार यह भी वि वास दिलाती है कि ना केवल नई चीनी मिलों के क्षेत्र में पैदा हुआ सारा गन्ना में लाया जायेगा बल्कि पुरानी चीनी मिलों के क्षेत्र का गन्ना भी पूर्णतयः प्रयोग कर लिया जायेगा चाहे चीनी मिले मई 1991 के अन्त तक क्योंन चलें क्येंकि सरकार को किसानों के हित से प्यारा कोई हित नही है।

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, किसानों का जो गन्ना बुडलाढ़ा की मिल को दिया गया है। उसका 2 रूपये क्विंटल के हिसाब से किरायें का काट लिया गया है। क्यां मंत्री जी बताएंगे कि भूना में जा गन्ना किसानों के खेतों में खड़ा है सरकार वह

सारे का सारा गन्ना अपनी चीनी मिलों को सप्लाई करवाने के बारे में विचार करेंगी?

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से सम्मानित सदन को वि वास दिलाता हूं कि केवल भूना का ही नहीं पूरे हरियाणा में चाहे जिस क्षेत्र मैं थी किसान के खेत में गन्ना खड़ा है उस सारे गन्ने की पिराई होने के बाद ही मिलों को बंद किया जाएगा।

वर्श 1991–92 के बजट पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज अब वर्श 1991–92 के बजट पर जनरल डिस्क ान होगी तथा थी श्री सीता राम सिंगला जी बोलेगे।

श्री सीता राम सिंगला (गुड़गाव): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे काचिल वित्त मंत्री ने 8 मार्च को यह बजट पे ा किया है। इस बजट की देखने से लगता हे कि यह बजट दि ााहीन और नीरस बजट है। यह बजट कांग्रसी संस्कृति के आधार पर बना हुआ बजट है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस न परम्परा चलाई कि बजट को घाटे का बजट प्रस्तुत करो और घाटा कैसे पूरा होगा इस बारे में कोई जानकारी न दो तथा बजट पे ा करने से पहले ही दूसरे माध्यमों सरकार जनता पर करों का बोझ लाद दें। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट तसलीम किया है कि इस बजट को पे ा करने से पहले ही 115 करोड़ रूपये का

बोझ पानी के बिलौं के रूपो में, बिजली के बिलों के रूप में तथा अन्य तरह से जनता पर डाल चुके है। वह जो घाटे का प्रोवीजन खुला छोड़ दिया गय है, इसके लिए कुछ नही किया गया इससे ऐसा खतरा लगता है लगाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे इस बजट में कृशि के बारे में जिक्र आया है। वैसे ते इस सरकार ने किसानों को बहुत सुविधाएं दी है। अ ाोक होटल के अन्दर 40 रूपये की एक सब्जी का कटोरी मिलती है, वहां 20 रूपये में खाना देने के लिये किसानों को राहत दी है। इससे ज्यादा राहत और यह सरकार क्यों देगी। इसमें यह भी जिक्र आया है। कि अनाज के रेट बढ़ाये गये है। धान का रेट 185 रूपये से बढ़ा कर 205 रूपये किया गया हूं। गेहूं का भाव 183 रूपये बढ़ा कर 215 रूपय किया है गया है गन्ने का भाव 38 रूपये से बढ़ा कर 46 रूपये किया गया है आपको यह पता है कि किसान जहां उत्पादक है, वहां उपभोक्ता भी है जिस परसैटेज के हिसाब से उसको अनाज की बढी हुई कीमतें दी गयी है उसके ज्यादा महंगाई के हिसाब से आपको आनज की बढ़ी हुई कीमतें दी गयी है, उससे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। उसको उससे ज्यादा मंहगे भाव से बाजार से चीजें खरीदनी पड़ती है। खाद है, बिजली है, पानी है, कीटना ाक दवाइयां और डीजल है। यह सब चीजें इतनी मंहगी है लेकिन जितनी किसान के उत्पादन की जो कीमतें बढ़ाई गयी है, वह बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात को जानते है कि हरियाणा में किसानों के हकों के लिये जब सघर्श किया गया था, लेकिन बाद में जब यह सरकार बनी तो इन्होंने एस0 वाई0 एल0

नहर के पानी लाने का जिक्र भी किया। उस समय हमारे नेता सबसे पहली बात यह कहा करते थे कि नहर का पानी जरूर आपाके जल्दी देंगे। अब तो केन्द्र की सरकार मैं इनके नुमाायदें बैठे हुए है लेकिन एस0 वाई0 एल0 नहर के पानी के जल्दी आने की कोई संभावना नही है। जब तक एस0 वाई0 एल0 का पानी हरियाणा में नही आयेगा तब तक चाहे किसी भी वर्ग का आदमी हो, तरक्की नही हो सकती है। फसल के बीमे के बार में भी जिक्र आया। इससें किसान को पूरा लाभ नही होगा जब तक कि आप कोई ऐसी योजना नही बनाते जिसमें किसान की फसल का पूरा बीमा हो सके। इसके अलावा औलावृश्टि से 400 रूपये प्रति एकड़ की राहत बहुत ही कम है। आज की मंहगाई के समय में यह बहुत कम है। मै मांग करता हूं कि इसको कम से कम 1000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना चाहिए। यही नही केवल औलावृश्टि की ही बात नही होनी चाहिये दूसरी जो नैचुरल केलौमिटीज है या दूसरी फसल की बीमारियां है जिनकी वजह से फसल मर जाती है, उनके लिये भी सरकार की कुछ न कुछ राहत देनी चाहिए। इसके अलावा यहां बिजली के कुनैक ान के बारे में भी बात आयी है। एक बात जो यहां पर कही गयी है वह यंह कि जो किसान 7,000 रूपये देगा, उसको वरीयता के आधार पर कुनैक ान दिया जायेगा। इससे वह गरीब किसान जिसके पास इतने साधन नही है कि यह है कि वह 7,000 रूपया पहले जमा कराने वाली बात को समाप्त करना चाहिये। इसके अलावा यहां पर आगरा कैनाल के नियंत्रण का जिक्र भी आया है। इसी सै ान में

एक दो दिन पहले भी इसका जिक्र आया है और बजट में भी जिक्र आया है। (**इस समय श्री उपाध्यक्ष हुए।**) उपाध्यक्ष महोदय मेरा कहना यह है कि इस सरकार को इस समस्या की और भी ध्यान देना चाहिए था। हमारे इलाके के किसानों को पानी पूरा न मिले और आबियाना ज्यादा देना पड़े, यह कहां का न्याय की बात है। इसके लिये बड़ी देर से कोि ा ें की जा रही है कि इसका नियंत्रण हमारी सरकार अपने हाथ में ले ले लेकिन इसका नतीजा कुछ नही निकला है। आप के माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि इस मामले में मुख्य मंत्री महोदय व्यक्तिगत रूचि लेकर इस समस्या को हल करे। एक और समस्या के बारे में जिस की वजह से मेरे यहां पर काफी गड़बड होने को थी, वह भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं। वि ोश तौर पर मेरे अपने हल्के से यह समस्या संबंध रखती है। उपाध्यक्ष महोदय, समस्या यह है कि गुड़गाव के चारों तरफ किसानो की उपजाऊ जमीन है जहां पर किसान लहलहाती खेती करते है। उस जमीन को जिस बेरहमी से एक्वायर किया गया है, वह देखने वाली बात है। झाड़सा गांव की यह जमीन है। मेरे हल्के में यह गांव पड़ता है। 360 गांवो की चौधराहट का वह गांव है। वहां के किसानों के साथ किस प्रकार से मजाक किया जा रहा है, यह देखने वाली बात है। उस गांव के अन्दर सैक्टर 29 बनाया गया है। सरकार द्वारा आधे से ज्यादा गांव एक्वायर कर लिया गया है। जिसमें 500 तो हरिजनों के मकान है, गांव का हाई स्कूल है, बाल्मीकियों के दोनो मोहल्ला है, बाल्मीकी मंदिर कृश्णा मंदिर हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर सैनी

मोहल्ला जैन धर्म ाला आदि सारे का सारा इलाका ही सरकार एक्वायर कर रही है। श्री मान बनारसी दास गुप्ता जब मुख्य मंत्री थे तो वे गुड़गाव में आये थे, उस समय लोग इनसे भी मिले थे। वहां पर 15,000 लोगों का इकट्ठ था। उन सब के सामने इन्होंने यह वायदा किया था कि उस अधिकारी को जिसने यह गल्त काम किया है और सरकार को इस आबादी को ऐक्वायर करने की सिफारिस भेजी है, मै उसे नही छोडूगा। अब अधिकारी को दण्ड दिया जाएगा और उन्होने कहा था इस आबादी को मुक्त कर दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने यह आ वासन पन्द्रह हजार लोगों के सामने दिया था लेकिन मुझे डर है कि सैक ान छः का नोटिस भीघ्र आएगा और लोगों के अन्दर बड़ी भारी बेचैनी पैदा हो जाएगी। लोगों के अन्दर बड़ा आक्रो ा पैदा हो जाएगा। इसके लिऐ हमें बड़ा संघर्श करना पड़ेगा और हालात खराब हो जाएगे। इसलिए मेरी इस सरकार हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के रेट बढ़ा दिए गए है। अब बिजली के रेट बहुत अधिक बढ़ा दिए गए है। भाहरों में जो एक रेढ़ी वाला है या चपड़ासी की नौकरी करता है उसका पांच सौ और एक हजार का बिल आ जाता है। जब से कम्प्यूटर द्वारा बिल आन लगे है तो वे वि ोश रूप से गलत होते है। इस वजह से भ्रश्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया है उपाध्यक्ष महोदय, एक कंज्यूमर के पास एक हजार का बिल आता है। उससे कहा जाता है कि पांच सौ रूपयें दे दो बिल कम हो जाएगा लेकिन दो महिने के बाद फिर एक हजार रूपये बिल आ जाता है इससे जनता बहुत अधिक परे ाान

है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए उपाध्यक्ष महोदय, फवे चर आवर के दौरान यह जिक्र की हरियाणा में अनऐंप्रूव्ड कालोनीज बहुत अधिक बन गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का दिल्ली के नजदीक पड़ता है। वहां पर एक अनऐप्रूव्ड कालोनी है। वहां के रहने वालों का कहा गया कि उनको बिजली का कनैक ान नही दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, उस कालोनी में तीन हजार मकान है और अढ़ाई हजार मकानों मं बिजली उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर प्राईमरी स्कूल खोल रखा है और अढ़ाई हजार मकानों में बिजली के कनैक ान दिए गए लेकिन बाद मैं कह दिया गया कि कनैक ान नही मिलेगे। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर प्राईमरी स्कूल खोल रखा है, वहां पर हैल्थ सैन्टर खोल रखा है और पिछले बीस पच्चीस साल से लोग वोट दे रहे है लेकिन वहां पर बिजली के कनैक ान के लिए मनाह कर दिया गया है। लोग इस कारण परे ाान है। मेरा निवेदन है कि चाहे वह कालोनी अनऐप्रूब्ड है लेकिन उनको बिजली मा और पानी का कनैक ान दिया जाना चाहिए। 1977 में भी इस बारे में केस सरकार के पास आया था। जब डा0 मंगल सैन लोकल गवर्नमैंट मिनिस्टर थे तो उन्होने उस कालोनी को देखा था और उन्होने वहां पर बिजली का कनैक ान देने के लिए रिकमैन्ड किया था। उपाध्यक्ष महोदय, डिप्टी कमि नर ने भी उस कालोनी देने के लिए रिकमैन्ड करके भेज है। वहां पर बिजली और पानी का किल्लत है मेरा सरकार से निवेदन है कि जो भी ऐसी जगह है, जो भाहरों के पास है वहां लोगों की सुविधा के लिए बिजली और पानी का कनैक ान दिए

जाएं। ऐसी कालोनीज के लोगों को भाहरों के पास नौकरी मिल गई है और उन्होंने पचास और सौ गज के प्लाट लेकर अपने छोटे–छोटे मकान भी बना लिये है। इसलिए उनको पानी और बिजली की सुविधा दी जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से नगरो में पानी की व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। सारे हरियाणा के लिए इस काम की मद में 8 करोड़ 60 लाख रूपय रखा गया है। मै समझता हूं कि यह बहुत थोड़ी रा ि ा है। हरियाणा में 8। कमेटोज है और 37 नगर है वहां पर जल निकासी को व्यवस्था ठीक नही है। इस नगरों में पानी की बहुत कमी है। इसका कारण यह है कि ट्यूबवैल्ज बहुत कम है और जब वहां बिजली जाती है तो पानी नही आता। मेरा निवेदन है कि नगरपालिकाओं का ट्यूक्वैल्ज के लिए जनरेटर की सुविधा दी जाए ताकि जब बिजली न हो तो जनरेटर चलाकर पानी उपलब्ध कराया जा सके। दूसरी बात यह जो मै कहना चाहता हूं कि पब्लिक हैल्थ जो पाइप लगाती है वह प्लास्टिक के होते है एक गांव से दूसरे गांव से जाती है जब उन पर कोई कोई ट्रक या गाड़ी गुजरती है या कोई और हैवी व्हीकल गुजरता है तो वे पाइप टूट जाते है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस तरफ ध्यान दें। और इस तरह के पाइप लगाए जाए जो मजबूत हो। ऐसा करने से मैटोरियल का खर्चा भी कम आएगा क्योंकि बार–बार पाइप बदलने से खर्चा ज्यादा होता है और लोगों को भी दिक्कत आती है। उपाध्यक्ष पाइप बदलने से खर्चा ज्यादा होता है और लोगों को भी दिक्कत आती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक

बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांव भाहरों के बिल्कुल नजदीक है और जहां चारो तरफ हुड्डा ने जमीन ऐक्वायर कर ली है वहां गांव के अन्दर सीवरेज और विकास का काम हुड्डा ने जमीन ऐक्वायर कर लो है वहां गांव के अन्दर सीवरेज और विकास का काम हुड्डा करेगा। इस तरह का फैसला सरकार लिया था। लेकिन में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी तक ऐसी जगहों पर कोई विकास कार्य भाुरू नही हुआ है। वहां पर लोगों को बड़ी भारी दिक्कत है खासतौर पर महिलाओं को भाौच जाने को बड़ी दिक्कत आती है। वहां पर महिलाओं के लिए भाौच के लिए कोई व्यवस्था नही है। गांव में ऐसे लोग है जो अपना सोवरेज और पानी का कनैक ान लेना चाहते है। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को कनैक ान दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं फूड एण्ड सप्लाईज के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा के अन्दर मिट्टी के तेल की बड़ी भारी कमी है। डिपो होल्डर्ज फूड एण्ड सप्लाईज के इंस्पैक्टर्ज से मिलकर गड़बड़ करते है। मिट्टी के तेल का जो पैमाना है, वह भी कम है। पांच लीटर को बजाये तीन लीटर का ही होता है और कीमत भी पूरी से कुछ ज्यादा ही लगते है। इस तरह से गरीब लोगों के लूटा कीमत भी पूरो से कुछ ज्यादा ही लगाते है। इस तरह से गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि सरकार इस और ध्यान दे ताकि गरीब लोगों को कुछ राहत मिल सके। दूसरी बात यह है कि डिपो होल्डर्ज

गेहूं को अपनी मांग के अनुसार नहीं उठा सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन की कमी होती है जिसका असर मिल सके। दूसरी बात यह है कि डिपो होल्डर्ज गेहू को अपनी मांग के अनुसार नही उठा सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन की कमी होती है जिसका असर वहां को गरीब जनता पर पड़ता है। अगर डिपो होल्डर्ज के पास लोगों की जरूरत के लिये गेहूं उपलब्ध नही होगा तो लोग गेहूं से वंचित रह जाएंगे। इसलिये मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि ऐसे डिपो होल्डर्ज को बैंको से या तो लोन दिलवाया जाए या फिर उन को उतने समय तक के लिये गेहूं उधार दिया जाए जिस समय तक थे उस गेहूं को बेच न ले। अगर डिपो होल्डर्ज के पास धन का अभाव होगा तो जनता के पास अनाज कैसे पहुंचेगा। अतः सरकार इस तौर वि ोश ध्यान दे।

इसके साथ–साथ मेरी एक और रिक्वैस्ट है कि मेरे इलाके में जो काफी पैदा होता है जोकि खाने के कम आता है परन्तु माल्ट में उसका उपयोग ज्यादा होता है। उससे भाराब बनती है और सरकार को उससे आमदनी होती है लेकिन यह आइटम खाद्य पदार्थ होने के नाते फूड एण्ड सप्लाईज विभाग के अन्दर आती है। जिससे किसानों को काफी परे ाानी होती है। किसानों को इसका पर्याप्त धन प्राप्त नही होता। इसलिये मेरा यह रिक्वैस्ट है कि इस आइटम को फूड एण्ड सप्लाईज विभाग के परव्यु से निकाला जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दिल्ली के नजदीक न्योडा में उतर प्रदे ा सरकार ने उद्योगों के मामले में लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी है और वहां पर दिन व दिन नई–नई फैक्टरिया लग हरी है और हरियाणा से भी से भी लोग अपनी फैक्टरिया उखाड़ उखाड़ कर वहां पर लगा रहे है। आज हरियाणा के अन्दर उद्योगपतियों को बहुत परे ाान किया जा रहा है जिस कारण से उद्योगपति न्योडा में अपनी फैक्टरियां ि ाफ्ट कर रहे है। साथ ही साथ जो इस विभाग के अधिकारी भी है उन्होंने भी पूरी तरह से लूट मचा रखी है। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री महोदय के पास इस तरह को ि ाकायतें भी आई होंगी कि व्यापारियों को परे ाान किया जाता है:

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को बिजली की आव यकता है, इसलिए उद्योगों को बिजली कम दी जा रही है। इसलिए मेरी रिकवैस्ट है कि अगर बिजली की कमी है तो कम से कम डीजल की सप्लाई तो मुतवातर होनी चाहिये। अतः सरकार इस और ध्यान दे। उपाध्यक्ष महोदय, जन संदे ा के नाम से गुड़गांव के अन्दर जो यूनियनें बनी हुई है, वे व्यपारियों से इस नाम से चन्द्रा लेती है, इस और सरकार को वि ोश ध्यान देना चाहिये मैं पहले भी इस बात का जिकर कर चुका हूं कि इस तरह से व्यापारियों को तंग किया जा रहा है, इस पर सरकार को और से रोक लगनी चाहिए। (ाोर एवं व्यवधान)

इसके बाद अब मैं हरियाणा रोडवेज के बारे मै भी कुछ निवेदन करूगा कि सरकार ने छोटे छोटे रूटों पर बहुत कम बसें लगाई हुई है और लम्बे रूटों वाली बसें गांव के पास खड़ो होकर नही जाती जिस कारण से बेचारे गांवो के लोगों को आने जाने में बड़ी परे ाानी का सामना करना पड़ता है। इसलिये। मेरी सरकार से रिक्वैस्ट जाने में बड़ी परे ाानी का सामना करना पड़ता है। इसलिये मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि छोटे–छोटे रूटों के लिये अधिक बसें चलाई जायें ताकि लोगों को सुविधा हो सके। इसके साथ–साथ मै एक बात और कहना चाहता हूं कि जब सभी हैड क्वाटर्ज से चण्डीगढ़ के लिये एक डी लैक्स बस चलाई जा रही है तो गुडगांव उससे वंचित क्यों रखा गया है। मेरी प्रार्थना है कि गुड़गांव से भी चण्डीगढ़ के लिये डी–लैक्स बस चलाने का भीघ्र ही प्रबन्ध किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, गुड़गांव एक ऐसा भाहर है जहां से लगभग रोजाना 2000 लोग दिल्ली अपने किसी न किसी काम से आते रहते है और बसों को कमी के कारण बस स्टैण्डज पर लोगौं की बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। खास तौर पर महिलाओं को बस वर्गरह चढ़ने के टाइस काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं का हालत बहुत भाोचनीय होती है जबकि दूसरे लोग धक्का करके बस पकड़ लेते है। ओरती की जो मिट्टी खराब होती है उसको देखकर हमें बड़ा ही दुख होता है। इसलिये मै सरकार से यह कहूंगा कि गुड़गांव से दिल्ली आने जाने के लिये ज्यादा से ज्यादा छोटे रूटों की बसों इन्तजाम किया

जाए और एक डी–लैक्स बस गुड़गांव से चण्डीगढ़ के लिये भी चलाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़को के बारे में कहना चाहता हूं। गुड़गांव से दौलतपुर धर्मपूर होते हुए भटोकड़ा गांव की सड़क जो दिल्ली से मिलाती है वह टूटी हुई है। गुड़गांव से बजरखेड़ा–नजफगढ़ जाने वाली सड़क दिल्ली सीमा तक टूटी हुई है, इनको ठीक करवाया जाए। गुड़गांव से मकडोला–रावता गांवों को जाने के लिए बहुत तकलीफ होती हैं ये गांव दिल्ली सीमा पर लगते है। दिल्ली वालों ने अपनी सीमा के अन्दर सड़क बना रखी है लेकिन हरियाणा की तरफ सड़क नही बनी हुई है। इस वजह से लोगों को दिल्ली आने–जाने में दिक्कत होती है। मेरी प्रार्थना है कि इस काम को भी करवाया जाए। राश्ट्रीय मार्ग नं0 8 जो जयपुर को जाता है उस के पास गुड़गाव के पास पुखराली व झाड़सा रोड जाती है, उसकी चौड़ा करवा कर दो लेन बनाया जाए। यह सड़क टूटी हुई है और कम चौड़ी है इसलिए वहां रोज दुर्घटनाएं होती है। मेरी प्रार्थना है कि उसको चौड़ा करवाया जाए। अब मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां डूढा, हेडा चकपुर मजधेडा, मकडोला और बढेढा में प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज खोले जाएं। मै एक निवेदन और करना चाहता हूं कि गांवो में आम तौर पर कोई डाक्टर या टीचर रहने को तैयार नही होते क्योंकि सरकार ने नियम ही इस प्रकार के बना रखे है क्योंकि जो कर्मचारी भाहर में रहता है उसको वेतन

भी ज्यादा मिलता है और हाउस रैट भी ज्यादा मिलता है। गांव में रहने वाले को ये दोनो चीजे कम मिलती है। इसलिए गांव और भाहरों में ये सुविधाए एक जैसी होनी चाहिएं। आज क्या होता है कि जिस भी डॉक्टर या मास्टर की गांव में ट्रांसफर हो जाती है वह पोलटीकल दबाव से दोबारा भाहर में आ जाता है। गांवों में आज हैल्थ सैन्टर्स की बिल्डिंग्ज तो बनी हुई है लेकिन वहां डाक्टर नही होते। ि ाक्षा के बारे में मै अर्ज करूंगा कि मेरे हल्के में भी और सारे हरियाणा में स्कूल अपग्रेड हुए है। एक साल उनको अपग्रेड किए हो गया है। लेकिन जो सैक ांड पोस्टस है उन पर टीचर नही पहुंचे, प्रिसिपल नही पहुचे। बगैर मास्टरों के स्कूल चल रहे है। मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द टीचर्ड का व्यवस्था को जाए। अब मार्च का महीना चल रहा है और परीक्षाएं भाुरू होने वाली है। सारा साल बच्चे खेलते कूदतें रहे क्योंकि अध्यपपकों की व्यवस्था नही थी। मुख्य मंत्री जी को पता है, पिछले सैक ान में भी इसका जिक्र आया था। चौधरी देवी लाल जी ने एक सर्कुलर भेजा था कि हरियाणा के कुछ लोगों प्रदे ा से बाहर रहते है और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। उन्होने कहा था कि अगर ऐसे लोगों हरियाणा में योगदान करें तो हम उनका नाम किसी इंस्टीच्यू ान से जोड़ देंगे यानी इंस्टीच्यूट उनके नाम से जाना जाएगा। हमारे हरियाणा के सेठ महाबीर प्रसाद बम्बई में रहते है। मैने उनसे प्रार्थना को थी कि गुडगांव में एक तीसरे कालेज की आव यकता है इसलिए उसके लिए आप अपना योगदान दे। वे तीस लाख रूपये देने के लिए राजी हो गये थे।

उन्होंने कहा था कि नया कालेज मेरे माता पिता के नाम से जाना जाए। उसका नाम सुरजा सुरजी रख दिया जाये। मैने इस बारे में सरकार को लिखा था और इन्होंने मान भी लिया था। जब हुकम सिंह जी ि ाक्षा मंत्री थे तो इन्होने कहा था कि उनकी औफर हमारे पास आ गई है। लेकिन आज तक उस बारे में कोई निर्णय नही लिया गया है। वे आज भी तीस लाख रूपया देने के लिये तैयार है। अब गुड़गांव में नए नए सैक्टर बन रहे हैं। किसी भी सैक्टर के अन्दर यह तीसरा कालेज खोल दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां गवर्नमैंट हायर सैकेंडरी स्कूल एक हो है। उसमें ग्यारवी क्लास के अन्दर 30 सैक ाज है जबकि है जबकि स्कूल के कुल कमरे सात ही है। 23 सैक ाज बाहर धूप में बैठते है। चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो और चाहे सर्दी हो, उस स्कूल में बैठने के लिये बच्चों का कमरे नही है। अगर खोल दृश्टि से उस स्कूलो के बच्चों को देखा जाए तो उस स्कूल के बच्चे नै ानल और इन्टर नै ानल लैवल पर हरियाणा प्रदे ा का नाम रो ान करते है। उस झाडसा स्कूल के ग्राउड मे वहा के आम पास के स्कूलो के लडके लडकिया खेलो की प्रैक्टिस करते है लेकिन इम्प्रूवमैट ट्रस्ट वाले उस स्कूल के ग्राउड को एक्वायर करने की कोि ा ा कर रहे है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उस ग्राउड को एक्वायर ने करने दिया जाए। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उस स्कूल के बच्चो के बैठने के लिए कमरे अव य बताए जाए ताकि बच्चो को कोई परे ाानी न हो और बच्चे आराम से पढ सके। इस वक्त उस स्कूल मे 11वी क्लास मे इतने ज्यादा

सैक ांज होने का यही कारण है कि उसके आस पास के 10 किलोमीटर के एरिया मे कोई 10 जमा दो प्रणाली का स्कूल नही है लेकिन उस गाव मे मे हाई स्कूल की बिल्डिग तैयार है। वह बिल्डिग गाव वालो ने बनाई है उस स्कूल को मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड करने के लिए डी0ई0ओ. की रिकमैडे ान भी आई हुई है। सरकार ने मेरी प्रार्थना है कि उस स्कूल को मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड किया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, गुडगाव दिल्ली के बिल्कुल नजदीक पडताहै इसलिए गुडगाव के कालेजो मे बी0एड और ला की क्लासिज भाुरू की जाए। इसके अलावा नूह मे एक पोलिटैकनिक कालेज खोलने के बारे मे चौधरी देवी लाल जी ने कहा था लेकिन अभी तक वहां पर वह कालेज बनाना भाुरू नही हुआ है। उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय अब मैं सेल्ज टैक्स के बारे में कहना चाहूंगा। हरियाणा में सेल्ज टैक्स ज्यादा होने के कारण हरियाणा प्रदे ा का सारा कारोबार दिल्ली में होता है क्योंकि दिल्ली हरियाणा के नजदीक है और वहां पर सेल्ज टैक्स या तो बिल्कुल नही है या हरियाणा से कम है। मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे एक माचिस है इस पर हरियाणा के अन्दर सेल्ज टैक्स है जिसका इस्तेमाल गरीब लोग करते है बड़े–बड़े लोग तो गैस का चूल्हा जलाने के लिए घरो में गैस लाइटर रखते है उसमें जलाते है लेकिन गरीब लोगों की बीड़ी जलाने के लिए माचिस की जरूरत पड़ती है हरियाणा प्रदे ा के अन्दर माचिस पर 8.10 परसैन्ट सेल्ज टैक्स है जबकि दिल्ली के अन्दर माचिस पर कोई

सेल्ज टैक्स नही है। इसके अलावा मै एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो डालडा घी हरियाणा प्रदे ा के अन्दर बनता है वह दिल्ली भेज दिया जाता है और वह दिल्ली से दो नम्बर का बन कर हरियाणा में आता है क्योंकि दिल्ली में डालडा घी पर 5 परसैट सेल्ज टैक्स है और हरियाणा में 8.10 परसैट सेल्ज टैक्स है। एक डालडा घी के कनस्तर के रेट मैं हरियाणा और दिल्ली में 25 रूपय का फर्क है। हरियाणा में एक डालडा घी कनस्तर में 25 रूपय का फर्क होने के कारण लोग सेल्ज टैक्स की चोरी करते है। मुख्य मंत्री जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर हुई बहस का जवाब देने हुए यह कहा था कि हरियाणा के अन्दर पीतल के बर्तनों पर सेल्ज टैक्स कम किया है। जिससे लोगों की राहत मिली है और टैक्स की चोरी भी कम हुई है अगर वह सरकार डालडा घी पर उसी प्रकार से 8.10 परसैट सेल्ज टैक्स की बजाय 5 परसैट सेल्ज टैक्स कर दे तो मै इस बात की गारंटी लेता हूं कि लोग टैक्स की चौरी करना कम कर देंगे वरना डालडा घी के एक कनस्तर में दिल्ली और हरियाणा के अन्दर 25 का फर्क होने के कारण लोग टैक्स की चोरी करेंगे, इससे सरकार का कोई लाभ होने वाला नही है। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा में बार्डर्ज पर यह टारगैट फिक्स किया जाता है कि हर बार्डर से इतने पैसे की कलैक ान जरूर करनी पड़ेगी उस कारण से अधिकारी लोग किसी न किसी बहाने से प्राईवेट वाहनों से रोक लेते है और उनसे अनाप भानाप जुर्माना लेते है। यह बहुत ज्यायती है। इसको चैक किया जाए ताकि लोगों को

बार्डर्ज पर कोई परे ाानी न हो। मै एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि स्वयं मुख्य मंत्री जी जा कर देखें कि नजफगढ़ की मंड़ी में कितनी रौनक है लेकिन गुड़गांव बहादुरगढ़ और फरीदाबाद की मड़िया बि लोगों को बार्डर्ज पर कोई परे ाानी न हो। मै एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि स्वयं मुख्य मंत्री जी जा कर देखें कि नजफगढ़ की मंड़ी में कितनी रौनक है लेकिन गुड़गांव बहादुरगढ़ और फरीदाबाद की मड़िया बिल्कुल सुनसान पड़ी है क्योंकि वहां पर मार्किट फीस भी ज्यादा है और सेल्ज टैक्स भी चार परसैट है लेकिन दिल्ली के अन्दर सेल्ज टैक्स नही है इसलिए नफजगढ़ की मंड़ी में ज्यादा रौनक है। मै सरकार प्रार्थना करूंगा कि जैसे सरकार न चने पर सेल्ज टैक्स दो परसैट से घटा कर एक परसैंट किया है उसी तरह से गेहूं और दूसरे अनाज पर भी सेल्ज टैक्स कम किया जाए मै तो यह कहता हूं कि अनाज पर सेल्ज टैक्स बिल्कुल खत्म किया जाए। यदि हरियाणा सरकार अनाज पर सैल्ज टैक्स बिल्कुल समाप्त कर दे तो उन गुडगांव और फरीदाबाद की दोनों मांडियों में दोबारा रौनक या सकती है और उन माड़ियों में अनाज की ज्यादा बिकी से सरकार को मार्टिक फीस से भी रेवेन्यू का लाभ हो सकता है। इसके अलावा मै एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदे ा के अन्दर एक नया टैक्स लगया जा रहा है जोकि टील टैक्स है। इस बारे में सरकार एक बिल भी पे ा करने जा रही है। इस टोल टैक्स के बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो ट्रक दूसरे प्रान्तों से रजिस्टर्ड है वे अगर हरियाणा के अन्दर खाली आते है

तो उन पर टोल टैक्स न लगाया जाए यानि ट्रकों के खाली आने जाने पर टोल टैक्स नही लगाया जाना चाहिए क्योंकि गुड़गांव और बहुदरगढ़ दिल्ली के नजदीक होने के कारण बहुत से ट्रक ड्राइवर्ज अपना खाली ट्रक राम के समय गुड़गांव और बहादुगढ़ में खड़ा करतै है और वहां से खाली ट्रक ले कर जाते है लेकिन उन पर टोल टैक्स लगा दिया जाता है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि खाली ट्रक पर सामान लदा हो तो उस पर टोल टैक्स लगे लेकिन खाली ट्रक पर टोल लगाया जाएगा तो यह उन ट्रक ड्राइवर्ज के साथ ज्यादती होगों। उसे अलावा मै यह भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी ट्रक पर कोई खाद्यान्न या बच्चों की पुस्तकें और स्टे ानरी का सामान लदा हो तो उस पर भी टोल टैक्स नही लगाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं नगरपालिकाओं के बारे में कहना चाहूंगा। नगर पालिकाओं के लिए गान्ट का जो प्रोविजन रखा गया है वह कम है। सरकार बजट का 71 परसैन्ट पैसा गांव के अन्दर खर्च करने के लिए रख रही है यह बहुत अच्छी बात है ताकि गांव का विकास हो जब तक गांवों का विकास नही होना तब तक भाहरों की भी उन्नति नही हो सकती लेकिन इस बारे में मेरा निवेदन है कि सरकार को नगरों के लिए कम से कम 25 प्रति ात पैसा रखना चाहिए ताकि भाहरों का अच्छी प्रकार से विकास हो सके। खासकर उन नगरपालिकाओं की तरफ वि ोश ध्यान दिया जाये जहां पर स्मल अधिक है। आजकल हर भाहर के

चारों तरफ उन अप्रुवड कालोनियां बस गई है। इन अनएप्रवड कालोनियों में न पानी के पानी की व्यवस्था है और न गन्दे पानी की निकासी का ही कोई प्रबन्ध है। न वहां पर सड़के है और नही बिजली की ठीक व्यवस्था है। वहां पर किसी प्रकार की सुविधा न होने की वजह से लोगों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो अन–एग्रुवड कालोनियां बन गई है उनमें अब मकान बनाने के लिए नक ो पास होने चाहिए इसलिए सरकार की इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए वहां पर 25 प्रति ात पैसा खर्च करना चाहिए। सरकार कई सालों से एक वाटर सीवरेज बोर्ड बनाने की सोच रही है लेकिन वह भी अभी तक नही बनाया गया है। इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह बोर्ड भीघ्र से भीघ्र बनाया जाये। इस बारे में मेरा सरकार को एक सुझाव यह भी है कि जैसे दे ी भाराब और अग्रजी भाराब की बिकने वाली बोतलों पर एक रूपया और दो रूपये नगरपालिकाओं को और पंचायतों को दिया जाता है। उसी प्रकार से बीयर पर भी यह अतिरिक्त पैसा लगाया जाये क्योकि बीयर काफी मात्रा में बिकती है जितनी अधिक बीयर बिकेगी उतना अधिक पैसा सरकार को आएगा और उससे ग्रामो का और भाहरों का नगरपालिकाओं का ठीक प्रकार से विकास हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय आप किसी भी गांव में चले जाए, आप गांव में घुस नही सकते क्योंकि चारो तरफ पानी खड़ा रहता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि गांवों के पानी की निकासी की तरफ वि ोश ध्यान दिया जाये और जब तक इस पानी की

निकासी की व्यवस्था ठीक प्रकार से नही हो सकेगी तब तक गांवों का विकास नही हो सकता। इसलिए सरकार को इस बात को प्रायरिटी बैसिज पर लेना चाहिए तभी गावों का विकास हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मै गृह विभाग के बारे में कहना चाहता हूं । यह विभाग के लिए पिछले वर्श 46 करोड़ रूपये खर्च हुए है और अगले साल इस योजना के तहत 112 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे है। हाउस में हमारे एक मित्र ने बोलते हुए मण्डल और कमण्ड की चर्चा करते हुए कहा की जब अडवानी जी की रथ यात्रा हरियाणा में आई तो हमारी पुलिस ने बडी मुस्तैदी के साथ काम किया क्योंकि बी0 जे0 पी0 वाले तो इस रथ यात्रा के बहाने साम्प्रदायिक दंगे करवाना चाहते थे बड़ी मुस्तैदी क साथ काम करते हुए ऐसा नही होने दिया। इसी बारे में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मण्डल आयोग रिपोर्ट लागू होने की वजह से सारे दे ा में और खासकर अपने प्रदे ा में आग लग रही थी तो उस वक्त पुलिस क्या देख रही थी और सरकार क्या कर रही थी? इतना ही नही सरकारी अधिकारियों पर हमले हो रहे थे, राजनीतिक लोगों पर हमले हो रहे थे, तब यहां की पुलिस क्या कर रही थी। उस समय पुलिस का प्रबन्ध कहां चल गया था? आज लोगों की जमीन पर नाजायज कब्जे किए जा रहे है लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कदम नही उठाये जाते। गुड़गाव के अन्दर एक ग्रीन ब्रिगेड नाम से दल बना हुआ है वह दल जबर्दस्ती

कब्जा कर लेता है। मै पूछना चाहता हूं कि गृह विभाग के लिए जो पैसा बढ़ाया जा रहा है उसका क्या उपयोग होगा? आजकल डीजल की वैसे ही काफी कमी है लेकिन जब भी कोई सरकारी रैली करनी हो तेा इधर उधर से ट्रकों को जबर्दस्ती रैली में भेजा जाता है। हिसार में रैली करनी हो तो ट्रक गुड़गांव से जाएंगे या सिरसा में रैली हो तो ट्रक गुड़गांव से जाएंगे। इतना ही नही गुड़गांव के साथ एक और मुसीबत बनी हुई है वहां पर भौडसी में कभी रात के 11 बजे प्राईमिनिस्टर साहब आते है और सुबह 7 बजे चले जाते है कभी 2 बजे आते है तो कभी 5 बजे आते है लेकिन जब भी हम किसी काम के लिये एस0 पी0 डी0 एस0 पी0 या इन्सपैक्टर की टेलीफोन पर पूछतें है तो जवाब मिलता है कि प्राईमिनिस्टर साहब के पास गए हुए है। जब भी मै किसी पुलिस अधिकारी का पता करवाता हूं तो हमे ाा यही जवाब मिलता है। कोई पुलिस अधिकारी थाने में मौजूद नही होता। वे सब उनके आने की वजह से नही मिलते क्योंकि वे उनकी सुरक्षा में लगे होते है। (विघ्न)

श्री आत्मा राम गोदाराः आन ए प्यायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय इनको वहां पर प्राईमिनिस्टर साहब के आने पर भी ऐतराज हो रहा है क्या उन पर ये लोग पाबन्दी लगवाना चाहते है। यहां पर ये प्रधान मंत्री क कहां से रैफरेस ले आए

श्री सीता राम सिंगलाः उपाध्यक्ष महोदय, मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय प्राईस मिनिस्टर जी के आने पर

मुझे बिल्कुल ऐतराज नही है वे आएं। उनकी सिक्योरिटी भी आव यक है क्योंकि प्राईम मिनिस्टर सारे राश्ट्र का नेता होता है और उन्हे पूरी सिक्योरिटी दी जानी चाहिए लेकिन इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि प्राईम मिनिस्टर जी के लिए सिक्योंरिटी स्टाफ अलग रखना चाहिए। सिटी पुलिस थाने में पुलिस के वरिश्ठ अधिकारियों का उपलब्ध होना आव यक है। जब कोई काण्ड हो जाता है और थाने टेलीफोन करते है या जाते है तो कोई पुलिस अधिकारी वहां नही मिलता। एस0 पी0 साहब को पूछते है तो कहते है कि प्राईस मिनिस्टर आ रहे है वहां गये है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदे ा में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है उनको देखते हुए पुलिस अधिकारियों का वहां पर उपलब्ध होना आव यक है। हरियाणा में कितने ही काण्ड ऐसे हो चुके है जिनसे लोगों का पुलिस पर से वि वास उठ गया है। हरियाणा मे कोसली काण्ड हुआ, गोहाना काण्ड भरोसा नही रहा। पुलिस की भर्ती में धांधलिया हुई। रेस्ट हाउस में मंत्री आवजे लगा रहे थे कि 30 हजार रूपये दो और कान्स्टेबल भर्ती करवाओ/(ाोर एवं व्यवधान) भार्तियों के मामले में जो भ्रश्टाचार चौधरी भजन लाल के जमाने में होता था इस सरकार ने तो उससे भी ज्यादा भ्रश्टाचार फैलाया है। पैसे ले कर जब पुलिस की भर्तियों की गई तो फिर पुलिस पर कैसे भरोसा किया जायेगा?

श्री उपाध्यक्षः सिगला साहब, अब वाईड–अप करियें।

श्री सीता राम सिंगलाः मै वाईड–अप कर रहा हूं। उपध्यक्ष महोदय, मै यह कह रहा था कि पुलिस को भर्ती में भ्रश्टाचार हुआ। (विघ्न) मेरा निवेदन है कि मेरे मित्रों का आलोचना भी सुननी चाहिए। यह हकीकत है कि 30–30 हजार रूपये ले कर पुलिस में भर्तियों की गई। (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः यह सरकार गलत है।

श्री सीता राम सिंगलाः यह बात मै नही कह रहा बल्कि राश्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में भी छपी है। आज सारे दे ा के अन्दर चर्चा ही रही है कि किस तरह नाजायज कब्जे हो रहे है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे है यानि कानून और व्यवस्था की स्थिति सारे प्रदे ा में बहुत ही खराब है।

श्री उपाध्यक्षः सिंगला साहब, अब आप बैठे।

श्री सीता राम सिंगलाः उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है जो आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री रणसिंह मान (बाढड़ा): अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को इस महान सदन में प्रदे ा के वित्त मंत्री चौधरी तैयब हुसैन जो न बजट अनुमान पे ा किये है। मैने का सम्मनित मैम्बर इसको पढ़ कर यही कहेगा कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट अनुमान पे ा किए है। उसमें यह साबित हो गया है कि सरकार का दोहातों के विकास का नारा एकदम खोखला है। राज्यपाल महोदय के अभिभाशण के वक्त आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने यह आ वासन

दिया था कि उनकी सरकार किसी भी क्षेत्र के लोगों को अपेक्षा करने की मन ाा नहीं रखती। अगर हकीकत में ऐसा होता तो यह बहुत अच्छा होता। मै तो उनके क्षेत्र के बिल्कुल निकट और उनके जिले का रहने वाला हूं। अगर ईमानदारी से उनकी यह मन ाा होती तो मै उनकी मन ाा की कद्र करता और उनको मुबारकबाद देता लेकिन हकीकत कुछ और है। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के बिकास के नाम पर बहुत थोड़े से पैसे का प्रोवीजन किया गया है। मै खुद गांव से ताल्लुक रखता हूं और आप भी गांवों में जाते ही रहते है। आपके चुनाव क्षेत्र में भी तकरीबन गांव लगते है और मुहल्ले भी इस तरह के है। जिनके अन्दर सफाई का उचित प्रबन्ध नही है। सड़को के पास गन्दा पानी इकट्ठा हो जाता है। विकास तो तभी होता है जब गालियां पक्की हों, नालिया हो, गांवो में प ा डिस्पेसरिया हो, अस्पताल हो, नये स्कूलों की बिलिडगें हो और जो है वे भी ठीक हालत हो उपाध्यक्ष महोदय सडको के लिए 2 करोड़ 60 लाख रूपया रखा गया है। क्या इतने थोड़े पैसे से सरकार की देहाती के विकास की मन ाा पूरी हो सकेगी?

विकास का यह सिस्टम है, यह इतना फाल्टी है कि इसके अन्दर यूटेलाईजे ान सर्टीफिकेट आने के बाद ही डिपार्टमैंट किसी ब्लाक को पैसा देता है। यह तय है कि हरियाणा जैसे छोटे से प्रदे ा में जहां पर प्र ाासन का इतना ज्यादा राजनीतिकरण हो चुका है, वहां पर प्र ाासन के ऊपर जो आका बैठे है, उनके इ ाारे के बर्गर कुछ नही होता। ब्लाक का जो बी0 डी0 ओ0

होता है, स्पैि ायली वह उन हल्को के यूटेलाईजे ान सर्टीफिकेट्स नही भेजता जिन हल्कों का प्रतिनिधित्व विपक्ष के विधायक करते है। मै यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो यह कहा है हम विकास के मामले में किसी भी तरह की दलगत भावना रही रखती है, हम भेदभाव नही रखते है। यह गलत बात है। मै चैलैज करता हूं कि जब से मुख्य मंत्री बने है, वे चैक करा लें। उनके नाक के नीचे वाडड़ा हुल्का आता है। उनका अपना जिला है। वहां पर एक पैसा भी नही लगा है अलबत्ता जो विकास कार्य पहली सरकार के समय पर वहां पर हो रहे थे वह भी अब बन्द हो चुके है। किसी काम के लिये भी एक पैसा खर्च करने का प्रावधान नही है। मैचिग ग्रान्ट स्कीम सरकार ने भुरू की। मै भी उस स्कीम का बहुत बड़ा हिमायती था। हरियाणा के जो आदमी बाहर बसे हुए है और अपने बाप–दादा के नाम पर कुछ करना चाहते हे, इनको कार्यो से उनकी धक्का पहुंचा है। मै अपने हल्के का उदाहरण देकर बात को स्पश्ट करना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर अगर किसी भी चुनाव क्षेत्र में इस मद में सबसे ज्यादा नालायक बी0 डी0 ओ0 लगा रखा है। जब से वह वहां पर लगा है, आप देख लीजिये वहां पर मैचिंग ग्रान्ट मद का एक पैसा भी खर्च नही किया गया है। कोई ऐसा काम नही किया गया जिसमें मौचिंग ग्रान्ट का पैसा खर्च किया जा सके जबकि सबसे ज्यादा पैसा हमारे यहां पर जमा है। यह न केवल लोगों क साथ मजाक है बल्कि सरकार की घोशित नीति क मुताबिक नही है। यह केवल राजनीतिक दुर्भावना की वजह से

किया जा रहा है कि इस स्कीम का पैसा वहां पर खर्च नही किया जा रहा है। इतनी अच्छी यह एक स्कीम थी कि इसको लागू करके लोगों का नामकरण की सुविधा दी जानी चाहिये। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि दूसरे अधिकारी ऐसे कामों में रूचि ले। जन भावना की ऐसी जो थोड़ी–बहुत स्कीमों है, उनके अन्दर जो थोड़ी–बहुत अर्टचमैंट लोगों की बनी हुई है, उसको बड़े पैमाने पर गांवो में, कस्बों में और भाहरों में लागू किया जाये तभीह जनता को इसका कोई फायदा हो सकता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नही हो पाया है। इसके अलावा, मै एक बात की और इसका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरी बात की फाइनैस मिनिस्टर से पहले जगन नाथ जी ही पहुंचा देंगे। मै उन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब वे हरियाणा के पंचायत तथा विकास मंत्री थे, उस समय आपने उस समय के मुख्य मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था कि पंचायतों की सम्पति को किस तरह से एक–एक योजना बद्ध तरीके से खुद–बुर्द किया जा रहा है। इसका अनुमान उदाहरण दिल्ली के आस–पास के इलाके है वि ोश तौर पर फरीदाबाद और गुड़गांव के इलाके है। जब यह पंचायत तथा डिवैल्पमैंट मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय चौधरी देवी लाल जी ाके इस संदर्भ में एक लैटर लिखा था। उसमें उन्होंने स्पश्ट किया था कि खास तौर पर फरीदाबाद और गुड़गाव जिलों में जो अधिकारी है, जो जिम्मेवार अधिकारी है, वह अपने राजनैतिक आकाओं को खु ा करने के लिये ऐसा कर रहे है। उसमें उन्हौने यह भी

लिखा है कि फलां–फलां गांव से इस तरह से जमीन को हड़प लिया गय है। बड़ी सीरियस बात है। मुख्य मंत्री जी के नोटिस में यह बात लायी जानी चाहिए। मास्टर हुक्म सिंह जी ने जब वह पंचायत एंड डिवैल्पमैंट मिनिस्टर थे, तब उन्होंने यह लैटर लिखा था। मै यह जानना चाहूंगा कि क्या उस पत्र में जो उन्होंने स्वयं पंचायत एंड डिवैल्पमैंट मिनिस्टर रहते हुए मुख्य मंत्री जी को लिखा था, में लगाये गये आरोपी एंड डिवैल्पमैंट मिनिस्टर रहते हुए मुख्य मंत्री जी को लिखा था, मे लगाये गये आरोपी के बारे में कार्यवाही कर ली गयी है? क्या उसमें इन्वाल्वड अधिकारियों के खिलाफ या जिनके इ ाारे पर ऐसा किया गया था, कोई कार्यवाही हो गयी है, या नही? जिन आकाओं के कहने पर उन अधिकारियों ने यह गलत काम किया था, पंचायत की गुड़गांवा और फरीदाबाद की सम्पत्ति को खुर्द बुर्द करने की कोि ा ा की गयी थी, क्या बअ वह छुड़ा ली गयी है?

16.00 बजे

अपाध्यक्ष महोदय, मै बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं और वित्त मंत्री तथा मुख्या मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। वे इनका सदन में स्पश्टीकरण करें। उपाध्यक्ष महोदय, मै एक बात कहना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए इस सदन की एक माननीय सदस्या जब वे ि ाक्षा मंत्री थी, श्रीमति सुशमा स्वराज तो उन्होने एक उदाहरण पे ा किया था। उन्होंनें इस सदन में एक कमिटमैंट की थी कि वे किसी भी भेद

भाव के बिना स्कूलों को अपग्रेड करेगी और उन्होंने वास्तव में इस पर अमल किया। हमारे मुख्य मंत्री जी ने बार–बार यह कहा कि स्कूलों के अपग्रेड ान नही किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी बात नही है। इसमे भेदभाव बरता जाता है और खास तौर पर जहां से विपक्ष के सदस्य आते है। वहां पर सरकार ने अपना संकुचित दृश्टिकोण अपनाया है लेकिन श्रीमति सुशमा स्वराज ने ऐसा नही किया था उपाध्यक्ष महोदय, नौरंगाबाद जाटान मेरी कांस्टीचुऐंसी में और मुख्य मंत्री के उप मण्डल में एक गांव है। वहां पर कोई स्कूल नही है। कोई भी हाई स्कूल उस इलाके में ऐसा नही है जो इस गांव से नौ किलोमीटर से कम हो वहां के बच्चे नौ किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाते है। अगर थोड़ा सी स्कूल को अपग्रेड करने का काइटेरिया हो, कोई भेदभाव न हो तो ऐसी कोई बात नही हो सकती कि बच्चों को नौ किलोमीटर पढ़ने के लिए जाना पड़े। सुशमा स्वराज की जो कमिटमैंट किया था। मै मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता चाहता हूं कि वे अपने वायदे को ध्यान में रखें और जो भी स्कूल अपग्रेड किए जाएं वे किसी भेदभाव के अपग्रेड किए जाए चाहे वह मेरा हल्का हो और चाहे किसी और का हो। कम से कम बीस प्रति ात स्कूल जन सेवा और विद्यार्थियों की सुविधा को देखकर अपग्रेड होना चाहिए। संकुचित विचार धारा से स्कूल अपग्रेड नही होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, सिंगला साहब ने उद्योगों के बारे में जिक्र किया। राजस्व का जो सब से बड़ा स्त्रोत है वह आज के मौडर्न युग में इंडस्ट्री से बड़ा कोई नही है। बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने उद्योग

नीति इस ढंग से तैयार की है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग उद्योग लगाने के लिये आकर्शित हो। उपाध्यक्ष महोदय, इसके हरियाणा इस वक्त बहुत बड़ा पोटैि ायल था। इसका कारण यह था कि आज पंजाब की हालत खराब है। वहां की स्थिति असामान्य है। वहां पर उद्योग विकसित नही कर रहे है। दूसरी तरफ आसमान है। वहा पर हालात बिगड़े हुए है। उपाध्यक्ष महोदय, आसाम में अधिकां ा उद्योग या व्यापार हरियाणवी लोगों के हाथ में है और वे चाहते थे कि यहां आकर उद्योग लगाएं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि टोटल ऐटमासफेयर बदल गया। यहां पर एच0 एस0 सी0 और एच0 एस0 आई0 डी0 सी0 बहुत अच्छी संस्थाएं है। उनमें बड़े अच्छे ओफ्ीसर्ज है और वे बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे है। लेकिन यहां पर जो राजनैतिक माहौला है और जो सामाजिक माहौला है यह इस तरह का है कि हम दूसरे प्रवे ाों के बिगड़े हुए हालात का फायदा न उठा पाए। बल्कि हुआ यह कि जो यहां पर उद्योग लगे हुए थे उन्होंने अपना मन बना लिया कि वे यहां से जा रहे है और इस तरह से न्योडा में ज्यादा उद्योग लग रहे है। उपाध्यक्ष महोदय, एल0 एम0 एस0 तक आगेनाईजे ान है। इसका पूरा नाम लूटमार सगठन है। गुड़गांव और फरीदाबाद में इस लूटमार संगठन ने यह हालत पैदा की हुई कि चाहे बाढ़ राहत फण्ड हो, चाहे कोई फण्ड हो वे वैसा लेने से नही चुकते। कोई रैली फण्ड हो कोई सूखा राहत फण्ड हो, कन्यादान फण्ड हो और चाहे कई भी फण्ड हो वे पैसा लेने से नही चूकते। वे कोई मौका अपने हाथ से नही जाने देते। वे ऐसे

मौके पर भाादी करेंगी कि जब फण्ड की भाक्ल में पैसा लिया जा सके। वे कोई मौका नही छोड़ते किसी न किसी बहाने से वे पैसा न ले। अपाध्यक्ष महोदय, जन सन्दे ा ने अखबार की ऐडवरटाइजमैट से इतन पैदा इक्ट्ठा किया है कि बात की जांच अगर कोई आयोग कर तो जनता के सामने यह तथ्य आ जाएगा कि अगर पचास साल तक एक पैसा भी एडवरटाइजमैंट के तौर पर या किसी तरह न आए तब भी यह पेपर चल सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह लूटमार नही तो क्या है? सरकार को जनता की सेवा के प्रति गम्भीर होना चाहिए। यह एक नार्मल बात है। जनता ने इस चीज को बार बार सावित किया है कि पावर में रहते हुए और पावर का दुरूपयोग करके न तो आप पेपर चल सकते हो और न ही संगठन। चाहे वह ग्रीन बिग्रेड ही या लूटमार संगठन, आप उसकी किसी चुनौती के टाईम के लिए या ऐसे टाईम के लिए जब किसी राजनैतिक दल को उस संगठन का इस्तेमाल करने के लिए जरूरत हो, खड़ा नही कर सकते। लेकिन भारत जैसे दे ा में यह संभव नही है। यह सरकार धोखा खायेगी और हरियाणा प्रदे ा 20 साल पीछे पिछड़ा जाएगा। इसलिये मेरी वित्तमंत्री महोदय से यह रिकवैस्ट है कि राज्य के अन्दर उद्योगी वातावरण को इस कदर ठीक करें कि जो लोगों हरियाणा में उद्योग स्थापित करना चाहते है, वे यहां पर खु ाी से अपने आप अपना उद्योग लगाएं। इससे उद्योग स्थापित करना चाहते है, वे यहां पर खु ाी से अपने आप अपना उद्योग लगाएं। इससे उद्योगों को भी बढ़ाया मिलेगा। ऐसे उद्योगपतियों को जो यहां हरियाणा के अन्दर उद्योग लगाना

चाहते है, पुरी तरह से सहलियतें दी जाएं इससे सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी। अगर इस से सरकार की आमदनी नहीं बढेगी तो मै। (ाोर एवं व्यवधान) लेकिन डिजनी लैण्ड से आमदनी लेने के लिये सरकार को इतने निराले आकर्शक नमूने रखने पड़ेगे ताकि दे ा और प्रदे ा के लोग वहां आएं और उनके प्रति आकर्शित हो। वे वहा आंएगे तो सरकार को कर की वसूली होगी और सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी।

श्री उपाध्यक्षः मान साहब, आप जरा समय का ध्यान रखें और बजट पर ही रहियेगा।

श्री रणसिंह मानः ठीक है जी। जहां तक कानून और व्यवस्था की बात है इस बारे में यहां बड़े जोर भाोर से कहा गया है कि हरियाणा के अन्दर कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। मै एक वि ोश बात की और आपका ध्यान दिलाना चाहूता हूं कि वे जी दो पुलिस के आदमी राजसिंह और प्रेम सिंह दिल्ली मे पकड़े गए इससे एक बात सामने आती है (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मान साहब, आप कृपया बजट पर ही बोलियेगा।

श्री रणसिंह मानः उपध्यक्ष महोदय, मै यह कहना चाह रहा था कि होम का जो 1987.88 का बजट था 46 करोड़ से बढ़ाकर अब 112 करोड़ा का होने जा रहा है ऐसी अनुमति है

लेकिन जो क्वालिटी और कैपेबिलिटी इन पुलिस फोर्सिज में होनी चाहिए वह नही है। अगर इसी तरह का वातावरण इस हरियाणा प्रदे ा का रहा कि पुलिस फोर्सिज की राजनैतिक लोग अपने स्वार्थी के लिये प्रयोग करते रहे, या फिर किसी रैलियों बगैरह में चाहे कोई महम की रैली हो, या फिर कही से चन्दा बटोरने की बात हो, ऐसे कामों के लिये प्रयोग में लाते रहे तो पुलिस कोर्सिज में डिस्पिलिन नहीं रहेगा जबकि पुलिस फोर्सिज में डिस्पिलिन और कैपेबिलिटीज का होना अत्यन्त अनिवार्य है। आगे से ऐसे कामों के कारण वे लोग आगे नहीं आएंगे। ये दो आदमी राजसिंह व प्रेम सिंह जी पकड़े गये है हो सकता है कि उनकी इनवाल्वमैन्ट कही न भी हो लेकिन इस सारी बातों का असर तो उन पर अव य ही पड़ेगा ओर आगे के लिये सी0 आई0 डी0 के आफिसर कोई लिखित आदे ा तो किसी को नही देंगे। ऊपर वाला अफसर नीचे वाले को कहेगा और नीचे वाला उस से आगे नीचे कह देगा कि आपकी अमुक अमुक जगहों पर यह यह ड्यूटीज है और यदि आगे से कोई जैनुअन ड्यूटी आई और सवेलैन्स स्टेट के हित में हुआ तो वे लोग, वे कर्मचारी जिनको ऊपर के अफसरों ने और राजनैतिक नेताओं ने नकार दिया कैसे अपनी डयूटी के प्रति ईमानदारी से काम करेंगे? वे हमे ाा कोताही बरतेंगे। उन में इनडिस्पिलिन आएगा और अपनी जोब के प्रति जो उनकी कमिटमैंट है, उनका कया ह ार होगा? इसलिये मै वित्त महोदय ये यह कहूंगा कि वे होममिनिस्टर साहब से इस बारे में बात करें और इस सदन को बताए कि किस तरह से हरियाणा की जो

पुलिस फोर्स है, वह हरियाणावी जनता के हितों की रक्षा करो के लिए और कानून और व्यवस्था को बहाल रखने के लिये कामयाब रहेगी?

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मै कोलोनाइजे ान से संबंधित कुछ बातें रखना चाहता हूं। इस विभाग के बारे में हम यहां पर बहुत कुछ सुन चुके है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है लेकिन एक बात स्पश्ट है कि दिल्ली के नजदीक के भाहरों में जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है और जिस तरह से जमीन के ऊपर प्रीमीयम है, उसमें प्रोत्साहित होकर इन्होंने यह काम किया है। मेरी तजबीज यह है कि दिल्ली से 50 किलोमीटर के दायरे में हुड्डा जिस तरह की नीति तैयार करना चाहे करे लेकिन जो दोहात सब डिवीजनल लैवल से या जिला हैडक्वार्टर से दूर पड़ते है उनके लिए सरकार को ज्यादा सुनि चत फार्मूला बनाना चाहिए ताकि जो स्लमं फरीदाबाद जैसे भाहरों में हो गया है वह वहां न हो। गांवों में चाहे हाउसिंग कोआप्रेटिव सोसइटीज बनाई जाएं या एम्पलाइज की सोसाइटीज बनाई बाएं लेकिन जहां पर जमीन का प्रीमियम न के बराबर है वहां पर प्राइवेट क्लोनाइर्ज की जमीन डिवैल्प करने के लिये दी जाए। उनको एक अच्छी योजना के तहत उसे डिवैल्प करने के लिये कहा जाए। यानी वहां पर स्कूल और पार्क वगैरह की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि देहात में जिनकी थोड़ी आमदन है या कोई बर्किंग क्लास का आदमी है उसको भाहर मे बसने की योजना होती है। अगर वही ठीक तरह

से व्यवस्था होगी तो वह बड़े भाहरों में भागने की बजाए वही ठहरेगा और इस प्रकार से वहां पर स्लम भी नही होगा। अन्त में डिप्टी स्पीकर साहब, मै वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो बजट अनुमान उन्होंने पे ा किए है, उसके बारे में वि ोश करके जो बातें मैने उनके सामने रखी है वे उनकी तरफ ध्यान दें। जो सामुदायिक विकास के लिए पैसा है कम से कम उसको जरूर बढ़ाने के कश्ट करें। हरियाणा के लोगों की इससे बहुत उम्मीद बंधी थी। उनके स्वप्न तब पूरे हो पांएगे जब व्यवहारिक रूप में पैसा देहात में जाएगा। बाकी जो बाते मैने कही है। वे मनुश्य मंत्री जी और होम मिनिस्टर के नोटिस में वित्त मंत्री जी लाएं और उनका उत्तर दे। धन्यवाद।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा चल रही है। मेरे माननीय साथियों ने बड़े अच्छे ढंग से सरकार की आलोचना की। (विघ्न) उपलब्धियों की बात का अभी जिक्र आया है। मेरे साथी श्री रण सिंह मान जी ने काफी लंबी चुप्पी के बाद चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बन्धुवापन की जंजीर को तोड़ कर आज काफी देर के बाद हिम्मत की है। उनको मै हदय से बधाई देता हूं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मान साहब ने बजट परजो कहा मै उसी पर बोल रहा हूं। उन्होंने गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ दी है। (ाोर एवं विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इनको ये भाब्द वापिस लेने चाहिए।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः ठीक है जी मै वापिस ले लेता हूं।

श्री उपाध्यक्षः महेन्द्र प्रताप जी, आप बजट पर ही बीलें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा चल रही है और बजट पर बोलते हुए मेरे साथी श्री सीता राम सिंगला ने जहा और बातें कहीं है उसके साथ साथ उन्होने ये भी कहा है कि अगर इस बजट को गौर से पढ़ा जाए तो यह बजट कांग्रेस पद्धति पर आधारित दिखाई देता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में जो भी प्रावधान किया गया है भाायद वह यह बजट कांग्रेस पद्धति पर आधारित होने के कारण किया गया है। सिंगला साहब ने पता नही किस भाव में कहा लेकिन उन्हें यह बात भी मालूम होनी चाहिए कि विकास की दृश्टि से हरियाणा प्रदे ा का नाम दे ा के नक्े ा पर दो नम्बर पर आता है। हरियाणा प्रदे ा ने विकास के मामले में कांग्रेस के समय भें जो कीर्तिमान स्थापित किया है वह दे ा के लिए आद र्ा बना है। यह बात किसी से छिनी हुई नहीं हैं। इस बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नही है यह बात सभी भली भांति जानते है। (ाोर) उपाध्यक्ष महोदय, अगर बजट को गहराई से पड़ा तो यह केवल दो बैसाखियों पर खड़ा नजर आता है और अब ये दो बैसाखियां भी बहुत जर्जर हो चुका है, इनका घुन लग चुका है और जंग लग चुका है। ये दो बैसाखियों है कर्जा मांफी और वृद्धावस्था पैन् ान। कर्जा माफी बात का जहां तक सवाल है उस बारे में जो ये जनता

से वायदा करके आए थे और जो कुछ इन्होंने अब तक किया है उसको दोहराने की आव यकता नही है क्योंकि इस बारे में सारी जनता जानती है कि यह वायदा पूरा नही हुआ है। इस तरह से बृद्धावस्था पैन् ान की बात है इसको भी ये आज तक ठीक प्रकार से लागू नही कर सके है जिससे कि लोगों की ठीक समय पर यह पैन् ान मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, बजट में 95 करोड़ रूपये का घाटा दिखाया गया है और अगले बजट के लिए 765 करोड़ रूपये की रा ि ा रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, मै सबसे पहले 1986–87 में जो बजट पे ा हुआ था उस बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं 1986–87 के बजट को आज तकरीबन 5 साल होने जा रहे है। उस साल काउ बजट भ्रुरू में 525 करोड़ रूपये का था लेकिन बाद में सरकार ने अपने साधन जूटा करके और प्रदे ा के विकास और प्रगति को ध्यान में रखते हुए इतनी चुस्ती के साथ काम किया कि उस सालके बजट को 565 करोड़ रूपये तक पहुंचाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो प्रस्ताविक बजट था उससे ज्यादा पैसा उस साल के बजट में सरकार ने अपने साधन जूटा करके खर्च किया और बजट को यहां तक ले गए (विघ्न) यह उससमय की बात है जब चौधरी बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद 1988–89 यानि दो साल बाद बजट को 550 करोड़ रूपये तक ले गए और बाद में 1989–90 में इसको 676 करोड़ रूपये तक ले गए। अब यहां पर मै स्पश्ट करना चाहूंगा कि 1989–90 में भ्रुरू में बजट में प्रोविजन तो 676 करोड़ रूपये कर किया था लेकिन बाद में इस घटा कर 570 करोड़

रूपये तक ले आये। इसी प्रकार से 1990–91 मे बजट को प्रोविजन तो 700 करोड़ रूपये का रख दिया लेकिन बाद में यह भी घटा कर 650 करोड़ तक ले आए। आज फिर जो बजट तैयब जी ने रहा है, इससे कुछ पुराने संस्कार जामें है और इस बजट को 765 करोड़ रूपये तक ले गए है लेकिन पिछले सालों को देखते हुए यह दिखाई नहीं देता कि ये साल खत्म होते इसको इतना रहने देंगे या नही क्योंकि बजट में पहले ही 95 करोड़ रूपये का घाटा है। इस घाटे की वजह से मुद्रास्फिती बढ़ेगी। अगर इनकी दो–तीन सालों की पुरानी परम्पराओं को देखा जाये तो इस साल भी फिर कम से कम 50–60 करोड़ रूपये का घाटा उठाना पड़ेगा। ये इसको कैसे पूरा करेंगे यह समझ नही आता। उपाध्यक्ष महोदय, ये यहां इस बजट को कर रहित बता रहे है। यह स्वाभाविक है कि जब चुनाव नजदीक आ रहे हो तो कोई भी सरकार टैक्स लगाने कर जोखिम नही उठाना चाहेगी क्योंकि उसको जनता के सामने जाना होता है। उनको अब टैक्स लगाने की जरूरत भी नही थी क्योंकि सरकार पहले ही 115 करोड़ रूपये के टैक्स लगा चुकी है। ये इस घाटे की पूर्ती कैसे इस बारे मै मुझे कोई रास्ता समझ नही आ रहा। यह जो घाटा है इसको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कर लगा कर या किसी अन्य तरीके से पूरा करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 765 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया हैै मुझे भांका है कि यह भी कम ही जाएगा। इसलिये यदि इस बजट को दि ाभ्रामक और नीरस बजट कहा जाए तो कोई गलत बात नही होगा। इस बजट

में योजना सहायता की भी सम्मिलित है। प्लानिंग कमी ान के एक माननीय मैम्बर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था हरियाणा के लिये की गई है। जो केन्द्रीय सहायता 200 करोड़ रूपये की मिलनी है उसको अगर इस बजट मे से निकाल दिया जाए तो यह बजट केवल साढ़े–पांच सौ करोड़ रूपय का ही रह जाता है। सरकार में अपने साधनों से करीब साढे पांच सौ करोड़ रूपयेही जुटाने है जब कि कांग्रेस ने जो बजट पे ा किया था वह भी करीब साढे–पांच सौ करोड़ा का ही था जिसमें 50–60 करोड़ की केन्द्रीय सहायता थी। यदि इसमें 10 प्रति ात मंहगाई का खर्च घटा भी दिया जाता है तो जो यह 765 करोड़ रूपये का बजट पे ा किया गया है यहा बहुत ही कम है जबकि कम से कम 1,000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान होना चाहिए था। इस प्रकार अगर इस प्रकार अगर इस बजट की दि ाा–हीन बजट कहा जाए तो कोई गलत नही होग। अध्यक्ष्य महोदय, जब 3–4 साल पहले यह सरकार आई थी और केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो यह कहा जाता था कि केन्द्र से हरियाणा को पूरा पैसा नही मिल रहा है, केन्द्रीय मदद नही मिल रही है। इसी प्रकार से एस0 वाई0 एल0 नहर के मामने में भी कहा जाता था कि कांग्रेस सरकार की मदद नही मिल रही है लेकिन अब तो वह सब बहाने भी खत्म हो गए है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब तो केन्द्र में भी सरकार इनकी है और हरियाणा में भी इनकी ही सरकार है। इसलिये अब इस प्रकार

के बहाने की भी कोई गुन्जाई ा नही रही है और अब तो यह इन्हीं की ही जिम्मेदारो बनती है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट में डिज्नीलैण्ड पर भी खर्च का प्रावधान किया है पिछले दिनों इस योजना के ऊपर इस दे ा में अखबारों के जरिये काफी भाोर और चर्चा रही तथा जनता ने रैलियां करके भी इसके खिलाऊ अपना रोव प्रकट किया। यह जमीन वास्तव में ऐसी है कि इसमें स्वतन्त्रता संवर्श का लहूं मिला हुआ है। यह एरिया स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वालों का एरिया रहा है जिस कारण लोगों का इस जमीन के साथ भावनात्मक रि ता जुड़ा हुआ है इतना रोव और भाोर होने के बावजूद भी सरकार इस योजना पर कार्य करने के लिए बजिद हैं उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सै ान में भी मैने सुझाव दिया था कि यदि इस योजना को लागू करना इतना ही जरूरी है तो जो पहाड़ो एरिया पड़ता है उसमे ंकाफी जगह है वहां पर सरकार को चाहे 10 हजार, 20 हजार या जितने एकड़ जमीन की आव यकता हो आसानी से मिल सकती है। जो जमीन इस कार्य के लिए एक्वायर की जा रही है वह या तो किसानों की जमीन है या फिर पंचायतों की जमीन है। यह जमीन किसानो की नही है यह कह कर में लोग जनता को गुमराह कर रहे है। (विघ्न) चौधरी सम्पत सिंह जी यह आदत तो आपकी हो रही है और इसका इलाज मेरे पास तो नही है, हां जनता जरूर इसका इलाज कर देगी। (विघ्न) सत्तापक्ष ने वहां पर नामी बेतामी जमीने खरीद रखी है। अपने स्वार्थ को दृश्टिगत रखते हुए ही इस योजना को कार्यन्वित करने हेतू इतना जोर दिया जा रहा है जो

कि बहुत ही भार्म की बात है लोकतन्त्र में सबसे बड़ा जनहित होता है। यह जमीन दे ाभक्तों की जमीन है। मै सस्कार से आग्रह करूंगा कि इस स्कीम पुर्नविचार किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, लोगों के विद्रोह और रोश के कारण इस का आकर 27 हजार एकड़ से घटा कर करीब 4 हजार एकड़ कर दिया गया है लेकिन अच्छा यह होता कि इस योजना को रोक दिया जाता। जब जब भी सरकार इसको छेड़ेगी तक तब सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा जिस सरकार ने भी इसका जिक्र किया वही सस्कार खत्म हो गई। यह उन लोगों को जमीन है जिन्होंने दे ा के लिये कुर्बानियां दी है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जी, आप केवल बजट पर ही बोले।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होग अगर इस खर्च को प्रवे ा के विकास की तरफ लगाया जायें। आज हरियाणा को ऐसी किसी योजना की जरूरत नही है। अब यहां पर विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे है, इस पैसे का एय्या ाों की तरफ खर्च करने की बजाये प्रदे ा में ऐसे लोगों की बहबूदी के लिये खर्च करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पुलिस की भर्ती के लिये इसमें जो 46 करोड़ रूपया रखा गया है और उनके रख–रखाव के लिये 142 करोड़ रूपया जो इस साल के बजट में रखा गया है उसका भी इसमें जिक्र आया है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदे ा में बिगड़ती हुई ला

एंड आर्डर की हालत, बिगड़ते और बढ़ते हुए आंकवाद और इसके अलावा जो इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है, उनको देखते हुए वह जरूरी है कि उसके लिये यह पैसा खर्च किया जाये। कर्मचारियों को सहूलियतें देने के लिये पैसे की जरूरत होती है। लेकिन यह पैसा जो हमसे मांगा जा रहा है, कही यह पैसा उन बेकार की चीजों के लिये खर्च न हो जैसे कि अभी पता चला है। दो सिपाहियों पर जिस प्रकार से पैसा खर्च हुआ है, कही इस तरह की कोई दूसरी ब्रिगेड बनाने के लिये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 3500 सिपाहियों की भर्ती का भी इसकमें जिक्र आया है। सिपाहियों की भर्ती का भी जिक्र किया था। चौधरी देवी लाल ने इसका जिक्र किया था कि हरियाणा के अन्दर पुलिस की भर्ती पैसे लेकर की गयी है। इस प्रकार की एक घटना तो मुझे याद है। पिछली बार जब पुलिस की सिपाहियों की भर्ती हुई तो एक नौजवान मेरे पास करैक्टर बैरीफिके ान के लिये फार्म अटैस्ट करवाने आया। उस समय तक भर्ती। हो चुकी थी। उस सब के मैडीकल भी हो चुके थे। जब मत उससे यह कहा कि भाई तुम कैसे पीछे रह गये, अब तो भर्ती है। तो वह कहने लगा कि आपसे अब क्या छुपाना। मैने 35000 रूपये दिये है। मै उसका नाम तो नही लेना चाहूंगा। लेकिन मै यह बात पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं।

प्रो0 सम्पत सिहः उपाध्यक्ष महोदय, मै यह कहना चाहता हूं कि एक नाम ही बता दे कि किसी ने पैसे लिये है। अगर कोई

एक सिगंल केस भी ही ता यह बता दे। हम उसके खिलाफ बाकयदा केस रजिस्टर भी करेंगै और उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे। (विघ्न एव भाोर)

डा0 रघुबीर सिंहः यदि हमने नाम दे दिए तो वे सारे हट जाएंगे। (ाोर)

Prof. Sampat Singh: Mr. Kadian, it was not recruitment in Confed. It was a police recruitment.

डा0 रघुबीर सिंहः आन ए प्वाग्रंट आफ आर्डर सर। मै आपके माध्यम से माननीय साथी से यह कहूंगा कि बड़ा ही जिम्मदाराना ओहदा इसके पास है और सरकार को यह चला रहे है। इस सरकार के चलाने में गरीब लोगों का पैसा खर्च होता है। पुलिस रिकूटमैंट के बारे में उन्होंने यह कहा कि यह रिक्रूटमैंट थी। सर, एफीडैबिट इस बारे में मौजूद है। अगर यह केस दर्ज करने तो कम से कम 8000 सिपाही तो हट जायेंगे।

प्रो0 सम्पत सिंहः आप प्रूफ लायै, हम बाकायदा केस रजिस्टर करेंगे। 8,000 हो नही चाहे कितने लोग हटैं अगर आप प्रूफ लेकर आयेगे तो हम बाकायदा केस रजिस्टर करेंगे। I again repeat that it was not recrutment in Confed It was a recruitment in the Police Department,

श्री उपाध्यक्षः महेन्द्र प्रताप जी, आप अपने टाईम का ध्यान रखे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय न जो कुछ कहा है, वह दूसरी बात है लेकिन मै जो कुछ कह रहा हूं वह पूरे यकीन और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। जो बात मेरे सामने हुई है वह मैने आपके सामने रख दी है। मै यह कहं रहा था कि ऐसा कोई न कोई मंच होना चाहिये जहां पर ऐसी बात क्लैरीफाई की जा सके जैसे कि मुख्य मंत्री महोदय ने पुलिस रिक्रूटमैंट के बारे में कहा था। मै उस आदमी का नाम नही देना चाहता। अगर मै उसका नाम दूंगा तो हो सकता है, उसकी नौकरी चली जाए और उसका पैसा भी वापिस न दे तो हो सकता है, उसकी नौकरी चली जाए और उसका पैसा भी ये वापिस न दे सके। (व्यवधान व भाोर) बहुत अच्छा मै आपको नाम भी बता दूंगा। अगर आप की नाम बताने से तसल्ली होती है, तो मै वह भी कर दूंगा। लेकिन मै एक बात जो कहना चाहता हूं वह यह है कि इसमें एक फीसदीह भी गुजाई ा नहीं है कि ऐसा नही हुआ है (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मुझे बोलते हुए 5–7 मिनट ही हुए होंगें।

श्री उपाध्यक्षः आपको बोलते हुए 20 मिनट हो चुके है। आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः मै कुछ सुझाव देकर समाप्त कर दूगा। मरी पार्टी का और मैम्बर इसमें हिस्सा नही लेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस में ि ाक्षा के लिये 36 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मै मंत्री महोदय से और खास तौर पर चौधरी तैयब

हुसैन जी से यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा में चाहे प्राइमरी स्कूलों की बात हो मिडल स्कूलो की बात हो, हाई स्कूलों की बात हो या 10 प्लस 2 स्कूलों की बात हो, ओर प्रदे ाों के मुकाबले ि ाक्षा के लिये जो संस्थाए है, वे काफी है। इसमे कोई दो राय नही और मेरा कहना यह है कि इनको और बढ़ावा दिया जाना चाहिये। लेकिन जो कभी मैने महसूस की है वह मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। यह सरकार जनता को कहती है कि हमने इतने स्कूल खोले है और इतने स्कूल अपग्रेड किए है लेकिन जब वहां पर बच्चों के लिये कोई कमरा न हो, कोई बैठने के लिये फ र्ा न हो तो उसका ज्यादा फायदा नही होता। उपाध्यक्ष महोदय, मैने खुद देखा है कि प्राइमरी स्कूल में एक–एक कमरा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अप कम्पैन चलाए जैसे कि कांग्रेस भाासन मे था कि हर गांव में सड़क और हर गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी (ाोर एव व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है और इन्होंने चार साल पहले इस बात को माना भी था। परा कहना यह है कि सब स्कूलों के लिये बिल्डिंग बनाई जाएं। इससे आगे मै खाद्य तथा अपूर्ति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः बस, आप आप बैठिए। आपका टाईम खत्म हो गया है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मै अपनी पार्टी की और से अकेला बोल रहा हूं मेरी पार्टी का कोई नही बोला है। (ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इनके समय में दो घंटे बिजली मिलती थी और अब 24 घंटे बिजली मिलती है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, जो बात अच्छी है उसको मै ऐप्री ि ाएट करूंगा और मैने हमे ाा किया है। उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य तथा आपूर्ति के मामले पर मैने एक मो ान दी थी और उसमें कहा था कि आटे की पोजी ान यह है कि आज आटा पांच रूपय किलो बिक रहा है और गरीब लोगों को बड़ी परे ाानी हो रही है। (ाोर एवं व्यवधान) मै यह कहना चाहता हूं कि जो डिपोज पर आटा जाता था वह दूसरे प्रदे ाो मै ब्लैक में बिकता रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये । इस संबंध में गुड़गांव का एक मामला मै सरकार के नोटिस में भी लाया था। वहां का जो डी0 एफ0 एस0 ओ0 था। उसने तीस रूपये बोरी के हिसाब से डिपो होल्डर्ज से सारे जिले में लिए। जब उसकी ि ाकायत मुख्य मंत्री जी से हुई तो इन्होंने अच्छा कदम उठाया और उसको सस्पैन्ड कर दिया लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसको पन्द्रह दिन के बाद फिर लगा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक यह चीज रहेगी तब तक व्यवस्था कैसे ठीक हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर झुग्गी झौपड़ी की बात भी कही गई। अनअथाराइज्ड कालोनीज का भी जिक्र आया।

यह समस्या इस प्रदे ा के लिये बड़ी भंयकर है और फरीदाबाद तो इसका मुख्य केन्द्र बने और झुग्गी झोपड़ियां न बने। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिए। आपको बोलते हुए तीस मिनट हो गए है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः मुझे लगता है कि यह इनका आखिरी सै ान है। (ाोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैने तो कुछ समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना है और उन्ही समस्यओं का जिक्र किया है। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: Nothing more is to be recorded. Shri Maha Singh.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः .....

श्री महा सिंह (राई): उपाध्यक्ष महोदय, 8 मार्च की इस हाउस में बजट पे ा किया गया, उस पर मै अपने विचार रखने के लिखे खड़ा हुआ हूं। सब से पहले मै इसके लिये अपने हाउस के नेता को और वित मंत्री महोदय को मुबारिकबाद देता हूं कि इस सरकार ने वितीय कंसट्रेन होने के बावजूद, कर रहित बजट पे ा किया है। उपाध्यक्ष महोदय, भाई महेन्द्र प्रताप सिंह जी बड़ा बढ़ चढ़ कर यहां पर बातैं कर रहे थें। उनकी सरकार के जो पिछले काले कारनामे रहे है, उनका मैं यहां पर ब्यान करूंगा। (ाोर) उपाध्यक्ष महोदय, ये ज्यादा गरीबों के हितैशी बनते है भाायद ये

उन काले दिनों को भूल गये है कि सलाखों में डाल दिया था। (ाोर एवं व्यवधान) (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः आध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाए।

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपकी आज्ञा से व्यवस्था की बात कहता हूं कि भाई महेन्द्र प्रताप सिंह जो की थोड़ी थोड़ी देर के बाद पता नही खुजली उठती है और जब चाहें वे खड़े होकर उठकर बोलने लग जाते है। उनको कम से कम इस हाउस की मान–मार्यदा का भी ध्यान रखना चाहिये और स्पीकर महोदय की आ ा के बिना बोलना नही चाहिये। (ाोर)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, जब सही बता कही जाती है तो वह कड़वी लगती और ये लोग सच्ची बात को सुनना बर्दा त नही करते। (ाोर)

श्री महा सिहंः अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ी खु ाी हो रही है कि इस सरकार ने गांव के किसानों की तरक्की के लिये यह बजट पे ा किया है और इस बजट का 71 परसैन्ट पैसा गांवो की बहबूदी व खु ाहाली पर ही खर्च होगा। होना भी चाहिये क्योंकि यह प्रदे ा किसानों का प्रदे ा है। इसके लिये मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। कुछ भाई इस बात की भांका करते है या इलजाम लगाते है कि यह सरकार भाहर वालों के खिलाफ है। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि इस बजट के

अन्दर भाहरा की तरक्की को उतनी ही बात सोची गई है जितनी कि देहात की। मै कहता हूं कि अगर 71 प्रति ात की बजाए 80 प्रति ात बजट देहात को जाए तो गलत न होगा। भाहरों की तरक्की के लिए मौजूद सरकार चौधरी हुक्म सिंह की सरकार ने बहुत काम किए है। एक स्मल डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया गया, म्युनिसिपल ग्रांट कमी ान बनाया गया। भाहरों में जो म्युनिसिंपल कमेटियों की आमदन कम थी उनके लिए सरकार ने दूसरे सोसिज जुटाए। इसलिए यह कहना नावजिब है कि यह सरकार भाहरों के खिलाफ है। चाहे कोई आदमी कही भी रहता हो यह सरकार सब को तरक्की करना चाहती है, इस बात को यह बजट द ार्ाता है। इसके साथ–साथ मै एक और बात आपको माध्यम से कहना चाहूता हूं। मंडल कनी ान के बारे में भाई महेन्द्र के जरिए उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने फट से अपनी बात बदल कर कहा कि मै इसको हिमायत करता हूं। (विघ्न)

श्री महेन्द्र प्रताप सिहंः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्षः आप कृपया बैठे। मेरी इजाजत के बगैर जो कुछ भी बोला जाए वह रिकार्ड नही होगा।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः.....

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै इस बजट के माध्यम से मडल कमी ान के बारे विचार रखना चाहता हूं। मै भाई महेन्द्र

प्रताप जी से प्रार्थना करूंगा कि वे भाान्त हो कर बैठे। जब उनकी बातें हमने सुनी तो वे भी हमारी बात सुने। कुछ भाइयों ने इलजाम लगाया कि चौधरी देवी लाल मंडल कमी ान के खिलाफ थे। मैं बताता हूं कि हिन्दुस्तान में वे पहले आदमी थे जिन्होंने उस रिपोर्ट को और भी अच्छे ढंग से इम्पलीमैंट करवाया। वे इसको लागू करवाने के लिए जेल में गए। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मंडल कमी ान की रिपोर्ट में कुछ कमियां नजर आई जिसकी वजह से लोगों में रि–एक ान हुआ लेकिन मैं हुकम सिंह सरकार को मुबारिकबाद देना चाहता हूं क्योंकि लोगों की तरफ से यह बात आई थी कि रिजर्वे ान का बेस इकोनोमिक होना चाहिए। इस मांग को देखते हुए हमारी सरकार ने गुरनाम सिंह कमी ान बैठा दिया। इसमें जो कमियां नजर आती थी वे पूरी कर दी। इससे हरियाणा में एक नई कान्ति की भाुरूआत हुई। आज हरियाणा का सारा दे ा अनुसरण करता है। आने वाले समय में रिजर्वे ान के खिलाफ कोई बगावत न हो इस कमी को भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। आज दे ा में सब से बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। मै हुक्म सिंह सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होने एक परिवार में एक रोजगार देने की बहुत अच्छी योजना बनाई है। ये लोग कह रहे थे कि प्रदे ा के अन्दर इतने परिवार है इसलिए इतने रोजगार सरकार नही दे पाएगी। हम बताएंगे कि कैसे रोजगार दे सकते है। यह तरीका भी हम बताएंगे कि हर परिवार के एक आदमी को हम कैसे रोजगार देंगे। हम सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार के साधन जुटाने के लिए

ि ाक्षा पद्धति में सुधार करेंगे। जो टैक्नीकल ि ाक्षा है हम उसको लागू करैंगे, जो जोब ओरिएन्टिड ि ाक्षा है हम उसको लागू करेगे। इसके साथ–साथ हमारी सरकार ने साइड बिजनैस जैसी योजनाएं भुरू की है। दिल्ली के चारों तरफ लगते हुए हरियाणा प्रदे ा के 40 किलोमीटर के एरिया में लोगों को कै ा क्रौप पैदा करने के लिए बढ़ावा दिया है ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सके और उसकी आमदनी हो सके। हमारे ऐम्पलायमैट मिनिस्टर सैनी साहब ने कहा कि हरियाणा के अन्दर 30–35 लाख परिवार ऐसे नही है। जिनके हर घर में बेरोजगार बैठा है। हो सकता है कि लगभग एक लाख नौजवान हरियाणा के अन्दर बेरोजगार हो उनको भी हमारी सरकार रोजगार के साधन जुटाएगी किसी को परमिट देगी, किसी को लाइसैंस देगी। जो बेरोजगार नौजवान है उनको हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएगी। हमारी सरकार एक परिवार एक रोजगार स्कोम को अव य लागू करेंगी। अध्यक्ष महोदय, अब मै बिजली के संबंध में कहना चाहूंगा। मै भाई महेन्द्र प्रताप जी से पूछना चहाता हूं कि इस समय हरियाणा के किसानों को कितनी बिजली मिल रही है और जब आपकी कांग्रेस पार्टी को सरकार थी उस समय किसानों को कितनी बिजली मिलती थी हमारी सरकार आने के बाद हरियाणा के किसानों को 53 परसैंट बिजली मिल रही है और आपकी कांग्रेस पार्टी के समय में किसानों को केवल 18 परसैंट बिजली मिलती थी। क्या आप किसानों को 18 परसैंट बिजली दे करके उनके हितैशी बनते थे? किसानों की हितैरी तो

यह सरकार है जिसमें 53 परसैंट बिजली देहातों को दी है और दे रही है। हर किसान के खेत में, घर में और खलिहान में बिजली जा रही है। भाई महेन्द्र प्रताप जी ने बोलतेक हुए कहा कि आपको पता लग जाएगा जब चुनाव आने वाले है। मै कहता हूं कि भाई महेन्द्र प्रताप जी पता आपको भी लग जाएगा जब चौधरी देवी लाल जी का यह नारा होगा कि लोगों भाप यह बताओं कि आपको बिजली कांग्रेस के समय में कितनी मिलती थी और अब कितनी मिल रही है। इसके अलावा मै एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने सामाजिक परिवर्तन किया है जोकि हमारी सरकार का एक बहुत ही सराहनीय काम है। भाई महेन्द्र प्रताप जी किस मूंह से कह रहे है कि यह बजट दो बैसाखियों पर खड़ा है भाायद इनको यह नजर नही आता कि यह एक आर्थिक परिवर्तन है जो हमारी सरकार ने बुढ़ापा पैं ान लागू की है। हरियाणा प्रान्त हिन्दुस्तान का पहला प्रान्त है जहां पर बूढे लोगों को बुढ़ापा पै ान दे कर सम्मान दिया गया है। जो बुढ़ापा पै ान लागू की गई है यह किसी आम आदमी की अर्थिक सहायता के लिये लागू नही की गई है। यह तो बूढ़े के समान के रूप में पैं ान दी गई है। जब हम गांवो मैं जाते है तो देखते है कि बूढ़े लोग चौपाल, डाकखाना या किसी सामूहिक जगह बैठे होते है और जब उनको यह कहा जाता है कि पैं ान आई हुई है तो कोई बूढ़ा लाठी ले कर चलता है और कोई बच्चा आपने दादा की ऊंगली पकड़ कर डाकखाने तक ले जाता है। वहां जा कर बूढ़े

बुढ़िया 800–800 रूपय के नोट लेते है। इस सरकार ने उनको बहुत सम्मान दिया है। (ाोर)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै यह कहना चाहता हूं कि जब हमारी माननीय साथी आगरा के एक होटल में थे उस समय यह बुढ़ापा पैं ान और बूढ़ी का सम्मान कहां पर था? (ाोर)

श्री अध्यक्षः यह कोई प्लायंट औफ् आर्डर नही है।

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै कह रहा था कि जब बूढ़े बुढ़ियों को पैं ान के 800–800 रूपय के नोट मिलते है और जब वे अपने घर में आ कर एक कमरे में बैंठ कर दरवाजा बन्द करके उन नोटों को गिनने लगते है तो उस समय उनके पोता पोती आ कर पूछते है कि दादा जी चाय लांऊ। चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बूढ़ो को ऐसा सम्मान दिया जिसके लिए वह सरकार बधाई की पात्र है। इस सरकार ने यह बहुत ही क्रातिकारी परिवर्तन की बात की है।

अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों के लिए यहां पर बड़ा भाोर– ाराबा हुआ कि उनके साथ बेइन्साफी हुई है लेकिन मै इन्हें यह बताना चाहता हूं कि हमारे सदन के नेता ने अपने कर्मचारियों के लिए 30–32 करोड़ रूपये की राहत दी और इस बात की चर्चा बजट में थी है। सरकार ने उनका मैडिकल एलाडंस बढ़ाया है और दूसरी कई सहूलियतें दी है और ये सहूलियतें भी

उस समय दी जब प्रदे ा की वितीय स्थिति बहुत ही खराब हालत में है। यह वितीय संकट एक तो खाड़ी संकट और दूसरी कई सहूलियतें दी है और ये सहूलियतें भी उस समय दी जब प्रदे ा की वितीय स्थिति बहुत ही खराब हालत में है। यह वितीय संकट एक तो खांड़ी सकंट की वजह से पैदा हुआ और दूसरे कुछ और कारणों से पैदा हुआ। मेरे कहने का मतलब यह कि इतने वितीय संकटों के बावजूद भी सरकार ने अपना दिल खोल कर अपने कर्मचारियों को सहायता दी है और इतना ही नही सी0 एम0 साहब ने यहा है कि फिर भी किसी कर्मचारी भाई की कोई ि ाकायत है तो सरकार के दरवाजे के लिए हमे ाा 24 घंटे खुले हुए है और इसी प्रकार से कोई उनकी उचित मांग होगी तो सरकार उसको भी मानने के लिए तैयार है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, कुछ भाई कहते है कि इस सरकार ने कुछ नही किया। अध्यक्ष महोदय, पहले जब चौधरी देवी लाल जो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने यानि हरियाणा सरकार ने ओलावृश्टि से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा अपने हरियाणा के किसानों को दिया। यह मुआवजा उनसे पहले हिन्दुस्तान के किसी सूबे की दूसरी सरकार ने कभी नही दिया था। चौधरी देवी लाल जी ने नैचुरल कलेमैटीज से होने वाली फसलो मुआवजा देना भाुरू किया है। इस घोशणा को करने वाले वे सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। मुआवजा भी कम नही बाल्कि 400 रूपया प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया है। पिछले सै ान में भी मैने इस संबंध में एक बात व्यक्तिगत रूप से कही थी कि जब पिछे चौधरी देवी लाल जी चीफ मिनिस्टर थे और सै ान चल

रहा था तो जिस प्रकार से अब की बार चलते सै ान में ओले पड़े है उसी प्रकार से उस समय भी ओले पड़े गए थें। उस समय बदकिस्मती मे ंमेरे हल्के में भी काफी ओले पड़े थे। और फसलों का बहुत अधिक नुकसान हुआ था। जब ओला वृश्टि से फसलों का काफी नुकसान हुआ तो तमाम डी0 सीज0 की रिपोर्ट मुख्यमंत्री महोदय तक आई तो चौधरी देवी लाल जी सदन छोड़ कर देहात में गए। चूंकि मेरे हल्के में उस समय बहुत अधिक नुक्सान हुआ था वे सबसे पहले मेरे हल्के में गए और मै भी उस समय उनके साथ था। वहां खेतों में जा कर जब उन्होंने गेहूं की फसलों का नुक्सान देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे हल्के के अन्दर जब वे एक गांव से गुजर रहे थे जो मेन रोड के साथ था तो उन्होंने खेत के अन्दर एक बूढ़े आदमी को बैठे हुए देखा। वे गाड़ी रोक कर के उसके पास पहूंचे और उस किसान से पूछा की बाबा आपको क्या तकलीफ है तो वह कहने लगा कि मेरे पास केवल 4 एकड़ जमीन थी और उसमें जितनी भी मेरा फसल थी वह सारी की सारी ओलावृश्टि से खराब हो गई है। वह बेचारा रो रहा था और बुरी तरह से सिसक रहा था। उसने अपनी बात कही नही जा रही थी। यह हालत उसकी चौधरी देवी लाल जी से देखी नही गई। बूढे बाबा ने कहा कि मेरे 5–6 छोटे–छोटे बच्चे है उनकी क्या होगा। इस पर चौधरी देवी लाल जी ने अपनी जेब में हाथ डाला और जितने पैस जेब में थे वे सारे के सारे उस बाबा को दे दिए और कहने लगे कि ये पैसे तो तुम रखो बाकी आपकी सरकारी तौर पर स्पै ाल गिरदावरी होगी और जो पैसा सरकारी

तौर से दिया जायेगा वह अलग से होगा। (विघ्न) मैने बाद में उस बाबा से पूछा कि आप की चौधरी साहब कितने पैसे देकर गए है तो वह कहने लगा कि 4 हजार रूपये थे । (विघ्न) 400 नही 4000 थे।

17.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, और भी बहुत से मुद्दे बजट में पे । किए गए है जिनकी बारे में से कहना चाहता हूं। सदन के अन्दर एम्यूजमैंट पार्क यानि डिजनीलैड पर भी चर्चा हुई। पर्यटन विभाग का इस हकीकत को कई भाई समझ नही कि और इन्होने उस गलत ढंग से लिया। टूरिज्म से सबसे ज्यादा फारेन एक्ससैज हिन्दुस्तान में कमाया जा रहा है इसलिए टूरिज्म को बढ़ाया दिया जाता बहुत जरूरी है। टूरिज्म डिपार्टमैंट के जरिये सरकार गरीवों की भलाई करना चाहती है। टूरिज्म के जरिए सरकार अमीर आदमी को जैब से निकाल कर गरीब को देना चाहती हैं इससे किसानों के साथ, गरीबों के साथ कोई नाइन्साफी की बात नही है। हिन्दुस्तान में बहुत से सैलानी हर साल आते है जिनसे काफी फारेन एक्सचेंज प्राप्त होता है। स्पीकर साहब, दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा भाौक है तो वह है सैर करना। लोग घुमने के लिए आते है और हिन्दुस्तान को सबसे ज्यादा फारेन करन्सी ट्ररिज्म से प्राप्त हो रही है। यही कारण है कि हिन्दुस्तान की सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। टूरिज्म के बारे में बोलते हुए माननीय साथी श्री भार्मा जी ने

भी कबूल किया कि टूरिज्म स्थलों पर पहले बहुत महगा खाना मिला करता था लेकिन इस सरकार ने पर्यटक स्थली पर साढे सात रूपये की थाली दे कर एक आद र्ा कायम किया है। इसमें गरीब आदमी के भले की बात की गई है, उसका फायदा किया है अध्यक्ष महोदय डिजनीलैड बनाने की बात का भी जिक्र किया गया है लेकिन हरियाणा सरकार कोई डिजनीलैंड नही बना रही है। हां मनोरजंन पार्क बनाने की बात जरूर है। जब लोगो ने इस मनोरंजन पार्क के बनाएं जाने का कुछ विरोध किया तो सरकार ने लोगों के मन को जानते हुए और उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए 26–28 हजार एकड़ भूमि पर बनने वाले इस मनोरंजन पार्क के एरिया को घटाकर 4–6 हजार एकड़ कर दिया है। स्पीकर साहब, यह भी कहा गया कि किसानों की जमीन ली गई और बड़े–बड़े फार्म कायम किये गए है लेकिन ऐसा नही है। इस पार्क के लिए किसानों और गरीब आदिमयों की जमीन नही लो गई है। ऐसा मनोरजन पार्क बनाना गरीब विरोधी नही है, किसान विरोधी नही है। इस मनोरंजन पार्क के बतने से कई गरीब लोगों की जीब्ज मिलैगी उनकी जेब मैं जेब से पैसा आएगा और लोगों का भला होग। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, अब आप वाईड अप कंरिये।

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै इस सारे बजट का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह बजंट गरीबों के भले का बजट है और इससे आम आदमी का जमीन स्तर ऊपर

उठेगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सरकार ने जितनों डेली येज, दिहाड़ीदार को एक दिन की मजदूरी दी है वह भाायद पंजाब के अलावा पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। (विघ्न) यू तो कम्यूनिस्ट कहते है कि हिम तो मजदूर को सरकार है और जो भी काम करते है उसमें मजदूरों को बराबर का हिस्सा देते है लेकिन कोई भी कम्यूनिस्ट सरकार इतने बेजिज नहीं दे पाई जितनी कि हरियाणा सरकार ने दिये है। (विघ्न) स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार गरीब और मजदूर की सरकार है और उनकी भलाई के लिए उसने एक नही कदम उठाये है जिसको सराहना पूरे हिन्दुस्तान में को गई है।

दिहाडीदार मजदूरी को हमारी सरकार ने तो इतनी ज्यादा मजदूरी दी है लेकिन इन कमण्डल वालों की सरकार ने मजदूरी के लिए क्या किया है? (विघ्न)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। डा0 महा सिंह जी कमण्डल वालों की सरकार कहा है। यह कमण्डल की सरकार नही है बल्कि ये बी0 जे0 पी0 की सरकारें है जो गरीब और मजदूर समर्थक सरकारें है। मैं इन्हें यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदे ा में बोड़ी बनाने वाले एक मजदूर को 15 रूपये दैनिक मिला करते थे लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने बीड़ी बनाने वाले मजदूर की दैनिक मजदूरी 15 रूपये से बढ़ा कर 45 रूपये कर दी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः भार्मा जी, ठीक है, अब आप बैठिए।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, एक और महत्वपूर्ण बात जो सारे हरियाणा के हित को है, वह है एम0 वाई0 एल0 कैनाल का बनाया जाना। सभी लोग इन बात की मानते है कि एम0 वाई0 एल0 हरियाणा के लिए लाईफ लाईन है। अध्यक्ष महोदय, एम0 वाई0 एल0 नहर को पूरा किये जाने के लिए मास्टर हुकम सिंह जी की सरकार सबसे ज्यादा प्रयास कर रही है ताकि इसका निर्माण जल्दी से जल्दी हो सके लेकिन नहर का क्षेत्र हमारी टैरीटरो में नहीं है, पंजाब की टैरीटरी में है। हरियाणा सरकार हर कोि ा ा कर रही है और इसके लिए गर्वमैंट आफ इण्डिया को भी एप्रोच की जा रही है कि हरियाणा की फोर्स भेजकर एस0 बाई0 एल0 कैनाल को जितनी जल्दी हेा सके, किसी न किसी तरह से बनाया जाये। यह सरकार पूरी तरह से इस कैनाल को हरियाणा की लाईफ लाईन समझती है और इसके महत्व को समझती है। इसलिये हमारी सरकार इस बात की पुरजोर कोि ा ा में है कि एस0 बाई0 एल0 कैनाल का पानी जल्दी से जल्दी हरियाणा के सूखे खेतों में पहुंचे और हरियाणा के किसानों को फसलें लहलहायें। यहां की प्यासी भूमि को पानी मिले। सरकार इसको जल्दी से जल्दी बनायें यह उसकी तीब्र इच्छा है।

अध्यक्ष महोदय, एक घटना के बारे में मै यहां पर कहना चाहता हूं। सारे दै ा में सबसे बड़ा गन्ना मिल हरियाणा के अन्दर होने का सौभाग्य हमें प्राप्त है और हिन्दुस्तान के अन्दर

कैपेसिटी यूटलाईजे ान की और रिकवरी की बात क जहां तक ताल्लुक है, इसके लिये भी मै मास्टर हुकम सिंह जो की सरकार को मुबारिक बाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में इतना बड़ा काम हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं वह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत हरियाणा सरकार ने दी है। वह तब दी जा रही है जबकि हरियाणा के गन्ने की रिकवरी दूसरों के मुकाबले में कम है। यहां के गन्ने की अविकतम रिकवरो 10 फीसदी है जबकि महाराश्ट्र के गन्ने की रिकवरी 18 फीसदी है और पंजाब के गन्ने की रिकवरी 11–12 फीसदी है। लेकिन इसके बावजूद भी कि हरियाणा के अन्दर गन्ने की रिकवरी बहुत कम है और गन्ने का भाव सबसे ज्यादा दिया गया है। इसके लिये भी यह सरकार बधाई की पात्र है। (घंटी) मै अपना बात खत्म हो करने जा रहा हूं।

ला एंड आर्डर के बारे में यहां पर बहुत चर्चा हुई है। यह बात ठीक है के इसमें कुछ कमियां हो सकती है। सरकार के चलाने में कुछ गलतियां भी ही सकती है लेकिन एक बात मैं सदन के अन्दर अव य कहना चाहता हूं कि पंजाब हमारे साथ लगता हुआ प्रदे ा है और वहां पर दे ा के दूसरे भागों के मुकाबले मे सबसे ज्याद टैरोरिस्ट ऐक्टीवीटीज होती है। हरियाणा का बहुत सा हिस्सा पंजाब के साथ लगता है। हरियाणा की पुलिस को और मास्टर हुक्म सिंह की सरकार की मै इस बात की मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि एक भी ऐसी अग्रवादी गतिविधी नही है जिसके

अन्तर्गत या तो कलाप्रिट्स को गिरफ्तार न किया गया हो या फिर उनको एनकाउन्टर में न मार गिराया हो। एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें ऐसा न किय गया हो। मै तो यही कहना चाहता हूं कि हमारी हरियाणा की पुलिस ने पंजाब मे जा–जाकर उग्रवादियौं को पकड़ा है। (व्यवधान व भाोर).....

Mr. Speaker: Please wind up.

श्री महा सिंह: अभी खत्म करूंग। एक पेय जल की बात है हरियाणा सरकार की इस बारे में थोड़ी सी कमी रह गई है, जो मै यहां पर बताना चाहूंगा एक डेढ फिक्स कर दी गई थी लेकिन वहां तक काम नही हुआ (विघ्न) मैं सरकार के एक मनसूबे के बारे में भी बताना चाहूंगा कि यह सरकार गांव और भाहर के फर्क को मिटाना चाहती है। जो सुख–सुविधाएं दिल्ली, बम्बाई और कलकता जैसे भाहरो में है, वही सुख सुविधायें हमारी सरकार गांव में भी देना चाहती है और कास्बे की झोपड़ी में भी देना चाहते है। जहां तक पीने के पानी की बात है, सरकार ने प्रोब्लम और नान प्रोब्लम दोनो किस्म के एक–एक गांव मे पीने का पानी महौया करने का संकल्प लिया है। उस संकल्प को जल्दी ही पूरा भी कर दिया जायेगा। जिस तरह से भाहरों के घरों में टूटियां लगी होती है, उसी तरह से गांवो में टूटियां नही लगी होती। अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नही है कि हम ऐसा कर सकते है। महेन्द्र प्रताप सिंह जी चले गये। उनकी पार्टी ने दे ा पर 38 साल तक राज किया है लेकिन उन्होंने गांवो की भोली–भाली जनता को बहका

कर राज किया है। उन्होने तो 35–40 साल तक भोले–भाले गांवो के लोगों में फूट डालकर राज किया है लैकिन उन्होने वहां के लोगों की भलाई के लिये कभी कोई कदम नही उठाया। हमारी इस सरकार ने मास्टर हुकम सिंह जी के नेतृत्व में यह फैसला किया है कि जैसे भाहरों के अन्दर घरों के अन्दर प्राइवेट टूटियां दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से हम गांवो के अन्दर भी टूटिया देंगे लेकिन इससे पहले हम हरेक गांव में एक–एक कामन टूटी देंगी।

Mr. Speaker: Please wind up now.

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपका आदे ा मानते हुए ज्यादा समय नही लूंगा। यह बजट जो गांव का हितैशी है, किसान का हितैशी है उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस सरकार ने जो बजट पे ा किया है वह हरियाणा के लिए समृद्धि बनकर आएगा और इससे लोगों की बहुत भलाई होगी।

अध्यक्ष द्वारा रूलिंग

अधिकारी दीर्घा में सी0 आई0 डी0 अधिकारी के बैठने सबंधी श्री हीरानन्द आर्य के प्वायंट आफ आर्डर पर

Mr. Speaker: Hon, Members, I have to give a Ruling. On Friday Shri Hira Nand Arya raised a point of order as to whether any officer of C.I.D. can sit in House (Officer's gallery) or not?

श्री सूरज भामः स्पीकर साहब, आन ए प्वाएंट आफ आर्डर। बड़ी बदाकिस्मती है कि आपका जो फैसला है वह अखबारों में भाायद छापा जा चुका है जोकि आप द्वारा रूलिंग देने से पहले छपना नहीं चाहिए था। This is a very serious matter.

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): आपने छपवा दिया होगा।

श्री अध्यक्षः क्या छप गया है?

श्री सुरज भातः सही कि वह बैठ सकता है। यह अखबारों में पहले कैसे छप गया? It is a very serious matter.

Hon. Membera, as this august House is quite a ware of this foct that officers Gffcrs Gallory is meant for the officers of the Government. The reasons for providing them some seating arrangement in the officers Gallory is obviously clear that their presence is required in connection with the business befor the House and they accordingly assist there departments so that the Ministers may bring the full facts before the House while answering the questions Ordinarily it has been observed that no offcer remains present in the Offcers Gallery for longer than the business of that department. This has been the practice and converntion that Heads of Deprtment/ Organisations are given seat in the Officers Gallery. In the absence of senior most officer, officer next to him remains present in the Officers Gallery for the convenience of the Minister other than official duties no fficer is allowed to sit in the officers Gallery. No official of the C.I.D. is permitted to sit in the Officers General of except these norms. In the absence of the Director General of Police some

other officers may be permitted to sit in the Offcers Gallery only for the purpose of obtaining some immediate infor mation for concerned Minister relating to the business befor the House and not otherwise.

डा0 रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, आपने जो सी0 आई0 डी0 के बारे में रूलिंग दी है उसके बारे में गृह मंत्री ने कहा कि वह अपोजि ान वालो के छपवा दी होगी। मैं यह कहना चाहता हूं–

श्री अध्यक्षः रूलिंग पर कोई डिस्क ान नही हो सकती। Please take your seat. (ाोर एवं व्यवधान)। Kadian Sahib please do not interrupt like this.

डा0 रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए।

Mr. Speaker: Doctor Kadian, I have given my ruling and you may interpret it the way you like. There can be no discussion on it.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, हम उस बात को बड़ा सीरियस मानते है और सीरियसनैस के कारण ही हम आपके नोटिस में लाए थें। इंटरप्रिट ान तो आपने ही करनी है।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप बेठै। अब सरदार सरदूल सिंह बजट पर बोलेंगे।

वर्श 1991–92 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुररारम्भ)

श्री सरदूल सिंह (सफीदो): स्पीकर साहब, मै इस बजट की किसानो, मजदूरो और ग्रमीणों की भलाई का बजट समझकर वित्त मंत्री अपने बहुत ही हमदर्द प्यारे मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। स्पीकर साहब, मै मिसाल दूंगा कि किन कारणों से यह बजट ग्रामीणों के लिए है। मै सब से पहले बिजली का जिक्र करता हूं। जब से यह सरकार आई है किसानों को बहुत तसल्ली है और खु ाी है कि बिजली के क्षेत्र मै इस सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है और बिजली ठीक मिलने के कारण जो उनकी ईकम है वह बहुत अच्छे ढंग से रोज व रोज बढ़ती जा रही है। बिजली को छोटी लाईन बिछाने की सरकार की स्कीम है जिसके लिये 25 हार्स पावर के ट्रांसफार्मर्ज लगाये जाएंगे। यह एक सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है। बिजली की लम्बी लाईन होने के कारण किसानों की परे ाानी होती थी क्योंकि जब वह लाईन खराब हो जाती थी तो 18–18, 20–20 ट्यूबवैल्ज जोकि उस एक लाईन पर हो चलते थे, वे सारे के सारे एकदम इक्ट्ठे की बन्द हो जाते थे लेकिन अब सरकार ने जो छोटी लाईनें बिछाने की स्कीम्ज बनायी है इनसे किसानों को बहुत सुख मिलेगा। इसके लिये मै सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के इतने अच्छे कामों की तारीफ करने की बजाये ये भाई भाोर मचा रहे है कि गरीबों की भलाई के लिये, किसानों को भलाई क लिये सरकार कुछ नहीं कर रही है। गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव नही हो रहा है। मै अपनी सरकार को इसलिये भी बधाई देता हूं कि किसी की मांग किये बगैर, किसी

के भाोर मचाने के बगैर ही सरकार ने गरीबों के लिये सस्ते अनाज का प्रबन्ध किया है और ओर सारे गांवों मे लगभग दुकानें खोल दी है। हमारे प्यारे मुख्यमत्री चौधरी हुक्म सिंह जी ने खासतौर पर अधिकारियों को यह आदे ा दे रखे है कि किसी भी गांव में अनाज की कमी नही होनी चाहिये। कोई आदमी भूखा नहीं मरना चाहिए। (तालियां) लेकिन हमारे अपोजी ान के भाई कहते हैं कि यह सरकार गरीबों क साथ धोखा धड़ी कर रही है। उनका यह कहना तो केवल एक ढलोसला है। उनकी ये बातें गल्त है। मेरे आपने हल्के के लोग मेरे पास आते है और कहते है कि सरकार ने किसानों के भले के लिये इस तरह के बहुत से काम किये है। हमारे गांव में अब अनाज की कोई कमी नही है। गरीब लोग पूरी तरह से खु ाहाल है।

स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर कानून और व्यवस्था की हालत बहुत बेहतर है। ये मेरे अपोजी ान के भाई भूलते है कि जब ऐमरजैन्सी के अन्दर लोगों को जेलों के अन्दर ठोंसा गया था, उस वक्त उनकी क्या हालत थी। मुझे भी जेल के अन्दर ठोंसा गया था लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि मेरा कसूर क्या था? हम यह कहते थे कि आप हमारे गरीब जमीदारों की सुना लो लेकिन इनकी सरकार ने कोई परवाह नही ी और लोगों को खुब सताया और यातनाएं दी। क्या यही कानून व्यवस्था थी इनके राज में जो ये लोग आज इस सरकार की कानून व्यवस्था को कोस रहे है? आज ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं सच्चाई के

साथ कहता है कि ऐमरजैन्सी के दिनों में जब हम जेल में थे तो जिन लोगों के पास सर कार का बहुत थोड़ा थोड़ा कर्जा था, उन लोगों को इस सरकार ने कोहलुओं से बांधा था और उन लोगों का बहुत दुख दिये थें। उन लोगों के तन पर कपड़ा नहीं था। उनको द ाा को जब हम देखते थे तो हमें बड़ा ही दुख आता था, बड़ा ही क्ले ा आता था। आखिर जनता ने ऐसी सरकार को थोड़ी देर में ही ढा मारा। इस तरह के काले करनामें इनकी सरकार ने किये थे। गरीब लोगों पर बड़ा अत्याचार ढाया था।

स्पीकर साहब, इसी तरह से मै सरकार की ि ाक्षा की पालिसी को भी बड़ा ही सराहता हूं कि इस क्षेत्र में सरकार ने स्कूलों को अप–ग्रेड करके बड़ा ही सराहनीय काम किया है। मेरे हल्के के में सरकार ने 4 लड़कियों के स्कूलों को अपग्रेड करके लड़कियों का मान सम्मान बढ़ाया है। इसके लिये मै सरकार को धन्यवाद देता हूं।

स्पीकर साहब, यह हरियाणा सरकार किसानों की मजदूरों की सरकार है। इन लोगों की सुख सुविधा के लिये वह सरकार बहुत कुछ कर रही है। एस0 वाई0 एल0 नहर जो पिछले कांग्रेस सरकार के समय में खाली दिखाई देती थी, इस सरकार से मुझे यकीन है कि वह इस नहर को लोगों को पानी से भरी हुई देगी। अगर इन भाईयों को अपने पिछले काले–कारनामें याद आ जाएं तो वे भाई बे ाक उसमें कूद पड़े तो अच्छी बात होगी। इन्होने अपने राज भाासन में किसान और मजदूरों को हमे ाा

तड़पा तड़पा कर मारा लेकिन मै इस सरकार को बधाई देता हूं कि इसने इनक भलाई के बहुत अच्छे काम किये है। ये लोग बावेला मचाते है, मालूम नही इनको क्या हो गया, अच्छे भले साथी थे। पिछले सै ान के समय एक फिरके के लोग कभी दिन के 12 बजे भी सफर करने या भाहर में जाने के लिये अपने आप को खतरे में डालने की बात सोचा करते थे लेकिन आज वही फिरका बड़ी खु ाी से आधी रात को भी भाहर में घूम आता है। तो इस प्रकार का अमन हमारे प्रदे ा में है। कोई भाई बताए कि किसी उग्रवादी को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस ने किसी एक पर भी झूठा मुकद्मा चलाया हो। ये कहते है कि पुलिस कुछ नही करती। जो लोग ऐसी बातें कहते है वे पुलिस से अपनी मन मर्जी करवाना चाहते है वरना पुलिस ठीक ढंग से काम कर रही है। हमारे एस0 पी0 जीन्द का यहां पर बार बार जिक्र आता है। वे वहां लगे हुए है मुझे फख है कि हमारे जिला जीन्द में किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होती। वहां पर कोई बेईमारी नही हो रही। सब काम ठीक ढंग से चल रहा है। स्पीकर साहब, मै इस सरकार का हिमायती हूं। मैं एक निर्दलीय सदस्य हूं और जी यह सरकार नीतियां अपना रही है वही मेरी नीतियां हैं। इसलिए मैं सरकार की हिमायत करता हूं। मै फिर इस सरकार को यकीन दिलाता हूं कि अच्छे काम करते चलो मै तुम्हारे साथ हूं। जय हिन्द।

श्री अनिल कुमार विज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, सदन में जो वर्श 1991–92 का बजट प्रस्तुत किया गया है, उस पर मै चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ है। बजट दि ाा मूलक होना चाहिए, दि ााहीन नही होना चाहिए। बजट से किसी भी सरकार की नीतियां प्रतिबिम्बित होती है। उससे पता चलता है कि सरकार अपने प्रदे ा की जनता को किस और ले जाना चाहती है। सरकार को नीतियां नया है और वह प्रदे ा की जनता को किस और ले जाना चाहती है, इसलिए बजट पर चर्चा करते समय इस पर विचार करना आव यक है। राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में कहा गया कि यह सरकार चौधरी देवी लाल की नीतियों पर और उन द्वारा द ार्ाए गए रास्ते पर चलने पर संकल्पबद्ध है। मै कहना चाहता हूं कि नीतियां वह होती है जो व्यवस्था में परिवर्तन लाने में सक्षम हो। चौधरी देवी लाल की नीतियां 1987 से पहले क्या थी और उसके बाद क्या है इनका तुलनात्मक अध्ययन करके देखें। उनकी नीतियां व्यवस्था में परिवर्तन लाने में बिल्कुल नाकामयाब नही रही है। अगर आप उन दोनों समयों को तुलनात्मक दृश्टि से देखें तो उसी प्रकार से भाई भतीजावाद उसी प्रकार से भ्रश्टाचार, उसी प्रकार से अफसर ााही, उसी बातें उसी प्रकार से बढ़ती जा रही है किसी ने कहा भी है:–

कौन कहता है कि कुछ बदला है,

वही सारंगी वही तबला है,

पहले बाप बजाता था, अब बेटे से बजवाया जा रहा है,

कठपुतलियों का नाच नचाया जा रहा है,

इनकी भी सरकार आ ाासनों पर चल रही है,

भ्रश्टाचार, बेरोजगारी, किराया भाड़ा मंहगाई दिन रात बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है यह सरकार इस तरह की चीजों के बढ़ने को प्रदे ा की तरक्की का प्रतीक मानता हो परन्तु इन कारणों से आम आदमी को जिन्दगी आज बिल्कुल बदतर हो गई है। हर हरियाणावासी के हर दिल से यह आवाज निकल रही है कि हमारे ही तरा ो हुए बुत आज बुतखाने में खुदा बने बैठे है। ओ बुतो भााबास तरक्की इसी को कहते है। जब तक तरा ाा न था गली गली में ठोकर खाने वाले पत्थर थे अब तराहा है तो खुदा बन बैठे है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हरियाणा के कर्मचारियों की दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में कहना चाहूंगा। हरियाणा प्रदे ा के कर्मचारी को दो जाने वाली सुविधाओं के बारे में कहना चाहूंगा। हरियाणा प्रदे ा के कर्मचारी काफी लम्बे समय से अपनी मांगो के बारे में सघर्श कर रहे है। उस दिन इस सरकार के एक काबिल मंत्री ने हरियाणा प्रदे ा के कर्मचारियों की मांगों के बारे मैं यह बताया कि इस सरकार ने हरियाणा प्रदे ा के कर्मचारियों के लिय क्या किया है। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों की सबसे मांग यह थी कि उन्हे समयबद्ध तरक्की दी जाए। जो पिछला बजट सै ान था उसमें भी

कर्मचारियों को यह आ वासन दिया गया था कि उन्हें समयबद्ध तरक्की दी जाएगी। पिछले महीने की 21 तारीख को भी इस सरकार ने कुछ मांगे मानी है लेकिन एक कंडी ान लगा दी कि जो समैवबद्ध तरक्की है वह 1–1–86 से मानी जाएगी और वह 1–1–91 से लागू होगी। अध्यक्ष महोदय, परमो ांज के अधिक ऐकेन्यूज न होने के कारण जो कर्मचारी अपने एक ही पदे पर काफी समय तक बैइे रहते है। उनको वह प्रोत्साहन देना का लेकिन इस सरकार ने जो कडीशन लगाई उसमे तो उनकी भरणीपरात भी कोई बैनिफिट नही मिलेगा। तदर्य कर्मचारियों को पक्का करने के बारे मैं यह कडी ान लगा दी की जो तदर्थ कर्मचारी 10–15 साल से नौकरी कर रहे है उनकी सीनिवोरिटा 31–12–1990 से मानी जाएगी। उनको उनकी 10–15 साल से नौकरी का कोई बैनिफिट नही मिलेगी। मै कहूंगा कि सरकार कि सरकार इस कंडि ायन को विदड्रा करे ताकि उन गरीब कर्मचारियों कोई परे ाानी न हो। कर्मचारी सरकार के वफादार नागरिक होते है। कोई भी सरकार अपना काम चलाने के लिये जी योजनाए होती है वे योजनाएँ उन्ही के माध्यम से बनाती है और उन्ही के माध्यम से उन योजनाओं की लागू करती है। और उन्ही के माध्यम से उन योजनाओं की लागू करती है। लेकिन जिस प्रकार से 7 मार्च को हरियाणा प्रदे ा के कर्मचारियों के साथ एक जवन्य अपराध किया गवा और चण्डीगढ़ पुलिस ने उनके हाथ पैर तोड़ दिए वह निदनीय है। कर्मचारी किसी भी सरकार के हाथ पैर होते है और जिस सरकार के हाथ हाथ पैर तोड़ दिए जाएं उस

सरकार की दयनीय स्थिति को देख कर उस सरकार को श्रद्धांजलि भेंट करने की जी चाहता है। यदि कर्मचारियों के हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो सरकार की योजनाए कैसे लागू होंगी। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से इस सरकार से कहूंगा कि हरियाणा प्रदे ा के कर्मचारियों की जो उचित मांगे हैं उनको स्वीकार किया जाए। इसी तरह से एक बात मै यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदे ा की नगरपालिकाओं के जो कर्मचारी है उनको पंजाब प्रदे ा की नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की तरह पै ान देने की तरफ सरकार ध्यान दे और उनकी बात को स्वीकार करें ताकि उनको कोई तकलीफ न हो। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मै एक बात यह कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों की ए0 सी0 आर0 लिखने की जो पद्धति है उसकी खत्म किया जाना चाहिए। दूसरे प्रदे ाों को सरकारों ने यह ए0 सी0 आर0 लिखने की पद्धति खत्म कर रखी है। जो अधिकारणीगण है ने यह ए0 सी0 आर0 लिखने की पद्धति खत्म कर रखी है। जी अधिकारीगण है वह कर्मचारियों को ए0 सी0 आर0 लिखने की पद्धति है इसको समाप्त किया जाए। इसके अलावा, मै यह कहना चाहूंगा कि जैसे पुलिस कर्मचारियों की बसों में सफर करने की सुविधाए दी हुई है, जैसे रेलवे में रेलवे के कर्मचारियों को सफर करने की सुविधाए मिली हुई है उसी तरह से सरकार अपने कर्मचारियों को बसों में सफर करने की सुविधाएं दे।

अध्यक्ष महोदय राज्यपाल के अभिभाशण में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पंचकूला में 200 मकान बनाने की बात कही गई है। इस समय सरकारी कर्मचारियों की जो मकान किराया भत्ता मिलता है वह बहुत कम है। इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे यहां चण्डीगढ़ और पंचकूला में कई हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी काम कर रहे है जबकि सरकार सिर्फ 200 मकान बनाने की बात कर रही है। इतने थोड़े मकान बनाना सरकारी कर्मचारियों की सख्या की देखने हुए बहुत कम है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि चण्डीगढ़ और पंचकूला मैं काम करने वाले कर्मचारियों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जो नए मकान बनाए जा रहे है ये अधिक से अधिक बनाए जाएं और साथ साथ मकान किराया भत्ता भी बढ़ाया जाए। इस बारे में मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि सरकार ने कर्मचारियों को जो हाउस रैन्ट देने के परपज से मकान किराये भत्ते को जो जुरिस्डिफ ान 8 किलोमीटर की फिक्स को हुई है उसका बढ़ाया जाये और इस कम से कम 60–65 किलोमीटर किया जाये ताकि लोंग चण्डीगढ़ और पंचकूला से बाहर आराम से रह सके क्योंकि चण्डीगढ़ और पंचकूला मैं कर्मचारियों का रहने के लिए मकान नही मिलते। अगर सरकार इस 8 किलोमीटर की जुरिस्डिक ान को बढ़ा देती है तो सरकारी कर्मचारियां की आवास को समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार से अब मै आगनबाड़ी वर्करों के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा। इन वर्करों के वेतनमान आज की मंहगाई के समय में इनके काम के समय को देखते हुए बहुत ही कम है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनकी पे बढ़ाई जाए। कर्मचारियों की मांगों के बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो भी उनकी उचित मांगे है। उनकी जरूर माना जाये।

स्पीकर साहब, अब मै सरकार का ध्यान ि ाक्षा तथा खेल कूद विभाग की तरफ दिलाना चाहता हूं। सरकार ने चालू साल में कई स्कूल अपग्रेड किए है और अगले साल भी कई स्कूल अपग्रेड किए जाने प्रस्तावित है यह अच्छी बात है। इसी प्रकार से चालू साल में भी कुछ नए स्कूल खोले गए है और अगले साल भी कुछ नए स्कूल खोले जाएगे। इसी प्रकार से सरकार ने एक कालेज इस साल खोला है और एक कालेज अगले साल खोलने की बात कही है। स्पीकर साहब, इसी संदर्भ में बोलते हुए मै सरकार का जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ि ाक्षा के क्षेत्र में प्राईवेट ि ाक्षा संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके इस योगदान की नकारा नही जा सकता। हमारे यहां पर 400 स्कूल ऐसे है जहां पर एक एक हो टीचर लगा हुआ है। इसी के साथ मै यह भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा में 5200 के करीब प्राईवेट ि ाक्षण संस्थाए काम कर रही है जिनमें लगभग 2 लाख 75 हजार विद्यार्थी ि ाक्षा प्राप्त कर रहे है। मै सरकार के

ध्यान में लाना चाहूंगा कि इनमें पढ़ाने वाले काफी टीचरों को 10 महीने से एक नया पैसा भी वेतन का नही मिल रहा है। इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आखिर स्कूल ि ाक्षा के मन्दिर है और इन मन्दिरों के चलाने वाले ि ाक्षकों की तरफ वि ोश ध्यान देना चाहिये। स्पीकर साहब, ऐसे भी कई स्कूल है जहां पर पिछले 21 महीने से उनमें काम करने वाले अध्यापकों को वेतन का एक पैसा भी नही मिला है। इसलिए सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और ए0 एम0 साहब को चालू सदन में ही कोई स्पश्ट घोशणा इनके बारे में करनी चाहिए ताकि उब्रकी ठीक समय पर वेतन मिल सके। इस बारे में मेरा सरकार को एक सुझाव है कि जिस प्रकार से प्राईवेट कालेज के ि ाक्षकों की वतन दिया जा रहा है उसी तरह से इन स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों को भी वेतन दिए जाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि उनको समय पर बेजिज मिल सके। इसी के साथ–साथ मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि आज प्रदे ा में प्राईवेट नर्सरी स्कूलों की सख्या, प्राईवेट स्कूलों की संख्या और कोचिंग सेन्टरों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में कमि ायल भााप्स के तौर पर बढ़ती जा रही है। इस बारे में सरकार को अपना दृश्टिकोण स्पश्ट करना चाहिए क्योंकि इन स्कूलों में बच्चों से बहुत अधिक फीस ली जा रही है। इन स्कूलों में जो सलेबल पढ़ाया जाता है उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनकी पे क्या होनी चाहिए उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इन स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापको का बहुत

कम वेतन मिलता है। इसलिए मै चाहूंगा कि सरकार को इस बारे में गंभीरता से विंचार करना चाहिए ताकि इन स्कूलों में जो बच्चों का ऐक्सप्लायटे ान हो रहा है उसको दूर किया जा सके।

स्पीकर साहब, साल के भाुरू में ही जो टीचरों की ट्रांस्फर का चक्कर चलता है इस तरफ भी सरकार की गंभीरता से ध्यान देना चाहियें। सरकार का सारा ध्यान ट्रांसफरों की तरफ ही लगा रहता है जिसकी वजह से स्कूलों में पढाई का काम ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि टीचरों की ट्रांसफर के लिए एक परमानेंट ट्रांसफर पालिसी बनानी चाहिए जिसके तहत ही ट्रांसफर हो। इसी पालिसी के तहत ही ट्रासफर चाहने वालों की ऐप्लीके ांज आने पर ही उनकी बदली हो ताकि सरकार को रह साल बेवजह जो बदलियों की वजह से परे ाानी होती है, दूर हो सके। ि ाक्षा के बारे में मै एक बात खुले रूप से यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों मण्डल आयोग रिपोर्ट लागू होने से कुछ घटनाएं हुई और उन घटनाओं में बहुत से बच्चे गुमराह भी हुए है? इस बारे में मेरे बोलने से पहले भी चूंकि बहुत कुछ कहा जा चुका है इसलिए इस पर मै ज्यादा नही कहना चाहूंगा। इस बारे में मै सी0 एम0 साहब से केवल एक बात कहना चाहूंगा कि जिनके खिलाफ झूठे केस दर्ज हुए हैं वे विदडा होने चाहिए। स्पीकर साहब, मै इस बात को मानता हूं कि जिन असामाजिक तत्वों ने आरक्षण विरोधी आन्दोलन में सम्पत्ति का नुक्सान पहुंचाया है उनके साथ किसी भी प्रकार की नमी नही

होनी चाहिए और उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन जिन लोगों तथा बच्चों के ऐग्जामज नजदीक आ रहे है उनके मन में केस विदडा कर लिये जाने चाहिएं। बच्चों ऐग्जामज नजदीक आ रहे हैं उनके मन में केसों के कारण बहुत भय बैठा हुआ है और मानसिंक रूप से परे ाान है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन कंरूगा कि वे इस बारे में कोई न कोई कार्यवाही जरूर करें ताकि छात्रो में किसी प्रकार का असन्तोश और निरा ाा न आए (विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, एक परिवार–एक रोजगार का बड़े जोर भाोर से प्रचार किया जा रहा है कुछ बेरोजगार प्रैजुऐट्स को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा रहा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जहां तक लोगों को रोजगार देने और बेरोजगारी भत्ता देने का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई भाक नही कि 25–30 हजार लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। मै इस बारे में माननीय मुख्यामंत्री जी का ध्यान वि ोश रूप से दिलाना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि वे इस और जरूर ध्यान देने की कृपा करे। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप प्रोसीड करिये।

श्री अनिल कुमार विजः बेरोजगारी भत्ता लेने के लिये पांच कण्डी ान्ज है। ऐम्प्लायमैंट एक्सचैज में 2 साल से ज्यादा समय से नाम दर्ज होना चाहिये, मैट्रिक हरियाणा प्रदे ा से पास की होनी चाहिये, ऐज 18 साल से 35 साल होनी चाहिए विद्यार्थी

नही होना चाहिये और फैमिली की इन्कम 10,000 रूपये साल से ज्यादा नही होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जिस परिवार की आमदनी 833.33 रूपये प्रतिमाह है उसका कोई बच्चा तो वैसे ही ग्रेजुऐ ान नही कर पाएगा या नहीं यह सोचने की बात है। मान लीजिए तक परिवार जिसकी आमदमी 833.33 रूपये है बड़ी मु कल से अपने बच्चे को मैट्रिक करवा भी लेता है, ऐम्प्लायमैंट ऐक्सचेंज में नाम दर्ज करवा लेता है और 2 साल बाद बेरोजगारी भत्ते का हकदार भी हो गया। उसको 50 रूपये महीना बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये यह कण्डी ान है कि स्टुडैन्ट नही होना चाहिए। इस योजना के तहत उस बालक को बेरोजगारी भत्ता तो मिल जाएगा लेकिन उस कोई नौकरी नहीं मिलेगी। स्पीकर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है। कि सरकार इस मागते में ज्यादा गम्भीर नही है केवल यह एक नारा है और हरियाणा के बेरोजगार नवयुवकों के लिए एक मजाक है।

श्री अध्यक्षः अब आप वाईड अप करिये।

श्री अनिल कुमार विजः अध्यक्ष महोदय, मै अब नागरिक आपूर्ति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पिछले दिनों यह कहा गया कि हमारे पास काफी गेहूं का भण्डार है और जिसकी जितनी मांग होगी गेहूं दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मेरे हल्के के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक डिपो पर केवल 25 बोरी गेहूं दिया गया है। मान लो अगर एक कार्ड पर 5 यूनिट्स है और एक डिपो पर 200 रा ान कार्ड है तो केवल 25 बोरी गेहूं

एक डिपो पर दिया जाना कहा तक न्यायोचित है। दूसरी बात मै कन्जयूम्र्ज प्रोटैक ान फोर्म के बारे में कहना चाहता हूं। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई यह स्कीम बहुत ही अच्छे है और मैं इस बारे में सुझाव देना चाहूंगा। यह फोर्म लोगों के ग्रीबैन्सिज को रिजरैस करने के लिए बनाई गई है लेकिन इन के बारे में लोगों का पता नही है। मै सुझाव दूंगा कि इनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। रेडियों के द्वारा, पम्फलैट छपता कर अथवा अखबारों के जरिये इसका पूरा प्रचार होना चाहिए ताकि लोगों आम आदमी इनके बारे में जान सके।

अध्यक्ष महोदय, बिजली की बात भी इसमें कही गयी है कि एक लाख 55 हजार में ज्यादा कनैक ान दिये जा रहे है। बिजली मंत्री महोदय मेरे सामने बैठे है। मैं इनसे यह कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे इलाके मै कनैक ान दिये हुए है, वह लकड़ी की बल्लियों पर से दिये गये है। उनको तारें लकड़ी की बल्लियों पर से जा रही है जिसकी वजह से जब बरसात होती है तो दुर्घटनाएं होने का ज्यादा अन्दे ाा बना रहता है। उसके लिये भी कुछ न कुछ प्रोवीजन होना चाहिये। मै यह चाहूंगा कि कनैक ान तो दे लेकिन वह जो लकड़ी की बल्लियों के ऊपर से तारे डालकर कनैक ान दिये जा रहे है, उनकी बजाये कोई आल्टरनोटिव प्रबन्ध किया जाये क्योंकि बरसात के दिनों में जब बल्लियां गीली हो जाती है ते उनमें करन्ट लगने का डर बना रहता है। इसका कोई न केाई सुधार किया जाये। (ाोर)

Mr. Speaker: Let him proeced please.

श्री अनिल कुमार विजः स्पीकर साहब, मै थोड़ा जन स्वास्थ्य के बारे में भी कहना चाहूंगा।

(खाद्य एवं आपूति मंत्री, श्री नर सिंह ढांडा द्वारा विघ्न)

Mr. Speaker: Dhanda Ji, what are you doing? Don't you want that House should proceed smoothly? Moreover, he is not irrelevant. Let him proceed.

श्री अनिल कुमार विजः स्पीकर साहब, अब मैं जन स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। पिछले बजट में कहा गया था कि 211 समस्याग्रस्त गांवो में और 709 गैर समस्याग्रस्त गांवो में 31 दिसम्बर, 1990 तक पीने के पानी की या नलकों की व्यवस्था कर दी जायेगी। लेकिन इस बजट में यह कह दिया गया ह। कि 380 समस्याग्रस्त गावों कम पानी पहुंचा दिया जायेगा। यह केवल खोखला नारा ही नही दिया जाना चाहिये बल्कि उस पर काम भी करना चाहिये। इसके बाद ट्रासपोर्ट के बारे मे इसमे यह कहा गया है कि इस वर्श के लिए बजट के केवल 25.07 करोड रूपया रखा गया है। (घंटी) स्पीकर साहब, अय मैं अपने हल्के की दो–बार मांगे और रखकर अपना स्थान ले लूंगा। स्पीकर साहब, मेरे नगर का बस स्टैड कई सालों से बनाने के लिए पड़ा हुआ है। उसके लिये जगह भी एक्वायर कर ली गयी थी वहां पर जो पानी के टैंक की डिग्री थी, उस जगह को समलत कर दिया गया है लेकिन अभी तक भी निर्माण कार्य नही हो रहा है। बाकी जगहों

पर भी बस स्टैड तो बनाये जाये लेकिन मेराह कहना है मेरे यहां पर भी बस स्टैड जल्दी बनाया जाये। मै यह कहना चाहूंगा कि सरकार को इस और हमारे हल्के की और भी थोड़ी सी कृपा दृश्टि करनी चाहिये। जी0 टी0 रोड़ होने की बजह से वहां पर यातायात का बहुत ज्यादा र ा रहता है। कई बार तो वहां पर यातायात अवरूद्ध भी हो जाता है इसलिये मेरा कहना यह है कि उस बस स्टैड पर काम जल्दी से जल्दी कराने के लिए मुख्य मंत्री महोदय आदे ा है।

इसके साथ ही मै अपने सिविल हस्पताल के बारे में भी कहना चाहता हूं। असल में उस अस्पताल की स्ट्रैन्थ तो 100 वेड़ज की है लेकिन उसमें 65 से ज्यादा बैड्ज लग ही नही सकते है।

Mr. Speaker: Anil Ji you please wind up now.

श्री अनिल कुमार विजः स्पीकर साहब, मै सिर्फ दो–तीन मिनट ही लूंग और खत्म कर दूंगा तो मै सिविल हस्पताल के बारे में सरकार का ध्यान दिलांऊगा कि वहां पर सैक ान्ड सट्रैन्थ के मुताबिक जो ीाी आव यक सामान है, वह मुहैया करवाया जाये। इसके अलावा एक बात वहां पर जुडी ीयल काम्पलैक्स से सम्बन्धित कहना चाहता हूं। वहां पर कम से कम सौ वर्श ने कचहरियां चल रही थी अब उनको वहां से ि ाफ्ट कर दिया गया है। अब छोटे से छोटे मुकदमे के निपटाए जाने के सम्बन्ध में आम आदमी की बड़ी मु ि कल हो रही है। सारी अदालतों को अम्बाला

भाहर में ि ाफ्ट कर दिया गया है। इस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनको छोटे–छोटे से चालान आदि के लिये भी अम्बाला भाहर में जाना पड़ता है। जुडी ीयल काम्पलैक्स की एक ब्रांच वहां पर होनी चाहिये। इसके अलावा वह पर एक महें ा नगर का नाला है। वहां से नागल कांस्टीच्यूएन्सी को सारा वरसात का पानी जाता है। जिन के कारण सारे के सारे के इलाके में बहुत मु ि कल होती है। लोगों ने वहां पर अपने घर बार बनाये हुए है। कई बार पहले भी इस विशय को उठाया लोगों ने वहां पर अपने घर बार बनाये हुए है। कई बार पहले मु ि कल होती है। लोगों ने वहां पर अपने घर बार बनाये हुए है। कई बार पहले भी इस विशय को उठाया गया है लेकिन उस किसी कभी गम्भीरता से ध्यान नही दिया गया। मेरा कहना गया है लेकिन उस पर भी गम्भीरता से लेना चाहिए और इस का कोई न कोई हल करना चाहिये। एक बात मै यह भी कहना चाहता हूं कि जी0 टी0 रोड के पास औवर ब्रिज बना हुआ है उनके पास पी0 एंड टी0 कालोनी, भाास्त्री नगर कालोनी रेलवे कालोनी आदि से जो बाजार में आने जाने के लिये सड़क थी, वह लगभग 25 साल से नही बैनी है और उस सड़क के न बनने के कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हर महीने कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। मैंने रेवले मन्त्रालय से भी पत्र व्यवहार किया था। रेवले मंत्रायल ने वहां फाटक बनाने के लिऐ अपनी सहमति दी है लेकिन उनका कहना है कि पहला खर्चा स्टेंट गवर्नमैट का वहन करना पड़ेगा।

Mr. Speaker: Now please take your seat. This is not the way.

श्री अनिल कुमार विजः अध्यक्ष महोदय, मै सदन में एक और बात कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्षः जब आप बैठिए। अत्री जी आप बोले।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, इनको एक बात कह लेने दीजिए।

Mr. Speaker: Mr. Sharma, you are defending him Rather you should ask him to take his seat.

Shri Ram Bilas Shrama: Sir, I am not defending him Let him compete.

Mr. Speaker: You should have asked him to sit down as I had already asked him to take his seat twice. (Interruptions) You ara encouraging him. Is it the way? I cannot run the House like this.

श्री राम बिलास भार्माः केवल एक मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्षः ठीक है। मंत्री जी, अभी आप बैठे।

श्री अनिल कुमार विजः स्पीकर साहब, यहां पर अनअथोराइज्ड कालोनीज का भी जिक्र किया गया। मेरे यहां पर भी एक ऐसी कालोनी है जो सौ साल से है। वहां पर कच्चे मकान बने हुए है। उनके बारे में मंत्री महोदय ने आ वासन दिया था कि

उस कालोनी को नियामित कर देगे। स्पीकर साहब, वहां पर एक दूसरी कालोनी भी है जो प्रोपर्टी डीलर्ज प्लाट काटकर लोगों को बेच गए और उनसे पैसा लेकर भाग गए। लोगौं ने वहां पर मकान बना लिए। इन मकानों को बने हुए कई वर्श हो गए हैं लेकिन वहां पर कोई सुविधा नही है। न वहां पर नालियां है और न सड़के है। स्पीकर साहब, इसमें उन लोगों का तो कोई कसूर नही है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन कालोनियों को जहा पर कच्चे और पक्के मकान बने हुए है रैगूलर किया जाए और वहां पर सड़के और नालियां बनाई जाएं। इसलिए मेरी सरकार से फिर प्रार्थना है कि वहां पर जो आव यक सुविधाएं है वे उनको दी जाएं ताकि उनका जीवन आराम से कट सके। बस इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं धन्यवाद।

श्री दुर्गा दत अत्री (राजौद): स्पीकर साहब, अपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्पीकर साहब, वर्श 1991–92 का जो बजट अनुमार है उस पर चर्चा चल रही है। मै उस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मै किसी पर छोटाक ी न करके अपने इलाके की समस्यओं को सरकार के समाने रखूंगा। मै अपने साथी जगन नाथ तथा भागीराम से अनुरोध करूंगा कि वे बीच में टीका टिप्पणी न करें। स्पीकर साहब, सब से पहले मैं कृशि के क्षेत्र के ऊपर बात करूंगा। मेरा सारा इलाका देहाती है। लोगों की जीविका का साधन कृशि है। अध्यक्ष महोदय, अलेवा को मण्डी बनाने के बारे में

मैने कई बार सरकार को लिखा कि ध्यान नही दिया गया। आज उसको कई हिस्सों में बांट दिया है। चार छः गांव कैथल में बदल दिए। ग्यारह गांव पीलूखेड़ा में बदल दिए और 28 गांव जीन्द में बदल दिए। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी, जो यहां पर बैठे हुए है, उनसे अनुरोध करूंगा कि जो गांव दूसरे ब्लौक्स में बदल गए है उनको अलेवा ब्लौक मे हुए है में ही रखा जाना चाहिए। अलेवा ब्लौक बहुत बड़ा ब्लीक है बौर बड़ा होने के कारण अधिकारीयों से सम्पर्क नही हो पाता है। कुछ ओफिसर पानीपत में बैठते है, कुछ सफीदों में बैठते है, कुछ औफिसर कैथल में बैठते है और कुछ जींद में बैठते है। इस ब्लैक में 43 गांव है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ये औफिसर्ज एक ही जगह पर बैठने चाहिएं ताकि जनता को ज्यादा दिक्कत न हो। स्पीकर साहब, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अलेवा गांव में तत्कालीन मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल गए थे और वहां के लोगों ने 10+2 स्कूल की मांग की थी। वहा पर दो हाई स्कूल हैं लेकिन 10+2 का कोई स्कूल नहीं है। हाई स्कूल से आगे पढ़ाई के लिए लड़कियों की बाहर भेजने में बड़ी दिक्कत होती है इसलिए मेरी प्रर्थाना है कि वहां पर 10+2 का स्कूल दिया जाए ताकि लड़कियां आसानी से आगे पढ़ सके। स्पीकर साहब, वहां पर दस बिस्तरों वाले अस्पताल की भी घोशणा की गई थी लेकिन आज तक उस पर विचार नही किया गया। हम लोग भी वहां से वोट लेकर आए है और लोगों ने हम में वि वास प्रकट किया है।

स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं सिचाई की बात इस सदन में रखना चाहूंगा। एस0 वाई0 एल0 नहर को बनाने के बारे में हम जनता को यह आ वासन देकर के आये थे कि इस नहर का पानी जल्दी ही हरियाणा को दिया जाएगा। हमारा झगड़ा भी यही था कि कांग्रेस सरकार को हम बार–बार इसलिये कंडैम करते रहे थे कि यह सरकार एस0 वाई0 एल0 नहर के लिये पूरा पैसा नहीं दे रही है लेकिन मैं अब कहना चाहता हूं कि अब तो केन्द्र व प्रदे ा की सरकार हमारे अपने कब्जा में है। म ीनें भी हमारी है लेकिन इस कार्य के लिये देरी क्यों हो रही है? सरकार को यह सोचना चाहिये कि एस0 वाई0 एल0 नहर का पानी हरियाणा के लिये एक जीवन रेखा है और इस नहर का जितनी जल्दी निर्माण हो जाए, उतना ही हरियाणा के लिये उपयोगी होगा। स्पीकर साहब, हरियाणा एक कृशि प्रधान प्रदे ा है। हरियाणा प्रदे ा का जीवन इसी एस0 वाई0 एल0 नहर पर ही निर्भर करता है। पिछले दिनों इस बात का आ वासन भी दिया गया था कि आने वाली फसल तक इस नहर का पानी आ जाएगा। अगर इस फसल तक नही तो अगली फसल तक भी पानी आ जाए तो भी उचित है। हम इस सरकार की चुनावों तक का भी पानी आ जाए तो भी उचित है। हम इस सरकार को चुनावों तक का भी समय दे रहे है कि तब तक भी आ जाए तो भी बेहतर रहेगा। समर्थन की इस सरकार के पास कोई कमी नही है। हम लोग तो बहुत तादाद में है। हमारा इस मामलें में समर्थन इस सरकार के साथ होगा। हम तो वहा पर इस सरकार का विरोध करेंगे, समर्थन नहीं देगे जहां यह

सरकार लोगों के साथ वि वासघात करेंगा। ऐसी जरूरी मामलो में जहां हरियाणा के हितों का सवाल हो, हम सरकार का पूरा समर्थन करेंगे।

स्पीकर साहब, जब हम इलैक ान जीतकर आये थे तो हमने सब ने जनता को यह आ वासन दिया था कि भ्रश्टाचार समाप्त करेंगे और पानी बिजली का प्रबंध करेंगे लेकिन सरकार अब जनता के साथ किए हुए वायदों से मुकर गयी है। जनता ने तो हमें यहां पर नोटों से, वोटों से तोल कर भेजा था लेकिन सरकार ने लोगों के साथ वि वासघात किया है। पहले हम सब ने मिलकर सरकार बनायी लेकिन लोग अपने स्वार्थी के लिये कभी इधर तो कभी उधर चले गये। इसलिये मेरी सरकार से आपके द्वारा प्रार्थना है कि इस एस0 वाइ0 एल0 नहर को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए क्योंकि यह तो हरियाणा के जीवन मरण का सवाल है।

इससे आगे स्पीकर साहब, में ि ाक्षा से संबंधित कुछेक बातें यहां पर रखूगा। मै यह कहना चाहता हूं कि गांवों में पढने वाले तमाम बच्चे को वह अवसर मिले जोकि, भाहरों में कांवेंट व नर्सरी स्कूलों में पढने वाले बच्चों को मिल रहा है। कुछ इस तरह से स्कूलों की गांवों के अन्दर व्यवस्था की जाए ताकि गांव का पढ़ा हुआ बच्चा भी डी0 सी0 एस0 पी0 के बच्चो से कम्पीटी ान में किसी भी प्रकार से कम न रहे, पीछे न रहे सरकार ने 71 परसैन्ट बजट का पैसा देहातों के ऊपर खर्च करने का आ वासन

इस बजट द्वारा दिया है। यह बहुत अच्छी बात है इसलियें बच्चों के स्तर को ऊपर उठाने के लिये यह आव यक है कि गांवों के अन्दर भी भाहरों जैसे कावेंट व नर्सरी स्कूल चाहे कोई प्राईवेट अदायरा ही क्यों न चलाए लेकिन सरकार उस को अपनी और से वित्तीय सहायता दे या फिर सरकार अपने लैवल इस पर तरह का गांवों के बच्चों की पढ़ाई का बढ़िया प्रंबंध करे ताकि वे बच्चे कल को भाहरों में पढ़ने वाले बच्चों के मुकाबले में हर कम्पेटी ान में उन से आगें रहे। इस तरह का प्रयास सरकार को करना चाहिये तभी गांवों का स्तर ऊंचा उठ सकता है।

अध्यक्ष महोदय, अब में इरीगे ान के मुताल्लिक अपने हल्के से संबंधित कुछ बातें कहूंगा कि तत्कालीन बिजली एवं सिचाई मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी मेंरे हल्के में गये थे और वहां वे हमें आ वासन देकर आये थे कि हसनपुर मा ादो माईनर व पेंगा माजरा माईनर की ऐक्सटेन्ड किया जाएगा लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई काम चालू नही हुआ है हालांकि 50 लाख रूपये की रा ि ा भी इनके लिये अलौट हो चुकी है। पता नही यह स्कीम अब कहां गयी। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने 14 अप्रैल 1989 के यह कहा था कि हम इस काम को एक महीने के अन्दर अन्दर भाुरू करवा देंगे। चौधरी साहब उसके बाद काफी समय तक इसी सरकार ने मंत्री के तौर पर भी रहे लेकिन हमें यह पता नही कि इतनी देर मंत्री रहने के बावजूद भी वे इस काम को भाुरू नही करवा सके। इसी तरह से और भी बहुत सी माईनर्ज है जिनकी

ऐक्सटैन्न ान के लिये हमने सरकार को लिखा था और अधिकारियों ने उनकी ऐक्सटैन्न ान के लिये हमने सरकार दी थी लेकिन उन माईनर्ज पर भी आज तक कोई काम नही हुआ। अगर पानी इस इलाके के लोगों को नही मिलेगा तो वे अपने खाने के दाने कहां से पैदा कर पाएंगे। इसलिये मेरी सरकार से पूरजोर अपील है कि इस तरह की ाजे माईनर्ज अधूरी पड़ी हुई है, उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि लोगों को अपना जीवन निर्वाह करने के लिये पानी की सुविधा हो सके। इसी तरह से 12—14 गांव और है जिनमें भी इन्ही माइनर्ज के न बनने कारण समस्याएं है जैसे गोइया, अलेवा, हसनपुर, कुचराना कलां, कुचराना खुर्द, कि ाना, थूआ, संडोला वर्गरह वर्गरह। अध्यक्ष महोदय, यह किसानों की सरकार है। अगर यह बिल्कुल ईमानदारी से किसानों के लिये काम करना चाहती है तो कर सकती है। आज पैसे की हमारे पास कमी नही है। केन्द्र में जो सरकार है वह हमारे कब्जे में है और हरियाणा सरकार भी हमारे कब्जे में है। अगर सरकार ईमानदारी से काम करे तो हम इसका धन्यवाद करेंगे। जहां तक वन विभाग का संबंध है, इसको पीछे बहुत नुकसान हुआ। जैसे पीछे आरक्षण के नाम पर और रास्ता रोकने के नाम पर अन्दोलन हुए। लोगों के अवैध रूप से पेड़ काट कर रास्ते रोक दिए थे। इससे एक और तो वन विभाग को नुकसान हुआ और दूसरी और लोगों की असुविधा हुई। मेरा निवेदन है कि इस तरह के वाक्यात बार बार न दोहराए जाए। उस समय जो लोग पंजाब से दिल्ली जाना चाहते थे, किसी न एयर पोर्ट पर समय पर पहुंचना था,

रास्ता रोकने की वजह से ऐसे लोगों को बहुत परे ाानी उठानी पड़ी। मै सम्पत सिंह जो से अनुरोध कंरूगा क्योंकि वे बड़े काविल मिनिस्टर है, पुलिस उनके कब्जे में है, इस तरह की बाधा आगे से किसी आदमी को न आए।

अध्यक्ष महोदय, अब मै वाटर सप्लाई के ऊपर अर्ज करना चाहता हूं। कुचराना कलां और कुचराना खुर्द में पानी व्यवस्था नहीं है। कि ाना गांव में जो पानी के पाइप दबाए गए है वे प्लास्टिक के है। ऐसे पाइप जल्दी टूट जाते है जिस वजह से लोगों को पीने के लिए पानी नही मिलता। एक गांव यूथा है जहां पर पहले हो वाटर सप्लाई का टैक बना हुआ है। वहां पर मवे ाी बैठते है लेकिन उसमें पानी नहीं है। मेरा निवेदन है कि भविश्य के लिये इसका ठीक इन्तजाम कर दिया जाए। सामदी में भी वाटर सप्लाई इन्तजाम नही है।

अब मै खाद्यान के ऊपर थोड़ा सा जिक्र कंरूगा। मै सरकार को कंडैम नही कंरूगा लेकिन विचौलिए लोगों ने पिछले दो महीनों में बहुत मुनाफा कमाया। कनफैड के पास सरकार ने गेहूं भेजा था, हमारे पास गेंहू की कोई कमी नही है। लेकिन बिचौलियों की वजह से उपभोक्ताओं तक गेहूं नही पहुंच पाया। जो गेहूं अढ़ाई सौ रूपय क्विटल मिलना चाहिये था उनकी उभोक्ताओं को साढ़े चार सौ और पांच सौ रूपय के हिसाब से कीमत देनी पड़ी। मेरा निवेदन है कि आगे के लिये ऐसी बात पर रोक थाम होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे थोड़ा

खुला समय दे तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मेरे हल्के में 12 सड़को पर काम होने वाला ह। समय के अभाव को देखते हुए मैं उनके नाम नही पढूगा बल्कि उनकी लिस्ट मंत्री जी को दे दूगा। मेरा निवेदन है कि उन पर लल्द काम भुरू करवा दें। अब मैं परिवाहन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारी बसों की हालत बहुत खराब है। बसों के पत्तरे टूटे होते है जिनकी वजह से यात्रियोंके कपड़े फट जाते है। हम एम0 एल0 ए0 कई बार जब अपने डैस्टीने ान से यहां पर आने का प्रयास करते है, हमें सीट नही मिलती। हमें देख कर लोग कहते है कि जो एम0 एल0 ए0 आ गया और हम सीट खाली करनी पड़ेगी। मै आपके मध्यम से अनुरोध कंरूगा कि महिलाओं के लिये विकलांगो के लिये और विधायकों के लिए सीटों की ठीक ढंग से व्यवस्थ होनी चाहिये। मै यह नही कहता कि हमारे लिए कोई वि ोश किस्म की गाड़ियां चलाई जाएं लेकिन जो आम बसें है उनमें व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए। आज कल हमारी माताओं और वहिनों को बसों मे आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, उनके कपड़े फट जाते है। माननीय होम मिनिस्टर साहब बैठे है और सौभाग्य से मुख्यमंत्री जी भी आ गए है। मै इनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि किसी भी महिला और अपाहिज को बसों में सफर करने पर कोई दिक्कत नही होनी चाहिए। जहां तक बसिज में सवारियों के बहुत ज्यादा मात्रा सें सफर का सवाल है, एक बस में कम से कम तीन गुण सवारी भर ली जाती है यहां तक कि सावरियों बसों की छतों पर चढ़ कर और लटक कर सफर करती है। खुदा न खास्ता अगर

कोई हादसा हो जाए तो उनके लिए चालक या परिचालक को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उनको वह केस भुगतना पड़ता है। जहा से बस भाुरू होती है वहा से लेकर जहा पहुचती है वहा तक सवारियो का बहुत बुरा हाल रहता है। इस बारे मे चैक किया जाए ताकि बसो से बस को कैपेसिटी से ज्यादा सवारिया सफर न करे और कोई हादसा न हो। यह तो हो सकता है कि एक बस मे उसकी कैपेसिटी से 5 या 10 सवारी ज्यादा हो जाए तो कोई बात नही वह सवारियो बस के अन्दर खडी हो करके सफर कर सकती है लेकिन यह नही होना चाहिए कि बस की छत पर या लटक कर सवारियो सफर करे।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मै अपने ह्लके के स्कूलो के बारे मे भी कहना चाहता हू। मै उनके नाम सरकार को लिख करके दे दूगा सरकार उनकी तरफ ध्यान दे। इसके अलावा मै यह कहना चाहता हू कि सरकार ने जो बुढापा पैं ान लागू की है यह बहुत ही बढिया काम किया हैं सरकार की यह बहुत ही अच्छी नीति है। इसी आधार पर लोगो ने हमे वोट दिए थे और हमे चुनाव जिताए थे। सरकार का बुजर्गो और विकलाग को पे ान देने का एक बहुत ही बढिया समाज कल्याण का काम था। इस बारे मे मै सरकार के नोटिस मे एक बात लाना चाहूगा। बुजर्गो और विकलागो को पें ान दे कर सम्मान दिया गया है न कि उनकी भुखमरी दूर की गई है। यदि कोई बूढा आदमी किसी कमजोर वर्ग से संबध रखता है तो उस की बहबूदी के लिए यह

सरकार अपने माध्यम से यह सुनि ि चत करे कि क्या ऐसे लोगो को पे ान सही और समय पर मिल नही रही है। सरकार यह भी सुनि ि चत करें कि क्या विधवा महिलाओं को सही और समय पर पै ान मिल रही है। हरियाणा प्रदे ा सरकार के अन्दर कोई भी विधवा महिला पै ान के बिना न रहे। जब हम लोग गांवों में जाते है तो ऐसी महिलाएं हमे ि ाकयत करती है कि उन्हें समय पर पैं ान नही मिल रही है। जो अधिकरीगण है वे उनकी परवाह नही करते है। मै सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार ऐसी महिलाओं को सही और समय पर पै ान नही दिलाने के लिये आनग अधिकारियों को हिदायंत दे ताकि उन महिलाओं को कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मै यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार सामूहिक विकास पर बहुत पैसा खर्च कर रही है। सामूहिक विकास के लिये जितने पैसे का प्रावधान बजट में होता है सरकार उतना ही खर्च कर पाती है। कहने के लिये चाहे यह सरकार कुछ भी कहे कि हम यह करेंगे हम वह करेंगे। वह अलग बात है। दोहात के लोगों के कुछेक सुविधाएं ऐंसी दी जानी चाहिएं जो उनके लिए बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि देहात के हर गांव में भाोचालय बनाए जाए। गांवों के अन्दर भाोचालय बनाने का काम पंचायतों द्वारा करवाया जाए। एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गांव को गालियों में कीचड़ भरा रहता है। गांवों के अन्दर वाटर सप्लाई स्कीम के जरिए पीने का पानी जाता है। लोग अपना पानी भर कर चले जाते है और टैप न होने के कारण पानी

चलता रहता है और वह पानी गांवों की गलियों में बिखरता रहता है। यह पानी की वेस्टेज भी है और इससे गालियों में गंदगी भी फैलती है। अध्यक्ष महोदय, आप गांवों में जा कर देखे उस पानी से गांवो की गलियों में सड़ांध जाती है। मै सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार गांवों की गलियों की सफाई की और भी वि ोश ध्यान दे ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। अब मै चिकित्सा सुविधाओं के बारे में कहना चाहूंगा। गावों के अन्दर चिकित्सा सुविधाएं अव य अपलब्ध कराई जाए। गांवो के अन्दर किसी गोली देने वाली नर्स और दाई का बन्दोबस्त किया जाए। जो लोग छोटे–छोटे गांवों में रह रहे है वह भी इस दे ा और प्रदे ा के नागरिक है। हमारे ज्यादातर वोटर्स गांवों में रह रहे हैं। जो भाहरों के लोग है वह अपनी चिकित्सा का प्रबन्ध अपने आप कर लेते है क्योंकि भाहरों के अन्दर तो प्राइवेट होस्पीटल्ज भी होते है। इसलिये भाहर के लोगों को दवाई पानी लेने में कोई दिक्कत नही होती है। मै सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार गांवों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में वि ोश ध्यान दे ताकि गांवों में रहने वाले लोगों की कोई दिक्कत न हो।

अध्यक्ष महोदय, अब मै कर्मचारियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कुछ समय पहले मै प्रौढ़ ि ाक्षा के कर्मचारियों से मिला था। उन्होंने मुझे रिक्वैस्ट की थी और मैने उनको रिक्वैस्ट सरकार तक पहुंचाने का आ वासन भी दिया था। हजारों की

संख्या में प्रौढ़ ि ाक्षा कर्मचारी जेलों में रहे और 6–7 महीने तक यहां एम0 एल0 एज0 होस्टल के सामने भी बैठे रहे थे। लेकिन सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नही दिया और न ही उनको बात सुनी। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया आदमी लगते है। मै इनसे प्रार्थना करूंगा कि यदि आप प्रोढ़ ि ाक्षा के कर्मचारियों की बात सुन ले तो उससे सरकार का नाम नीचा नही होगा। अगर किसी गरीब व्यक्ति कौ कोई तकलीफ है, यदि सरकार उनकी तकलीफ सुनती है तो उससे सरकार का नाम नोबा नही होता बल्कि ऊंचा ही होता है। स्पीकर साहब, सरकार अपने कर्मचारियों का ध्यान रखे तो इससे सरकार झुकेगी नही। सरकार जितना प्रोत्साहन अपने कर्मचारियों को देगी उतना बढ़िया काम सरकार को उनको दवाई बूटो आदि का प्रबंध करना चाहिए और उनको जल्दी से जल्दी रिहा कराये जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। स्पीकर साहब, यहां पर गुरनाम सिंह आयोग का भी जिकर आया है और मण्डल कमी ान की रिपोर्ट का भी जिकर आया है। मण्डल आयोग को रिपोर्ट का मकसद यही था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग है उनको कैसे रोजगार मिलै। यह बहुत लम्बे समय से मांग की जा रही थी उसी का ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को उस समय लागू किया गया था लेकिन इस रिपोर्ट के लागू होने से जो लोग उत्तजित थे या परे ाान थे उनकी वजह से सरकार को काफी नुकसान हुआ। सरकार को उसको रोकना चाहिए था। इसके बाद अपनी इस सरकार ने गुरनाम सिह आयोग को मैने भी एक रिप्रजैन्टे ान दी थी उस रिप्रजैन्टे ान में यह लिखा था कि जाति

के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नही करनी चाहिए। स्पीकर साहब, मण्डल रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री वी0 पी0 सिंह जिस तरीके से लागू किया था उस हिसाब से लागू न करके पहले इस पर बहस कराने का अवसर दिया जाना चाहिए था लेकिन वह गलती रह गयी जिसकी वजह से बहुत अधिक नुकसान हुआ। उस रिपोर्ट के लागू होनें के बाद हरियाणा सरकार ने एक और आयोग गुरनाम सिंह आयोग के नाम से 7 सितम्बर, 1990 के बैठा दिया। 7 दितम्बर, 1990 को ि ाड्यूल्ड कास्टस एण्ड बैकवर्ड क्लासिज डिपार्टमैंट की तरफ से जो नोटिफिके ान जारी हुई उसके तहत इस आयोग के चैयरमैन, भूतपूर्व जास्टिंस श्री गुरनाम सिंह व श्री मोरी राम कम्बोज व श्री साधुराम मैम्बर बनाए गए। इस नोटीफिके ान की धारा 3 की सब धारा (2) के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। इसमें यह लिखा है–

"To investigate the reasons for backwardness of various agrilcultural Classes/Communities in the State such as Ahirs, Gujjars, Sainis Jats, Jat Sikhas, Roades and Meos etc,

इस तरह से इस कमी ान के दायरे को सीमित करके रख दिया। अगर इसमें जातियों का वर्णन न किया गया होता तो यह ज्यादा अच्छा होता क्योंकि जातियों के वर्णन से जो सही मायनों में हकदार थे, जो एग्रीक्लचरिस्ट लोग है जो हरियाणा के सो ाल और इकानोमिकली बैकवर्ड लोग है वे वंचित रह गए है क्योंकि इस नोटिफिके ान के तहत उसके दायरे को सीमित करके

रख दिया गया और बाद में इसी दायरे मैं रहते हुए आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। अगर जातियों का वर्णन नोटिफिके ान में न किया गया होता और आयोग को सही रिपोर्ट देने की खुली छूट दी जाती तो वह ज्यादा अच्छा होता ताकि वह गांव–गांव में जा कर देखता कि सही मायनों में इसका हकदार कौन है और जिसको रोजी रोटी की सही जरूरत है यदि उसी को इसमें भाामिल किया जाता तो और भी ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन आयोग का दायरा सीमित होने की वजह से सही मायनों में हकदार लोगों अपने हकों से ंवंचित रह गए है। (घंटी)

Mr. Speaker: Attri Ji, you have taken suffcient time.

श्री दुर्गा दत अत्रीः अध्यक्ष महोदय, मै एक बात यह कहना चाहूंगा कि कुछ लोग सरकार को जानबुझ कर बदनाम करना चाहते है इसलिए कुछ लोगों न मण्डल रिपोर्ट पर जान बूझ कर आतंक का वातावरण पैदा किया और सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाया। ऐसे लोग गलत काम करके सरकार को बदनाम कर रहे है। ऐसे ही लोग सरकारी और पंचयातों की जमीन पर नाजायज कब्जे करने में लगे हुए है। जिससे सरकार बदनाम हो रही ह। मेरे हल्के मे ढयोला गांव के अन्दर ऐसे ही कुछ लोग जो गुरदासपुर, पंजाब से और गंगानगर, राजस्थान से आए थे गांव की 63 एकड़ जमीन पर कब्जा करके नाजायज पट्टा करवाना चाहते थे जिसकी वजह से वहां पर काफी झगड़े हुए और झगड़ा

इस हद तक बढ़ गया था कि यदि उसकों समय पर न रोका गया होता तो काफी लोगों मारे जाते।

Mr. Speaker: Please take your seat. No more time now.

श्री दुर्गा दत अत्रीः अच्छा जी, धन्यवाद।

Mr. Speaker: Thank you very much. Chaudhri Udai Bhan.

श्री उदय भान (हसनपुर): अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को आदरणीय चौधरी तैयब हुसैन, वित मंत्री जी ने जो बजट पे ा किया है, मै उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके साथ मै आदरणीय वित मंत्री जी तथा सरकार को लगातार चौथे वर्श कर रहित बजट पे ा करने के लिए बधाई तथा मुबारिकबाद देना चाहता हूं। स्पीकर साहब, हमारी सरकार की करनी और कथनी में कोई अन्तर नही है। यह बात तथ्यों पर आधारित है। इस सरकार ने कर्मचारियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की है। सरकार ने वृद्धावस्था पै ान दी है और दूसरी भी अनेक सुविधाएं दी गई है। ये सब सुविधाएं देने के कारण सरकार पर 255 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है लेकिन इस के बावजूद भी जो कर रहित बजट पे ा किया गया है उसके लिए राज्य के आदरणीय मुख्य मंत्री और वित मंत्री बधाई के पात्र है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा यह जो कर रहित बजट पे ा किया गया है यह सरकार की उन

प्रगति ील नीतियों का परिचायक है जो चौधरी देवी लाल जी ने निर्धारित की थी और हमारी सरकार ने उन प्रगति ील नीतियों का अनुसरण किया है। कृशि सहकारिता और दूसरे हरेक मामले में चाहे वह किसानों का हो मजदूरों का हो, व्यापारियों का हो, कर्मचारियों का हो सभी वर्गों को बराबर और समान सुविधाए प्रदान की गई है। पहले जो गांवों के साथ भेदभाव किया जाता था इस सरकार ने उस भेदभाव को भी दूर किया है और 71 प्रति ात बजट गांवों के विकास पर खर्चह करने का प्रावधान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, लैण्ड डिवैल्पमैंट बैंक और कोआपरेटिव बैंक के द्वारा जो 86 करोड़ रूपये के कर्जे माफ किए गए है असके कारण सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसके बावजूद भी वर्श 1991–92 के लिए लोगों को ठी ढंग से और टाईम पर ऋण मिल कसे इसके लिए भी ठीक व्यवस्था की गई है। जहां पहले यह रा ि ा 226 करोड़ रूपये थी वहां अब 400 करोड़ रूपये से ज्यादा रा ि ा का प्रावधान किया गया है जिसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक चीनी मिलों का संबंध है वह बात भी किसी से छिपी हुई नही है। ये चीनी मिलें कांग्रेसी हुकूमत के समय में वर्श 1985–56 में 5 करोड़ 62 लाख रूपये के घाटे में चल रही थी लेकिन वर्श 1989–90 में चौधरी देवी लाल की प्रगति ील नीतियों के कारण इन चीनी मिलों ने 15 करोड़ से अधिक का मुनाफा कमाया है। यह इस बात का परिचायक है कि किस प्रकार से यह सरकार किसानों और सहकारिता को साथ लेकर चल रही है और चीनी मिलो ने अपनी

क्षमता से अधिक उत्पादन किया है। हमारी चीनी की मिले बधाई की पात्र है क्योंकि उन्होने 120 प्रति ात कैपिसिटी का यूटीलाईजे ान करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसक लिए सारा यहकारिता विभाग बधाई का पात्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, सिचाई और बाढ़ नियन्त्रण के मामले में भी यह सरकार पूरी तरह से सजग है। सिचाई के क्षेत्र में पर्याप्त पैसे का प्रावधान किया गया है। पक्की खालें बनाई गई है। एस0 वाई0 एल0 के बारे में मैने गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए सरकार से जोरदार मांग की थी इस काम को किसी सरकारी एजैंसी के माध्यम से करवाया जाए। हालांकि हमारी सरकार के आने के बाद एस0 वाई0 एल0 नहर पर काफी काम हुआ है। 47 के करीब ब्रिजिज का निर्माण भी किया गया है। लाईनिंग का काम भी हुआ है, जमीन भी ऐक्वायर की गई है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ समय से काम बन्द पड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से अपनी सरकार से यह मांग करता हूं कि केन्द्रीय सरकार पर दबाब डाला जाए कि पैरा मिलिट्री फोर्सिज लगा कर एस0 वाई0 एल0 के काम को भीघ्र पूरा करें ताकि किसान को पानी मिल सके और धरती की प्यास बुझ सके।

उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ नियन्त्रण के लिए 3 करोड़ 42 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। जो ड्रेनेज का मामला है, मैने इस बारे में सरकार से कई बार जानकारी चाही है लेकिन सरकार इस विशय में विस्तार से नही बता सकी है। ड्रेनेज में जो

4 करोड़ का घोटाला हुआ है और केवल तीन दिन में इतना पैसा खर्च कर दिया है, मै इसकी तरफ हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो इसके लिये गृह मंत्री और मुख्य मंत्री जी को इस्तोफा देना चाहिये लेकिन इन की नाक के नीचे तीन दिन के अन्दर 4 करोड़ रूपये का गदन हुआ है, क्या उसके लिए इनकी जिम्मेदारी नही बनती। यह कैसे दूसरों को इस्तीफे के लिये कह सकते है? उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सरकार द्वारा जो भी बाढ़ राहत के कार्य किये जा रहे है, ये सारे इन्ही लोगों द्वारा किये कारनामों की वजह से करने पड़ रहे है। आपको पता है कि आगे बरसात आने वाली है। ड्रेन्ज की सफाई का जो काम था, उससे अफैक्ट हो रहा है। ड्रेनेज का काम सारा ठप्प होकर रह गया है। मै आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस विशय मे माकूल जवाब दे और इसके बारे में तुरन्त इन्कवायरी करके जो भी इसके लिये दोशी हो, सदन में बतायें और उसको बराबर सजा मिलनी चाहिये। मैं इस के साथ–साथ यह कहना चाहता हू कि जहां तक बाढ़ नियंत्रण का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का ऐसा है कि उसके साथ–साथ खादर का एरिया पड़ता है। पहले वहां के लिये कोई टैक्निकल स्कीम तैयार की गई थी। फ्लड कंट्रोल बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी, उसमें हालांकि वहां स्कीमों मंजूर की गयी थी लेकिन उन सारी की सारी स्कीमों पर अब काम लगभग ठप्पा पड़ा है। उन पर कोई भी काम भुरू नही हुआ है। मै आपके माध्यम से सह कहना चाहूंगा कि जो टैक्नीकल टीम की सिफारि ो है,

उनकी सिफारि ा के बाद ही उन स्कीम्ज को मंजूर किया गया है। मेरा कहना है कि उन पर काम भीघ्र किया जाये। उतर प्रदे ा सरकार ने एक–एक किलोमीटर लम्बे स्टडज बना रखे है जिससे हमारे हरियाणा के एरिया मे काफी कटाव हो रहा हैं। हमारे एरिया को भूमि के बचाव के लिये यह जरूरी है कि सरकार इस ओर गम्भीरता में ध्यान दे। वित मंत्री महोदय से भी मेरा इस बारे में यह अनुरोध है कि वह इस मा मले में प्रैफरेस देकर इसके लिये अधिक से अधिक रा ि ा उपलब्ध कराएं ताकि बाढ़ राहत के कार्य तेजी से हो सके। जो 10 करोड़ रूपये का प्रोवीजन इसके लिए किया गया है, वह बहुत कम है। इसके अतिरिक्त मैं आगरा कैनाल के संबंध में भी थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। इसका जिक्र गवर्नर एड्रैस में भी आया है। मै यह कहना चाहता हूं कि यह कैनाल तो फरीदाबाद और गुड़गाव यानी दो जिलों की जीवन रेखा है। इस आगरा कैनाल का जो कमांड एरिया है वह 1 लाख 60 हजार से भी ज्यादा है। लेकिन यह कैनाल 78 हजार एकड़ जमीन को ही पानी उपलब्ध करा पाती है। आगर कैनाल से हमारे किसानों को दोहरों मार पड़ती है। एक तरफ तो यह नहर सारी कच्ची है, व कोई लाइनिग नही हुई है। सारी खोलें कच्ची है। दूसरों तरफ इसकी जो दरे है, वह हरियाणा की दूसरी नहरों के मुकाबले में दोगुनी और चौगुनी है। इस तरह से फरीदाबाद और गुड़गांव जिले के किसानों को दोहरी मार पड़ती है। मै सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार इसके लिए कुछ उपाय अव य करें। फरीदाबाद और गुड़गांव के किसानों को उतर

प्रदे ा के रहमोकर्म पर न छोड़ा जाये। इसके लिए कोई ऐसी योजना बनाई जाये जिससे हरियाणा की इस प्यासी धरती को भी पानी दिया जा सके। हमारे इस नहर के साथ पड़ने वाले इलाके को उजीना डाइक र्न ड्रेन और गोच्छी ड्रेन से पानी की सुविधा दे दी जाये तो आपकी बड़ी मेहरवानी होगी। मेरे इस प्रस्ताव को यह सरकार पूरी गम्भीरता से ले और इसकी और ध्यान दे। इसके बाद मै बिजली के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। मै अपनी सरकार को इसके लिये बधाई देता हूं कि कांग्रेस की सरकार के समय में कही पर भी दो घंटे से ज्यादा बिजली व्यवस्था को बनाये रखने के लिये थर्मल पावर स्टे ान यमुना नगर और पानीपत का काम ं ाुरू हो गया है। हरियाणा सरकार ने हिसार के लिये मंजूरी मांगी हुई है। हसनपुर और दूसरे चांदन मजूर हो चुके है। उन के बारे यह कहा गया था कि वह मार्च, 1991 तक पूरे हो जायेगे लेकिन अभी तक भी उन पर काम भाुरू नही हो पाया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हसनपुर और चान्दन में 66 के0 वी0 के पावर हाउस भीघ्रति ीघ्र बनाये जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जन स्वास्थ्य का संबंध है सरकार ने पानी और सिवरेज की समस्या को प्राथमिकता दी है। श्री ओम प्रका ा चौटाला जब मुख्य मंत्री बने थे तो उन्होंने मुख्य मंत्री बनते ही पानी के मामले को प्राथमिकता दी थी और कहा था कि 31 दिसम्बर तक सभी गांवो में पानी पहुंचा दिया जायेगा। सरकार इस मामले में काफी गम्भीर है इसमें कोई भाक नही है

लेकिन सरकार ने जो दस्तावेज दी है उनके अनुसार केवल उस्सी गांव समस्या ग्रस्त रहे है। मै चाहता हूं कि इन अस्सी गांवों की भीघ्राति ीघ्र पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा भाहरों में भी जहां पानी की किल्लत है वहां पर पानी का इन्तजाम किया जाए। मेरे यहां होडल में पानी की काफी कमी है वहां पर पानी का इन्तजाम किया जाएं। मेरे यह होडल में पानी की काफी कमी है। वहां पर कई ट्यूबवैलज का पानी खारा हो गया है। भाहरों में भी ड्रैनेज की व्यवस्था ठीक नई ह। वहां पर पानी के निकास की कोई व्यवस्था नही है। वहां का पानी या तो उजीना ड्रेन में डाला जाए या किसी दूसरी जगह पर डाला जाए। पानी का निकास न होने कारण वहां पर नालियों पानी भरी रहती है। पानी के निकलने का कोई साधन नही है। इसलिए वहां पर गन्दगी बनी रहती है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मै सड़को के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे हल्के की चार पांच सड़के ऐसी है जो तीन साल पहले सैक ान हुई थी लेकिन फण्डज रिलीज न होने के कारण किसी भी सड़क पर काम नही हुआ। ये सड़के कांग्रेस की हुकूमत में भी मन्जूर हुई थी लेकिन बाद मैं इनको कैन्सिल कर दिया गया। जब हमारी सरकार आई तो उनको फिर मन्जूर किया गया। लेकिन अभी तक काम किसी पर भी नही हुआ। ये सड़के है जटौली से अतरचढा, घासेड़ा से मीरापुर कौराली, घासेड़ा से

नखरौला और गुलाबड़ से करीमपुर। एक सड़क और है उसका नाम है भिडूकी से बासवां। जब चौधरी देवी लाल जो भरतपुर गए थे तो उन्होंने इन दोनो गांवों का दौरा किया था। इन दोनों गांवों की आबादी पन्द्रह हजार से अधिक है। इन दोनो गांवों के लौगों ने इस सड़क के लिए मांग भी की थी और चौधरी देवी लाल ने वहां पर एस0 ई0 को कहा था कि इन दोनों गांवों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह सड़क भीघ्राति ीघ्र बना दी जाए। एस0 ई0 ने इस सड़क का अस्टीमेट बनाकर भी भेजा था लेकिन उस अस्टीमेंट को सैक्रिरिएट लेवल पर खारिज कर दिया गया। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि भिडूकी की बांसवां तक की सड़क के बारे में सरकार पुर्नीविचार करें और इसको भीघ्राति ीघ्र बनवाया जाए जिससे कि वहां के लोगों की दिक्कत दूर हो सके।

इसी तरह से परिवहन का मामला है उपाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में जितनी बसिज थी वे अब एक चौथाई रह गई है। यह ठीक है कि फरीदाबाद में वसिज कम है इसलिए मै चाहता हूं कि वहां पर बसिज की पर्याप्त व्यवस्था की जाएं। मण्डल कमी ान के तहत पलवल में काफी झगड़ा हुआ लेकिन उसका असर मेरे हल्के पर ज्यादा पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, जब मण्डल कमी ान की बात आई है तो मै थोड़ा सा उसके बारे में कहना चाहता हूं। बहुत बार कहा जाता है कि ग्रीन ब्रिगेड के लोगों ने बहुत ज्यादती की थी लेकिन मै आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मण्डल कमी ान

के सिलसिलें में जो झगड़े हुए चाहे वे झगड़े रोहतक में हुए, चाहे सोनीपत में हुए, चाहे अम्बाला में हुए, चाहे वे यमुनानगर में हुए और चाहे वे जगधरी में हुए, ये सारे के सारे बी0 जे0 पी0 वालो ने, मण्डल कमण्डल वालों ने कराए थे। जहां बी0 जे0 पी0 के लोग थे वहां पर झगड़े कराए गए। जहां तक बी0 जे0 पी0 के लोगौं के संबंध है ये तो अपने आपको भारतीय संविधान से भी ऊपर मानते है। (ाोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ये अपने आपको न्यायपालिका से भी ऊपर मानते है। उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग तो अपने आपको सविधान से भी ऊपर मानते हैं।

श्री राम बिलास भार्मा: उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी भान जी को तो स्वप्न में भी हम नजर आते है। गृह मंत्री महोदय जी ने सवालों का जवाब देते हुए इस सदन में बताया था कि लोगों के ऊपर मुकदमें चल रहे है, मुकदमें दर्ज है लेकिन लोग पहचानने में नही आ सके लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उदय भान जी बी0 जे0 पी0 के ऊपर इस तरह के गल्त ऐलीगे ान लगा रहे है तो हम किस बात को सच माने। इनको कम से कम गृह मंत्री जी की बात को तो रखना चाहिए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उदय भान: उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग तो यू ही नाराज हो गये है। मेरे कहने में झुठ क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, मै इससे आगे कहना चाह रहा था कि सरकार की यह पालिसी है कि वह किसी भी प्राईवेट कोलोनाइजर को लाईसैंस नही देगी। अगर सरकार की यह पालिसी है तो मुझे बडे दु:ख के साथ कहना पड़

रहा है कि अनगपुर गांव के आर0 कान्त नाम के आदमी को 400 एकड़ भूमि किस प्रकार दे दी गई? इस भूमि को 1984 में चौधरी भजन लाल ने एक फिल्म इंडस्ट्रीज को दे दिया था और उस जमीन पर एस0 पी0 व डी0 सी0 के द्वारा जवरदस्ती टैम्पोररी कब्जा करवा लिया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इसी कोलोनाइजर को किस कानून के तहत लाईसैस दे दिया गया। मै इसका स्पश्टीकरण सरकार से चाहता हूं।

प्रो0 सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इनसे पूछा जाए कि ये कौन सी सरकार के वक्त की बात कर रहे है।

श्री उदय भानः उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता जी के वक्त की बात है। उन्होंने इस्तीफा देने से केवल एक दिन पहले आर0 कान्त नाम के व्यक्ति को 400 एकड़ भूमि डेढ़ करोड़ रूपया लैकर दे दी (ाोर एवं व्यवधान) ऐसा कैसे हुआ सरकार इसको स्पश्ट करे। (ाोर)

श्री सूरज भानः उपाध्यक्ष महोदय, किसी पर इस तरह से ऐलीगे ान लगाने से पहले क्या इन्होने इस बारे में लिखा कर दिया है क्योंकि रूल्ज के अनुसार किसी के खिलाफ बोलने से पहले इस को एडवान्स कापी देनी पड़ती है। मै इसका स्पश्टीकरण चाहता हूं कि वे किस रूल के तहत, जो सदस्य हाउस में हाजिर नही है, के खिलाफ कह रहे है? (ाोर एवं व्यवधान) इनकी तो ऐसा कहने की आदत सी ही हो गयी है।

श्री उदय भानः तो उपाध्यक्ष महोदय, मै कह रहा था कि किस तरह से इस आदमी को कोलोनाइजर का लाईसैन्स दे दिया गया? मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि इस हाउस की एक कमेटी बनायी जाए जो कि इस सारे मामले की छानबीन करें। साथ में इस बात का भी पता लगाया जाए कि अब तक कितने प्राईवेट कोलोनाइजर्ज का भी लाईसैन्स दिये गये है।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मै ि ाक्षा के बारे में भी कुछेक बातें इस सदन रखना चाहूंगा। आज प्रदे ा के अन्दर ि ाक्षा को वि ोश महत्व दिया जाना चाहिए। हरियाणा के अन्दर ि ाक्षा का हर स्तर पर विकास हुआ है। हमारी बजट स्पीच में भी दिया गया है कि सातवीं पंचवर्शीय योजना में लड़कीयों के लिए 500 प्राथमिक स्कूल खोले गये और 507 प्राथमिक और 329 माध्यमिक स्कूलों का दर्जा बढाया गया है, यह सरकार का ि ाक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का बड़ा ही सराहनीय कदम है। इसके लिए हम सरकार को बधाई देते है।

श्री उपाध्यक्षः उदय भान जी अब आप बैठे। आप कंटिन्यू करेंगे। अब हाउस कल सुबह 9.30 बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

18.30 बजे

(तत्प चात् सदन मंगलवार दिनांक 12 मार्च 1991 प्रात 9.30 बजे तक स्थगित हुआ।)

ANNEXURE

CONSTRUCTION OF CHAUPALS

267 Shri Jai Narain Khundia: Will the Minister for State for Welfare of Sch. Castes & Back Ward Classes be pleases to State the district wise number fo Chaupals if any, constructed for the persons belonging to Sch. Castes & Back Word Casses during the period form 1987 to 1990 in the State together with the number of Chaupals lying icompleted so far?

Minister of State for	(Sh Joginder Singh):
Welfare of Schedued Castes & Backward Classes.	

The Districtwise number of Chaupals constructed of Sch. Castes & Back Ward Classes during the period from 1987 to 1990 is given in the enclosed list.

Sr.	Name of the District	Chaupals for Schedule Castes during 1987-90		Chaupals for Backward Schedule Castes during 1987-90	
		No. of Chaupals constructed	No. of Chaupals lying incompleted	No. of Chaupals constructed	No. of Chaupals lying incompleted
1	2	3	4	5	6
1.	Ambala	32	6	23	2
2.	Bhiwani	79	-	58	-

3.	Faridabd	15	10	13	7
4.	Gurgaon	54	50	21	25
5.	Hissar	1	44	-	42
6.	Jind	45	48	14	18
7.	Karnal	73	-	28	-
8.	Kurukshetra	65	33	25	2
9.	Narnaul	18	5	18	2
10.	Rohtak	47	9	46	3
11.	Sonepat	59	8	16	6
12.	Sirsa	37	23	38	19
13.	Rewari	8	5	2	3
14.	Panipat	70	13	35	-
15.	Kaithal	9	58	8	5
16.	Yamun Nagar	19	28	2	1
	Total	631	340	347	135